ECONOMY - 24th March 2024

1.c

स्पष्टीकरण:

ऑफ-बजट वित्तपोषण (Off-budget financing):

- ऑफ-बजट वित्तपोषण एक वित्तीय व्यवस्था को संदर्भित करता है जहां कुछ सरकारी व्यय या राजस्व आधिकारिक बजट या लेखा प्रणाली से बाहर रखे जाते हैं।
- ये लेन-देन **सीधे सरकार के प्राथमिक बजट में दर्ज नहीं किए जा सकते हैं**, जिससे समग्र वित्तीय तस्वीर में पारदर्शिता की संभावित कमी हो सकती है।
- ऑफ-बजट वित्तपोषण में विभिन्न रणनीतियाँ शामिल हो सकती हैं जैसे सार्वजनिक उद्यम, विशेष निधि, या बाहरी उधार जो नियमित बजट गणना में शामिल नहीं है।
- हालांकि इस तरह की प्रथाएं विशिष्ट नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन वे सरकारी खर्च और राजस्व की वास्तविक सीमा को भी अस्पष्ट कर सकती हैं, जिससे राजकोषीय रिपोर्टिंग में जवाबदेही और सटीकता के बारे में चिंताएं पैदा हो सकती हैं।
- आमतौर पर, जब केंद्र सरकार किसी योजना या परियोजना को क्रियान्वित करने का इरादा रखती है, तो वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से धन उधार लेने का अनुरोध करती है।
- हालाँकि, **इस उधार को केंद्र सरकार के लिए एक दायित्व माना जाता है,** तथा **मूलधन और ब्याज भुगतान दोनों केंद्र सरकार द्वारा कवर किए जाते हैं। (अत: कथन 1 और 2 सही हैं)**
- इसके बावजूद, इस तरह की उधारी को केंद्र सरकार के उधारी आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता है और इसे राजकोषीय घाटे की गणना से बाहर रखा जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए कोई ऑफ-बजट उधार लेने का अनुमान नहीं लगाया गया था। **(अत: कथन 3 सही है)**

2.c

स्पष्टीकरण:

- वैधानिक तरलता अनुपात (SLR): वैधानिक तरलता अनुपात कुल जमा के उस हिस्से से संबंधित है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आसानी से उपलब्ध रूप में बनाए रखना अनिवार्य है। इस धन का उपयोग अक्सर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियाँ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नतीजतन, वैधानिक तरलता अनुपात बैंकिंग प्रणाली के भीतर अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने और सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है। यह बैंक ऋण में हेरफेर के माध्यम से घरेलू बाजार में तरलता के प्रबंधन का एक उपकरण है। **(अत: कथन 2 सही है)**
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF): सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर उस दर को निर्दिष्ट करती है जिस पर अनुसूचित बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करके रातोंरात भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से अस्थायी

रूप से धन उधार ले सकते हैं। एमएसएफ एक संक्षिप्त उधार तंत्र है जो मुख्य रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए है, जो गंभीर नकदी की कमी या तीव्र तरलता घाटे के समय नियोजित होते हैं। **(अत: कथन 1 सही है)**

- एमएसएफ बैंकों के लिए अंतिम उपाय के रूप में कार्य करता है, जब वे रेपो दर जैसी कम ब्याज दरों वाली सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर तरलता समायोजन सुविधा सहित उधार लेने के अन्य सभी रास्ते समाप्त कर चुके होते हैं।
- एमएसएफ दर बैंकों के लिए दंडात्मक दर के रूप में स्थापित की गई है और यह हमेशा रेपो दर से अधिक होती है। यह बैंकों के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, जो वैधानिक तरलता अनुपात द्वारा परिभाषित सीमा के भीतर सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने सहित अन्य सभी विकल्पों का पता लगाने के बाद ही पहुंच योग्य होता है। आरबीआई द्वारा एमएसएफ की शुरूआत का उद्देश्य अंतर-बैंक बाजार में रातोंरात उधार दरों में उतार-चढ़ाव को कम करना और पूरे वित्तीय प्रणाली में मौद्रिक नीति के सुचारू प्रसारण की सुविधा प्रदान करना है। **(अत: कथन 3 सही है)**

3.c

स्पष्टीकरण:

- प्रतिष्ठित सरकारी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अमूल्य डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, कृषि मंत्री ने **11 अगस्त, 2020 को 'कृषि मेघ' नामक एक डेटा रिकवरी केंद्र का** उद्घाटन किया । यह केंद्र, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा प्रणाली- क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज का हिस्सा है, जिसे हैदराबाद में स्थापित किया गया है। आईसीएआर का प्राथमिक डेटा सेंटर वर्तमान में दिल्ली में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (IASRI) में स्थित है, जो भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, जिससे डेटा हानि का खतरा है। इसलिए, हमारी महत्वपूर्ण कृषि संबंधी जानकारी को संरक्षित करने के लिए एक सुरक्षित स्थान पर डेटा रिकवरी सेंटर की स्थापना महत्वपूर्ण है।
- डेटा रिकवरी सेंटर, जिसे कृषि मेघ के नाम से जाना जाता है, हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (NAARM) में स्थित है। कृषि मेघ का लक्ष्य नई दिल्ली में ICAR-IASRI में ICAR-डेटा सेंटर को हैदराबाद में ICAR-NAARM में आपदा रिकवरी सेंटर के साथ एकीकृत करना है। यह पहल भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एनएएचईपी) के तहत शुरू की गई है। **(अत: दोनों कथन सही हैं)**
- नई दिल्ली में ICAR-IASRI के डेटा सेंटर की तुलना में कृषि मेघ के लिए स्थान के रूप में एनएएआरएम, हैदराबाद का चयन इसके विशिष्ट भूकंपीय क्षेत्र के कारण रणनीतिक है। इसके अलावा, हैदराबाद कुशल आईटी पेशेवरों और अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के साथ एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है, जिसमें निम्न आर्द्रता स्तर भी शामिल है जिसे डेटा सेंटर वातावरण के भीतर नियंत्रित किया जा सकता है।

4.d

स्पष्टीकरण:

समेकित सिंकिंग फंड (CSF)

- राज्य सरकारें, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ साझेदारी में, समेकित सिंकिंग फंड (सीएसएफ) रखती हैं।

- सीएसएफ का प्राथमिक उद्देश्य एक सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करना है जो उनके वित्तीय दायित्वों के व्यवस्थित निपटान में सहायता करता है।
- राज्य सरकारों के पास विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) का उपयोग करने का विकल्प होता है, जो रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यह सुविधा सीएसएफ के भीतर रखी संपत्तियों द्वारा समर्थित है।
- इस सुविधा से जुड़ी ब्याज दर को रेपो दर से नीचे के स्तर पर बनाए रखा जाता है, जो इसकी लागत-प्रभावशीलता में योगदान देता है। **(अतः सभी कथन सही हैं)**

5.c

स्पष्टीकरण:

- मुद्रास्फीति का तात्पर्य एक निश्चित अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि से है। इसके परिणामस्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए समान रूप से उच्च लागत बढ़ जाती है।
- मुद्रास्फीति बढ़ती मांग, आपूर्ति की कमी, बढ़ती उत्पादन लागत या मुद्रा मूल्य में बदलाव जैसे कारकों के कारण हो सकती है। इसे आम तौर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) या उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) जैसे सूचकांकों का उपयोग करके मापा जाता है।
- उदाहरण के लिए, ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां किसी उत्पाद की लागत 70 रुपये से बढ़कर 80 रुपये हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप 10 रुपये की वृद्धि होती है। 1000 रुपये की मामूली आय वाले व्यक्ति के लिए, यह 1% कर का बोझ है। इसके विपरीत, 1,00,000 रुपये कमाने वाले उच्च आय वाले व्यक्ति के लिए, समान वृद्धि मात्र 0.01% कर के बराबर है। नतीजतन, जहां सीमित साधनों वाला व्यक्ति मूल्य वृद्धि के कारण अपनी आय का 1% खर्च कर रहा है, वहीं एक अमीर व्यक्ति अपनी कमाई का केवल 0.01% ही आवंटित कर रहा है। **यह एक प्रतिगामी प्रणाली का प्रतीक है**, क्योंकि उच्च आय वाले व्यक्तियों के लिए कर प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम है और कम आय वाले लोगों के लिए अनुपातहीन रूप से अधिक है। **(इसलिए विकल्प सी) सही है)**

6.b

स्पष्टीकरण:

- अवसर लागत (Opportunity cost) से तात्पर्य **अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य जो कोई विकल्प चुनने पर छोड़ दिया जाता है।** दूसरे शब्दों में, यह वह संभावित लाभ या मूल्य है जिसे आप तब छोड़ देते हैं जब आप एक विकल्प को दूसरे के स्थान पर चुनते हैं। इस अवधारणा का उपयोग अक्सर अर्थशास्त्र में निर्णय लेने में शामिल ट्रेड-ऑफ का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है और इसलिए यह अवधारणा किसी व्यवसाय की पूंजी संरचना को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। **(इसलिए विकल्प बी) सही है)**
- **यहां अवसर लागत का एक उदाहरण दिया गया है:** कल्पना कीजिए कि आपके पास खाली शाम का समय है और आपको आगामी परीक्षा के लिए अध्ययन करने या अपने दोस्तों के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने के बीच निर्णय लेना है। यदि आप अध्ययन करना चुनते हैं, तो अवसर की कीमत वह आनंद और सामाजिक मेलजोल होगी जो आप कार्यक्रम में नहीं देख पाते। दूसरी ओर, यदि आप कार्यक्रम में जाते हैं, तो अवसर लागत वह समय होगी जो आप

अध्ययन करने और संभावित रूप से परीक्षा में बेहतर ग्रेड प्राप्त करने में बिता सकते थे। दोनों ही मामलों में, आप एक विकल्प को दूसरे के बजाय चुनने के लिए कुछ मूल्यवान (या तो सामाजिककरण या अध्ययन) छोड़ रहे हैं।

7.c

स्पष्टीकरण:

विवैश्वीकरण (Deglobalisation)

- विवैश्वीकरण वह अवधारणा है जहां देश टैरिफ या व्यापार सीमाएं लगाने जैसी संरक्षणवादी रणनीति लागू करके वैश्विक आर्थिक एकीकरण को कम करने के लिए काम करते हैं। ऐसा उनके अपने उद्योगों को प्राथमिकता देने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भरता कम करने के लिए किया जाता है। ऐसे बदलाव अक्सर आर्थिक राष्ट्रवाद, राजनीतिक बदलाव या जनमत में बदलाव से प्रभावित होते हैं।
- यह आर्थिक वैश्वीकरण है जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है, न कि आर्थिक विवैश्वीकरण। वैश्वीकरण न कि विवैश्वीकरण, जो जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणामों को कम करने में मदद करता है **क्योंकि इसमें सहयोग और समन्वय के माध्यम से विश्व स्तर पर जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को फैलाने की क्षमता है। (इसलिए 1 गलत है)**
- यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से विवैश्वीकरण के खतरे स्पष्ट रूप से बढ़ गए हैं। युद्ध पहले से मौजूद प्रतिकूलताओं जैसे बढ़ती मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आदि को भी बढ़ाता है। इसलिए युद्ध विवैश्वीकरण की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। **(अत: 2 सही है)**
- विवैश्वीकरण का एक अनूठा उदाहरण है जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि यूरोपीय संघ के साथ व्यापार संबंध कमजोर हो गए हैं। ब्रेक्जिट वैश्वीकरण की विफलता को दर्शाता है । **(इसलिए 3 सही है)**
- कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी आर्थिक एकीकरण के मामले में झटका लगा, जिससे विश्व व्यापार में गिरावट आई। इस संकट ने आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण की सीमा के बारे में वैश्विक आशंकाओं को बढ़ा दिया है। चिकित्सा आपूर्ति, सुरक्षात्मक गियर और दवाओं के अपर्याप्त घरेलू उत्पादन के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए, देशों ने निर्यात प्रतिबंध लागू किए। इस अवधि में राष्ट्रों में संरक्षणवाद और वैक्सीन राष्ट्रवाद के उदाहरण भी देखे गए। **(अत: 4 सही है)**
- UNCTAD के निवेश रुझान मॉनिटर के अनुसार, वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह ने 2021 में एक मजबूत बदलाव दिखाया, जो 2020 में 929 बिलियन डॉलर से 77% बढ़कर अनुमानित $1.65 ट्रिलियन हो गया, जो कि उनके पूर्व-कोविड -19 स्तर को पार कर गया। **(इसलिए 5 गलत है)**

8.b

स्पष्टीकरण:

- **निवेश में बारबेल रणनीति (Barbell strategy) का उद्देश्य** मध्यम-जोखिम वाले विकल्पों से बचते हुए, उच्च-जोखिम और कम-जोखिम दोनों परिसंपत्तियों में निवेश करके जोखिम-पुरस्कार संतुलन बनाना है। यह दृष्टिकोण आमतौर

पर निश्चित आय वाले निवेशों में लागू किया जाता है और इसे इक्विटी बाजारों तक भी बढ़ाया जा सकता है। प्राथमिक उद्देश्य उच्च जोखिम, उच्च प्रतिफल वाली संपत्तियों में उपस्थिति बनाए रखते हुए निवेशक के समग्र जोखिम जोखिम को कम करना है। **(इसलिए विकल्प बी) सही है)**

- आर्थिक सर्वेक्षण ने प्रदर्शित किया कि भारत पर कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए बारबेल रणनीति का उपयोग कैसे किया गया। इसमें कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा उपायों और वास्तविक समय की जानकारी के आधार पर अनुकूली नीति समायोजन का संयोजन शामिल था। देश में कोविड के व्यापक प्रसार का सामना करने पर भारत ने अपनी पारंपरिक वाटरफॉल पद्धति (Waterfall method) के बजाय बारबेल नीति दृष्टिकोण को चुना।

9.d

स्पष्टीकरण:

- **सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)** किसी देश के आर्थिक उत्पादन के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को घटाकर उत्पादन में उपयोग किए गए इनपुट के मूल्य को शामिल किया जाता है। जीडीपी की गणना व्यक्तिगत उपभोग व्यय, सकल निजी घरेलू निवेश, वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध निर्यात और सरकारी उपभोग व्यय और सकल निवेश के योग के रूप में भी की जा सकती है।
- कथन 1 सटीक रूप से इंगित करता है कि जीडीपी आय वितरण को प्रकट करने में विफल रहता है, जो व्यक्तियों की भलाई को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। जबकि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में 5% की वृद्धि समग्र वृद्धि का संकेत दे सकती है, यह असमानताओं को छुपा सकती है जहां कुछ समूह अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव करते हैं जबकि अन्य स्थिरता या गिरावट का अनुभव करते हैं।
- कथन 2 इस बात पर सही ढंग से प्रकाश डालता है कि जीडीपी तकनीकी प्रगति पर विचार नहीं करती है जो कल्याण को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, इंटरनेट ने लोगों को सीधे यात्रा बुक करने में सक्षम बना दिया है, जो एक गैर-जीडीपी गणना वाली गतिविधि है जो जीडीपी वृद्धि को बेहतर कल्याण का अपर्याप्त माप बनाती है।
- कथन 3 जीडीपी की एक और खामी की सटीक पहचान करता है - इसमें घरेलू कल्याण में योगदान देने वाली गैर-बाजार गतिविधियों को शामिल नहीं किया गया है। चूंकि जीडीपी मूल्यांकन के लिए बाजार कीमतों पर निर्भर करती है, इसलिए यह औपचारिक बाजारों के बाहर की गतिविधियों के मूल्य को छोड़ देती है।
- कथन 4 सही ढंग से बताता है कि जीडीपी में बाहरी चीजें शामिल नहीं हैं, जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को होने वाले गणना नही किए गए लाभ या नुकसान हैं। इन बाह्यताओं के पास मूल्यांकन के लिए बाजार का अभाव है और ये जीडीपी गणना का हिस्सा नहीं हैं। उदाहरण के लिए, किसी तेल रिफाइनरी के पास की नदी पर प्रदूषण के प्रभाव को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा।

10.c

स्पष्टीकरण:

- **घर्षणात्मक बेरोजगारी** (**Frictional unemployment**) तब उभरती है जब व्यक्ति नौकरी, करियर, स्थान बदलते हैं, या श्रम बल में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं। यह अधूरी जानकारी के कारण श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच

असंतुलन के परिणामस्वरूप हो सकता है। आमतौर पर, व्यक्ति अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ देते हैं और **बाद में अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप नए पदों की तलाश करते हैं।** इस संक्रमण अवधि में नौकरी के लिए आवेदन और नियोक्ता चयन के लिए समय शामिल होता है, जिससे बेरोजगारी की अस्थायी स्थिति पैदा हो जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी को घर्षणात्मक या संक्रमणकालीन कहा जाता है, और यह अर्थव्यवस्था के भीतर लगातार मौजूद रहती है। **(इसलिए विकल्प सी) सही है)।**

- संरचनात्मक बेरोजगारी विभिन्न कारकों से उत्पन्न होती है, जैसे श्रमिकों के पास आवश्यक कार्य कौशल नहीं होना, सरकारी नीति में बदलाव, तकनीकी परिवर्तन, या भौगोलिक सीमाएँ जो नौकरी स्थानांतरण को रोकती हैं। इसके अतिरिक्त, अपर्याप्त वेतन स्तर के कारण व्यक्ति काम करने में अनिच्छुक हो सकते हैं। यह स्थिति नियोक्ताओं द्वारा आवश्यक कौशल और श्रमिकों के पास मौजूद कौशल के बीच एक महत्वपूर्ण असमानता पैदा करती है। संरचनात्मक बेरोजगारी तब स्पष्ट हो जाती है जब रोजगार के अवसर मौजूद होते हैं और व्यक्ति काम करने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन उपलब्ध कार्यबल में रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक योग्यता का अभाव होता है।
- चक्रीय बेरोजगारी से तात्पर्य उस प्रकार की बेरोजगारी से है जो आर्थिक मंदी या मंदी के कारण उत्पन्न होती है। इन अवधियों के दौरान, वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग में गिरावट आती है, जिससे उत्पादन कम हो जाता है और व्यवसायों द्वारा छंटनी होती है। परिणामस्वरूप, कमजोर आर्थिक गतिविधियों के कारण लोग बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगारी का यह रूप सीधे व्यापार चक्र से जुड़ा हुआ है और आर्थिक संकुचन के दौरान बढ़ता है और आर्थिक विस्तार की अवधि के दौरान गिरता है।

11.**c**

स्पष्टीकरण:

- विश्व बैंक ने यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स के सहयोग से **'लर्निंग पॉवर्टी' की अवधारणा पेश की है।** यह शब्द 10 वर्ष की आयु तक बुनियादी पाठ को पढ़ने और समझने में असमर्थता को दर्शाता है। **(इसलिए विकल्प सी) सही है)**
- विश्व बैंक 10 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का कौशल प्राप्त करने के महत्व पर जोर देता है। जब एक बच्चा अपनी शैक्षिक यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ता है तो पढ़ना आगे सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करता है। इसके विपरीत, प्रभावी ढंग से पढ़ने में असमर्थता इस मार्ग को बंद कर देती है। इसके अलावा, जब बच्चे पढ़ने में संघर्ष करते हैं, तो यह अक्सर इंगित करता है कि गणित, विज्ञान और मानविकी जैसे विषयों में सीखने की सुविधा के लिए शैक्षिक प्रणालियाँ अपर्याप्त रूप से संरचित हैं। हालांकि जीवन में बाद में महत्वपूर्ण प्रयास के साथ सीखना अभी भी संभव है, जो बच्चे 10 साल की उम्र तक या प्राथमिक विद्यालय के पूरा होने तक पढ़ने में असमर्थ होते हैं, उन्हें आम तौर पर पढ़ने के कौशल में महारत हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे अपनी शैक्षिक गतिविधियों में आगे बढ़ते हैं।

12.**d**

स्पष्टीकरण:

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में शामिल होने पर, एक राष्ट्र को एक कोटा आवंटित किया जाता है, जो देश की जीडीपी (50%), खुलेपन की डिग्री (30%), आर्थिक परिवर्तनशीलता (15%) और अंतर्राष्ट्रीय भंडार (5%) सहित कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कोटा विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) में व्यक्त किए जाते हैं, जो आईएमएफ के खाते की मानक इकाई है। उदाहरण के लिए, भारत का कोटा 2.76% है, चीन का 6.41% है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का कोटा 17.46% है।
- किसी सदस्य की कोटा सदस्यता उस अधिकतम वित्तीय प्रतिबद्धता को निर्दिष्ट करती है जो सदस्य को आईएमएफ तक बढ़ानी होगी। आईएमएफ में शामिल होने पर, सदस्यता का पूरा भुगतान करना होगा, जिसमें 25% तक एसडीआर या व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त मुद्राओं (जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन, पाउंड या युआन) में और शेष 75% सदस्य की घरेलू मुद्रा में होगा। इन कोटा की हर पांच साल में समीक्षा करने का लक्ष्य है।
- इसके अलावा, किसी सदस्य का कोटा यह निर्धारित करता है कि उन्हें आईएमएफ से कितनी वित्तीय सहायता मिल सकती है। उदाहरण के लिए, एक सदस्य असाधारण परिस्थितियों में संभावित अपवादों के साथ, सालाना अपने कोटा का 145% और संचयी रूप से 435% तक उधार लेने के लिए पात्र है। विशेष रूप से, आईएमएफ विशेष रूप से सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है।
- कोटा कई प्रमुख पहलुओं को निर्धारित करने का काम करता है:
    - सदस्यता, एक सदस्य द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय प्रतिबद्धता को दर्शाती है। **(इसलिए 1 सही है)**
    - मतदान की शक्ति और आईएमएफ निर्णय लेने में भागीदारी। **(अत: 2 सही है)**
    - एसडीआर का एक देश का आवंटन हिस्सा। **(इसलिए 3 सही है)**
    - आईएमएफ से संभावित वित्तीय सहायता के लिए उधार लेने की क्षमता। **(अत: 4 सही है)**
- अगस्त 2021 में, आईएमएफ ने 456.5 बिलियन एसडीआर का अपना सबसे महत्वपूर्ण आवंटन निष्पादित किया, जिसके परिणामस्वरूप कुल एसडीआर आवंटन लगभग 650 बिलियन हो गया। आवंटित एसडीआर में से, भारत को 12.57 बिलियन एसडीआर प्राप्त हुए, जो कुल आवंटन के 2.75% के बराबर है। भारत की कुल एसडीआर होल्डिंग्स 1.09 बिलियन एसडीआर से बढ़कर 13.66 बिलियन एसडीआर हो गई, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाती है।

13.**a**

स्पष्टीकरण:

- केंद्र सरकार महात्मा गांधी नरेगा की धारा 6(1) के अनुसार, **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि मजदूरों (सीपीआई-एएल) पर भरोसा करते हुए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) श्रमिकों के लिए सालाना मजदूरी दरों को समायोजित करती है।** ये संशोधित दरें प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होती हैं। **(इसलिए विकल्प ए) सही है)**
- वेतन संशोधन के लिए उपयुक्त सूचकांक निर्धारित करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक पूर्व अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण पर स्विच करने और दिसंबर महीने के सूचकांक के बजाय वार्षिक औसत का उपयोग करने का सुझाव दिया। फिलहाल वित्त मंत्रालय के सहयोग से सिफारिशों की समीक्षा की जा रही है।

- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम मजदूरी में भिन्नता के कारण विभिन्न राज्यों में मनरेगा मजदूरी अलग-अलग हो सकती है।

14.**b**

स्पष्टीकरण:

- कर उछाल (Tax buoyancy) एक आर्थिक शब्द है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व की प्रतिक्रिया को संदर्भित करता है। यह इंगित करता है कि आर्थिक गतिविधि में परिवर्तन के संबंध में कर राजस्व कितनी प्रभावी ढंग से बढ़ता या घटता है। **(अत: कथन 1 सही है)**
- जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो उच्च आय, उपभोग और आर्थिक लेनदेन के कारण कर राजस्व में वृद्धि होती है।
- कर उछाल सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के संबंध में **कर राजस्व की लोच को मापता है। यदि कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से अधिक बढ़ता है, तो इसे सकारात्मक कर उछाल माना जाता है, जो दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ कर प्रणाली अधिक राजस्व उत्पन्न कर रही है।** दूसरी ओर, यदि कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से कम बढ़ता है, तो इसे नकारात्मक कर उछाल कहा जाता है, जो आर्थिक विकास के दौरान कमजोर राजस्व प्रदर्शन का संकेत देता है। **(अत: कथन 2 सही है)**
- कर उछाल सरकारों के लिए उनकी कर नीतियों और राजस्व संग्रह तंत्र की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह नीति निर्माताओं को यह समझने में मदद कर सकता है कि कर प्रणाली किस हद तक आर्थिक परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करती है और क्या स्थिर राजस्व सृजन सुनिश्चित करने के लिए समायोजन की आवश्यकता है।
- कर उछाल की गणना कर राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन को नॉमिनल /**नाममात्र जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करके की जाती है। (इसलिए कथन 3 गलत है)**
- उदाहरण के लिए, यदि नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद में 12% की वृद्धि का अनुभव होता है और किसी विशिष्ट वर्ष के लिए कर राजस्व वृद्धि 15% है, तो कर उछाल 15% / 12% = 1.25 होगा। यह मान सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक प्रतिशत परिवर्तन के संबंध में कर राजस्व में वृद्धि को दर्शाता है। एक से अधिक कर उछाल अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक परिदृश्य का प्रतीक है।

15.**b**

स्पष्टीकरण:

- रोजगार लोच (विकास की) आर्थिक वृद्धि में 1 प्रतिशत परिवर्तन के साथ जुड़े रोजगार में प्रतिशत परिवर्तन का एक माप है। रोजगार लोच = रोजगार में % परिवर्तन/आर्थिक विकास में % परिवर्तन **(इसलिए कथन 1 गलत है)।**
- 0.01 की रोजगार लोच यह दर्शाती है कि सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि के लिए, रोजगार में मात्र 0.01 प्रतिशत की वृद्धि देखी जाती है। रोजगार लोच में लगातार गिरावट आ रही है, जो 1990 के दशक के दौरान 0.4 से गिरकर 2014 में 0.2 हो गई है, और अब 0.1 पर है।

- जब अर्थव्यवस्था में ताजा निवेश होता है, तो यह आर्थिक विकास को गति देता है, साथ ही रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देता है। हालाँकि, यदि आर्थिक विकास (फ़ैक्टरी) क्षमता उपयोग में वृद्धि से प्रेरित है, यह मानते हुए कि उपयोग नए निवेशों के बजाय पहले **कुछ कारणों से कम** था, तो रोजगार सृजन प्रभाव सीमित हो सकता है। **(अत: कथन 2 सही है)**

16.**d**

स्पष्टीकरण:

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का सुझाव देते समय, CACP कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार करता है। यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि हालांकि उत्पादन की लागत एमएसपी के निर्धारण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, लेकिन यह एमएसपी निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार एकमात्र कारक नहीं है। विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी का सुझाव देते समय दिए गए सभी कारकों पर विचार किया जाएगा।
- सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करती है जो "अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत" से कम से कम 50% अधिक होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एमएसपी पूरे देश में एक समान रहता है। उत्पादन की लागत की गणना में तीन अलग-अलग दृष्टिकोण शामिल हैं:
    - A2: (वास्तविक भुगतान लागत का औसत): इस पद्धति में इनपुट खरीद, बिजली, उर्वरक आदि जैसे खर्च शामिल हैं। **भूमि/उपकरण के लिए पट्टा भुगतान और किराये के श्रमिकों की मजदूरी का भी हिसाब रखा जाता है**। हालाँकि, जब पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, तो इसे इस लागत में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह अपनी जेब से किया जाने वाला खर्च नहीं है।
    - A2 + FL (वास्तविक भुगतान लागत + पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल है): इस परिदृश्य में, **यदि किसान पारिवारिक श्रम पर निर्भर है**, तो गणना में उस लागत का निर्धारण शामिल है जो किसान को वहन करनी होगी यदि वही श्रम बाजार से किराए पर लिया गया था। यह मान फिर A2 में जोड़ा जाता है, जिसे पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य कहा जाता है।
    - C2 (अधिक व्यापक और इसमें A2 + FL के अलावा, स्वामित्व वाली भूमि और अचल पूंजी संपत्तियों पर किराया और आरोपित ब्याज शामिल है): इस पद्धति के तहत, यदि किसी किसान के पास जमीन है, तो किराये से जुड़ी लागतें जोड़ दी जाती हैं, भले ही कोई वास्तविक किराया न चुकाया गया हो। यदि भूमि किराए पर ली गई थी तो यह काल्पनिक लागत का हिसाब है।
- सरकार यह सुनिश्चित करती है कि एमएसपी "A2+FL" लागत से कम से कम 50% के स्तर पर निर्धारित हो।

(इसलिए उपरोक्त सभी कारकों पर विचार किया जाता है)

17.**c**

स्पष्टीकरण:

आरबीआई द्वारा शुरू किया गया एक **वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड, हाल ही में लॉन्च किया गया है।** यह डैशबोर्ड प्रासंगिक संकेतकों को कैप्चर करके वित्तीय समावेशन की प्रगति का मूल्यांकन और ट्रैक करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है।

इसके अलावा, यह प्लेटफ़ॉर्म देश भर के जटिल भौगोलिक क्षेत्रों में वित्तीय बहिष्करण की डिग्री को मापने की सुविधा प्रदान करता है, इस प्रकार ऐसे क्षेत्रों के लिए लक्षित समाधान सक्षम करता है। **(इसलिए विकल्प सी) सही है)**

18.**d**

स्पष्टीकरण:

अर्थोपाय अग्रिम (WMA):

- सरकार के बैंकर के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अनंतिम ऋण व्यवस्था प्रदान करता है। ये अनंतिम ऋण, जिन्हें अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) के रूप में जाना जाता है, सरकार के राजस्व और व्यय धाराओं में क्षणिक असंतुलन को दूर करने के लिए एक विधि प्रदान करते हैं। **अत: कथन 3 गलत है**
- WMA पहल को सरकार के वित्तीय प्रवाह और बहिर्प्रवाह में उत्पन्न होने वाले अस्थायी अंतराल को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब सरकार को तत्काल धन की आवश्यकता होती है, तो वह आरबीआई द्वारा प्रदान की गई इस सुविधा का उपयोग कर सकती है। WMA, RBI द्वारा 90 दिनों की अवधि के लिए एक ऋण योजना के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि सरकार को इस समय सीमा के भीतर बकाया राशि का भुगतान करना आवश्यक है।
- WMA पर लगाई जाने वाली ब्याज दर वर्तमान में रेपो दर के अनुरूप है। WMA के लिए पारस्परिक रूप से सहमत सीमाएँ RBI और भारत सरकार के बीच चर्चा द्वारा निर्धारित की जाती हैं। यह पहल सुनिश्चित करती है कि सरकार अपने वित्तीय संचालन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए जरूरत पड़ने पर अल्पकालिक धन तक तुरंत पहुंच बना सके।
- आइए इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करें:
- आगामी वित्तीय वर्ष, 2022-23 पर विचार करें, जहां केंद्र सरकार को 50 लाख करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान है। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार 50 लाख करोड़ रुपये के बांड जारी करने की योजना बना रही है। जो ट्रेजरी बिल या दिनांकित प्रतिभूतियों का रूप ले सकता है। हालाँकि, मान लेते हैं कि 20 जून, 2023 को, 50 लाख करोड़ रुपये की उधारी की व्यवस्था करने के बावजूद, सरकार को अगले 30 दिनों के लिए नकदी की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है।
- ऐसे में केंद्र सरकार के पास दो विकल्प हैं। यह या तो भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से ऋण प्राप्त कर सकता है, जिसे 'अर्थोपाय अग्रिम' कहा जाता है, या 30 दिनों की परिपक्वता अवधि के साथ 'नकद प्रबंधन बिल' के रूप में जाना जाने वाला एक अल्पकालिक बांड जारी कर सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि 30 दिन की अवधि के बाद, सरकार उधार ली गई राशि चुकाने के लिए बाध्य है।
- संक्षेप में, 'अर्थोपाय अग्रिम' और 'नकद प्रबंधन बिल' सरकार की नियोजित उधार आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, जिन्हें अक्सर राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसके बजाय, वे नकद प्राप्तियों और भुगतानों के बीच अस्थायी असंतुलन के समाधान के रूप में काम करते हैं, तथा संवितरण के लिए तत्काल नकदी की जरूरतों को पूरा करते हैं।
- 'अर्थोपाय अग्रिम' (डब्ल्यूएमए) और 'कैश मैनेजमेंट बिल्स' (सीएमबी) के बीच अंतर उनकी प्रकृति और व्यापार क्षमता में निहित है। **WMA RBI द्वारा प्रदान की जाने वाली एक ऋण सुविधा है और इसका व्यापार नहीं किया जा सकता है।** दूसरी ओर, सीएमबी बाजार में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए बांड हैं, और वे व्यापार योग्य प्रतिभूतियां हैं। जबकि सीएमबी विशेष रूप से केंद्र सरकार के लिए हैं, **डब्ल्यूएमए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए उपलब्ध हैं। (इसलिए कथन 1 और 2 गलत हैं)**
- केंद्र सरकार अर्थोपाय अग्रिम पर रेपो दर या संभावित रूप से इससे भी अधिक दर पर ब्याज का भुगतान करती है।

19.**a**

स्पष्टीकरण:

भुगतान बैंक (Payment banks)

- भुगतान बैंकों की स्थापना छोटे बचत खातों का विस्तार करके और प्रवासी मजदूरों, कम आय वाले परिवारों, छोटे व्यवसायों, असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं और अन्य उपयोगकर्ताओं को भुगतान और प्रेषण सेवाओं की सुविधा प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में की गई है।
- भुगतान बैंकों की गतिविधियों के दायरे में निम्नलिखित शामिल होंगे:
    - मांग जमा स्वीकार करना, चाहे वह बचत हो या चालू, विशेष रूप से 2 लाख रुपये की सीमा तक जो बिना सावधि जमा के होते हैं। **(इसलिए कथन 1 गलत है)**
    - उधार देने की गतिविधियों में शामिल होने से बचना।
    - क्रेडिट कार्ड को छोड़कर, एटीएम/डेबिट कार्ड जारी करने की सुविधा प्रदान करना।
    - विभिन्न चैनलों के माध्यम से भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रदान करना। **(अत: कथन 4 सही है)**
    - किसी अन्य बैंक के लिए बैंकिंग संवाददाता (बीसी) की भूमिका ग्रहण करना। **(अत: कथन 3 सही है)**
    - म्यूचुअल फंड या बीमा पेशकश जैसे सरल वित्तीय उत्पाद वितरित करना।
- भुगतान बैंकों को नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना अनिवार्य है। सभी सार्वजनिक जमाओं को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना या अन्य वाणिज्यिक बैंकों में रखना आवश्यक है, जिससे किसी भी उधार गतिविधियों पर रोक लग जाती है। यह सुरक्षा भुगतान बैंकों में जनता की जमा राशि की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। भुगतान बैंकों की स्थापना विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करती है, जो विभेदित बैंकों के दायरे में आते हैं। (ऐसे प्रतिबंधों के बिना काम करने वाले सार्वभौमिक बैंकों के विपरीत, विभेदित बैंक या तो भौगोलिक दायरे या परिचालन पहलुओं के संदर्भ में विवश हैं)। **(अत: कथन 2 सही है)**

20.**d**

स्पष्टीकरण:

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) बैंकों से उधार लेने और बाद में ऋण देने की प्रक्रिया में संलग्न होती हैं, जबकि धन उत्पन्न करने के लिए वित्तीय बाजारों के भीतर बांड जारी करने का विकल्प भी चुनती हैं। ये जुटाई गई धनराशि फिर ऊंची ब्याज दर पर उधार दी जाती है। इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी ऋण वित्तपोषण के माध्यम से विदेशों से वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बनाते हैं, जिसे बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के रूप में जाना जाता है। मुद्रा बाजार में वाणिज्यिक पत्र (सीपी) जारी करने से अल्पकालिक वित्तीय ज़रूरतें पूरी होती हैं।
- म्यूचुअल फंड के संदर्भ में, एनबीएफसी निवेश को आकर्षित करते हैं क्योंकि वे म्यूचुअल फंड को ऋण उपकरण जारी करते हैं, जो बदले में उधार दिए जाते हैं। एनबीएफसी के लिए थोक वित्त पोषण के प्रमुख स्रोतों में मुख्य रूप से शामिल हैं:

- बैंक, मुख्य रूप से सावधि ऋणों के माध्यम से, बाकी गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्र द्वारा वित्त पोषित होते हैं।
- ऋण म्यूचुअल फंड, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्र द्वारा प्राप्त होते हैं।

(अत: सभी कथन सही हैं)

21.**c**

स्पष्टीकरण:

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) किसानों को हर तीन साल में एक बार जारी किया जाने वाला एक रिपोर्ट कार्ड है, जो 12 मापदंडों के आधार पर उनकी मृदा की स्थिति बताता है। साथ ही, इसमें उपयोग के लिए उर्वरक और अन्य प्रभावी ढंग से मृदा सुधार संबंधी सिफारिशें भी शामिल हैं।
- देश में नाइट्रोजन-फॉस्फोरस-पोटेशियम (एनपीके) का वर्तमान उपभोग पैटर्न 4:2:1 के असंतुलित अनुपात की ओर झुका हुआ है। एसएचसी व्यापक क्षेत्र-विशिष्ट मिट्टी की उर्वरता रिपोर्ट पेश करने का काम करता है, जिससे उर्वरकों के उचित वितरण की सुविधा मिलती है।

- एक एकीकृत पोषक तत्व प्रणाली को बढ़ावा देने से रासायनिक उर्वरक के उपयोग में 20% की कमी आने का अनुमान है, जिससे **सरकार पर वित्तीय बोझ कम हो जाएगा** । यह कदम आवश्यक है, क्योंकि उर्वरक क्षेत्र देश के भीतर कुल सब्सिडी और बिजली खपत में महत्वपूर्ण योगदान देता है। **(इसलिए कथन 1 गलत है)**
- भारत अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उर्वरक आयात पर निर्भर है, जैसे कि यूरिया की मांग का लगभग 25-30% आयात करना। इसलिए, मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक के उपयोग को नियोजित करने से **आयात लागत कम हो जाएगी**, **जिससे खेती की प्रति इकाई पैदावार में वृद्धि होगी**।
- समय बीतने के साथ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) **भूमि प्रबंधन प्रथाओं से उत्पन्न मृदा स्वास्थ्य में परिवर्तन का पता लगा सकते हैं**।

22.**b**

स्पष्टीकरण:

कृषि उपज बाज़ार समिति (एपीएमसी)

- भारतीय संविधान के अनुसार कृषि विपणन राज्य (प्रांतीय) सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। जबकि राज्य के भीतर व्यापार राज्य सरकारों के दायरे में है, अंतर-राज्य व्यापार केंद्र या संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- कृषि उपज बाज़ार समिति (एपीएमसी) विशिष्ट अधिसूचित कृषि, बागवानी या पशुधन उत्पादों से जुड़ी व्यापारिक गतिविधियों की देखरेख के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक कानूनी रूप से स्थापित बाज़ार समिति है। यह ढांचा संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम के तहत संचालित होता है। **(अत: कथन 1 और 2 सही हैं)।**

KUMAR'S IAS

- एक निर्दिष्ट क्षेत्र को बाज़ार क्षेत्र के रूप में नामित किए जाने और बाज़ार समिति के अधिकार क्षेत्र में आने के बाद, थोक विपणन गतिविधियाँ प्रतिबंधित हो जाती हैं। एपीएमसी अधिनियम यह निर्धारित करता है कि क्षेत्र में उत्पादित अनाज, दालें और खाद्य तिलहन जैसी अधिसूचित कृषि वस्तुओं की प्रारंभिक बिक्री एपीएमसी की देखरेख में होनी चाहिए।
- यह लागू करों और शुल्कों के भुगतान के साथ लाइसेंस प्राप्त कमीशन एजेंटों के माध्यम से किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एपीएमसी खरीदारों पर बाजार शुल्क और कमीशन एजेंटों पर लाइसेंस शुल्क लगाते हैं, जो खरीदारों और किसानों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। **(इसलिए कथन 3 गलत है)**
- निर्यातकों, प्रोसेसरों और खुदरा श्रृंखला संचालकों को किसानों से सीधे खरीदारी करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उत्पादों को विनियमित बाजार चैनलों का पालन करना और लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को शामिल करना आवश्यक है।

23.**c**

स्पष्टीकरण:

प्रभाव बॉन्ड (Impact bonds)

- प्रभाव बांड नवीन वित्तीय उपकरण हैं जो विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश और विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं। वे केवल इनपुट से ध्यान हटाकर प्रदर्शन और परिणामों पर जोर देते हैं । पारंपरिक वित्तपोषण के बजाय जहां सरकारें या दानकर्ता किसी परियोजना को अग्रिम रूप से वित्तपोषित करते हैं, प्रभाव बांड में निजी निवेशक शामिल होते हैं, जिन्हें अक्सर जोखिम निवेशक कहा जाता है, जो शुरू में किसी पहल के लिए धन मुहैया कराते हैं। इन निवेशकों को पुनर्भुगतान सहमत परिणामों की पूर्ति पर निर्भर है, जिन्हें 'परिणामी फंडर्स' के रूप में पेश किया गया है। **(अत: कथन 1 ग़लत है और शेष सही हैं)**
- एक प्रभाव बांड, जिसे परिणाम-आधारित वित्तपोषण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, में एक निवेशक को सामाजिक सेवा कार्यक्रमों के लिए अग्रिम पूंजी का योगदान करना शामिल है। कार्यक्रम के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की सफल प्राप्ति के आधार पर, इस निवेश को अक्सर अतिरिक्त ब्याज/ प्रतिफल के साथ चुकाया जाता है। विशेष रूप से, सामाजिक प्रभाव बांड में, पुनर्भुगतान सरकार की ओर से होता है, जबकि विकास प्रभाव बांड में, एक तीसरा पक्ष, आमतौर पर एक दाता संगठन या फाउंडेशन, पुनर्भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।
- अक्टूबर 2021 में, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने भारत में कौशल विकास के लिए समर्पित 14.4 मिलियन डॉलर के फंड से जुड़ी एक अभूतपूर्व 'इम्पैक्ट बॉन्ड्स' पहल शुरू करने के लिए वैश्विक भागीदारों के साथ सहयोग किया। इस प्रयास का लक्ष्य चार साल की अवधि के भीतर 50,000 युवाओं को लाभान्वित करना है, उन्हें नौकरी के लिए तैयार कौशल से लैस करना है। लक्षित समूह में लगभग 60% महिलाएँ और लड़कियाँ शामिल हैं। व्यापक उद्देश्य उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना है, जिससे स्वास्थ्य सेवा, खुदरा, लॉजिस्टिक्स और परिधान सहित कोविड-19 रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वेतन-रोजगार तक पहुंच संभव हो सके।
- इसमें शामिल हितधारक हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को बढ़ाने, अनुसंधान का समर्थन करने और कौशल विकास कार्यक्रम के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे। प्रशिक्षण की सुविधा एनएसडीसी के संबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

KUMAR'S IAS

24.**a**

स्पष्टीकरण:

जून 2010 से, रिज़र्व बैंक **उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (CCS) निष्पादित कर रहा है।** यह सर्वेक्षण आर्थिक स्थितियों, घरेलू स्थितियों, आय, व्यय, मूल्य निर्धारण और रोजगार के अवसरों के संबंध में व्यक्तिपरक अंतर्दृष्टि एकत्र करता है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण से लिए गए हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण से मेल खाते हों। **(इसलिए विकल्प ए सही है)**

25.**d**

स्पष्टीकरण:

- मुद्रास्फीति प्रीमियम की अवधारणा में अतिरिक्त रिटर्न शामिल होता है जो निवेशक दीर्घकालिक प्रतिभूति के लिए प्रतिबद्ध होने पर अनुरोध करते हैं जहां वास्तविक रिटर्न पर मुद्रास्फीति का संभावित प्रभाव महत्वपूर्ण होता है।
- उदाहरण के लिए, ऐसे परिदृश्य पर विचार करें जहां वर्तमान मुद्रास्फीति दर 6% है, और बांड 8% के कूपन या ब्याज दर के साथ जारी किए जा रहे हैं। इसका मतलब 2% की वास्तविक ब्याज दर है, जो एक काफी अनुकूल संभावना है जो बांड में निवेश को प्रेरित कर सकती है।
- हालाँकि, अगर व्यापक अनुमान है कि मुद्रास्फीति लंबी अवधि में बढ़ सकती है, तो अनुमानित मुद्रास्फीति वृद्धि के कारण 8% ब्याज दर के साथ बांड खरीदने से भविष्य में वास्तविक रिटर्न कम हो सकता है। परिणामस्वरूप, व्यक्ति भविष्य में मुद्रास्फीति के जोखिम को महसूस कर सकते हैं और परिणामस्वरूप, बढ़े हुए मुद्रास्फीति जोखिम को ऑफसेट करने के लिए 8% से अधिक अतिरिक्त ब्याज दर (रिटर्न) की मांग कर सकते हैं। निवेशकों द्वारा मांगे गए इस पूरक ब्याज या रिटर्न को 'मुद्रास्फीति प्रीमियम' कहा जाता है। **(इसलिए विकल्प d) सही है)**

26.**b**

स्पष्टीकरण:

- भारत के गिनी गुणांक, जो आय असमानता को मापता है, में वृद्धि का अनुभव हुआ है। यह गुणांक 2011 में बढ़कर 35.7% हो गया और 2018 में बढ़कर 47.9% हो गया। **(इसलिए कथन 1 गलत है)**
- 1905 में अमेरिकी अर्थशास्त्री मैक्स लोरेंज द्वारा पेश किया गया लोरेंज वक्र ग्राफिक रूप से धन के वितरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस वक्र पर, धन वितरण की एक आदर्श समानता को एक सीधी विकर्ण रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि वास्तविक वितरण को इसके नीचे के वक्र द्वारा दर्शाया जाता है **। (अत: कथन 2 सही है)**
- अक्सर, गिनी सूचकांक को लोरेंज वक्र के माध्यम से दृश्यमान रूप से दर्शाया जाता है। लोरेंज वक्र क्षैतिज अक्ष पर आय और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर संचयी आय द्वारा जनसंख्या प्रतिशत को आलेखित करके आय (या धन) वितरण को दर्शाता है। गिनी गुणांक की गणना लोरेंज वक्र के नीचे के क्षेत्र को पूर्ण समानता की रेखा के नीचे के क्षेत्र से घटाकर और फिर पूर्ण समानता की रेखा के नीचे के क्षेत्र से विभाजित करके की जाती है। **(अत: कथन 3 सही है)**

27.**d**

स्पष्टीकरण:

डब्ल्यूटीओ का व्यापार-संबंधित निवेश उपाय (टीआरआईएमएस) समझौता इस आधार पर स्थापित किया गया है कि व्यापार और निवेश के बीच एक मजबूत संबंध मौजूद है। निवेश पर सीमाएं लगाने से व्यापार विकृत होने की संभावना है। **निवेश पर कई बाधाएँ**, जो व्यापार को बाधित करती हैं, अस्वीकार्य समझी जाती हैं। इनमें **स्थानीय सामग्री को अनिवार्य करना**, **निर्यात दायित्व लगाना**, **घरेलू रोजगार आवश्यकताओं को निर्धारित करना** और **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता जैसी** शर्तें शामिल हैं। **(अत: सभी सही हैं)**

28.**c**

स्पष्टीकरण:

- प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति (Counter-cyclical fiscal policy) व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान होने वाले आर्थिक उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने के लिए सरकारों द्वारा नियोजित एक रणनीति है। व्यापार चक्र में आर्थिक वृद्धि (विस्तार या तेजी) और आर्थिक संकुचन (मंदी) की अवधि शामिल होती है। प्रति-चक्रीय नीति का लक्ष्य चक्र में प्रचलित प्रवृत्तियों के विपरीत चलने वाले कार्यों को करके अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है। इस संदर्भ में, दिए गए कथनों को समझाया जा सकता है:
- सरकार आर्थिक विस्तार की अवधि के दौरान अत्यधिक तप्त होती अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए प्रति-चक्रीय नीति अपनाती है: आर्थिक विस्तार या उछाल की अवधि के दौरान, जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही होती है और संभावित रूप से अत्यधिक तप्त हो रही होती है, तो सरकार अर्थव्यवस्था को ठंडा करने के लिए प्रति-चक्रीय उपायों का उपयोग कर सकती है। इसमें अत्यधिक विकास को धीमा करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए सरकारी खर्च को कम करना और करों को बढ़ाना शामिल हो सकता है। **(अत: कथन 1 सही है)**
- प्रति-चक्रीय नीति के ढांचे के भीतर, जब अर्थव्यवस्था मंदी का अनुभव करती है तो सरकार व्यय बढ़ाती है और करों में कमी करती है: जब अर्थव्यवस्था मंदी में होती है, जिसमें आर्थिक गतिविधि में कमी और बढ़ती बेरोजगारी होती है, तो सरकार प्रति-चक्रीय उपाय लागू कर सकती है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए. इसमें रोजगार पैदा करने और मांग को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर सरकारी खर्च बढ़ाना शामिल हो सकता है, जबकि उपभोक्ता और व्यावसायिक खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए करों को कम करना भी शामिल हो सकता है। **(अत: कथन 2 सही है)**

29.**a**

स्पष्टीकरण:

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)

KUMAR'S IAS

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1976 के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के माध्यम से विशेष रूप से छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य सेवाएं प्रदान करके ग्रामीण आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी।
- जबकि रिज़र्व बैंक आरआरबी पर वित्तीय नियम लागू करता है, पर्यवेक्षी अधिकार नाबार्ड के पास है। **(इसलिए कथन 1 गलत है)**
- आरआरबी के लिए इक्विटी केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक द्वारा 50:15:35 के अनुपात में प्रदान की गई थी। **(इसलिए कथन 2 गलत है)**
- सीआरएआर, जिसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात के रूप में भी जाना जाता है, किसी बैंक की जोखिम-भारित परिसंपत्तियों और देनदारियों के सापेक्ष उसकी पूंजी का आकलन करता है। केंद्रीय बैंकों द्वारा स्थापित यह मानदंड आरआरबी पर लागू नहीं होता है। **(अत: कथन 3 सही है)।**
- हालाँकि, आय पहचान (income recognition), परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान को नियंत्रित करने वाले मानदंड, जो वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रासंगिक हैं, आरआरबी पर लागू होते हैं।

30.**c**

स्पष्टीकरण:

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना

- चल रहे प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, आरबीआई ने 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम' शुरू की है, जो एक व्यापक समाधान है जिसका उद्देश्य सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में व्यक्तिगत निवेशकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है।
- 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' योजना के प्रावधानों के तहत, व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों को आरबीआई के साथ 'रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट' (आरडीजी खाता) स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार दिया जाएगा। यह खाता योजना के लिए डिज़ाइन किए गए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शुरू किया जा सकता है। इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को सरकारी प्रतिभूतियों और NDS-OM (नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग सिस्टम) के प्राथमिक जारी करने में प्रवेश मिलेगा। **(इसलिए दोनों कथन सही हैं)**
- नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (NDS-OM), जिसे रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2005 में पेश किया था, सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक, स्क्रीन-आधारित, ऑर्डर-संचालित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। रिज़र्व बैंक के स्वामित्व वाला और सीसीआईएल द्वारा अनुरक्षित यह प्लेटफ़ॉर्म सरकारी प्रतिभूतियों के लिए मौजूदा ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) या फ़ोन बाज़ार के साथ-साथ संचालित होता है।
- एनडीएस-ओएम सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाता है, जिससे सदस्यों को एनडीएस-ओएम स्क्रीन पर सीधी बोली (खरीद ऑर्डर) और ऑफर (सेल ऑर्डर) लगाने की अनुमति मिलती है।
- इस योजना के अंतर्गत आने वाली सरकारी प्रतिभूतियों के दायरे में शामिल हैं:
    - भारत सरकार के राजकोषीय बिल
    - भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियाँ

- सॉवरेन गोल्ड बांड (एसजीबी)
- राज्य विकास ऋण (एसडीएल)

31.**d**

स्पष्टीकरण:

- देश के मौद्रिक प्राधिकरण, आरबीआई के संचयी दायित्व को मौद्रिक आधार या उच्च शक्ति वाली मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इसमें मुद्रा (जनता के बीच प्रचलन में नोट और सिक्के तथा वाणिज्यिक बैंकों के नकदी भंडार) के साथ-साथ भारत सरकार और आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई जमा राशि शामिल है।
- वॉल्ट कैश दैनिक परिचालन आवश्यकताओं के लिए एक वित्तीय संस्थान की वॉल्ट के भीतर रखी गई भौतिक मुद्रा से संबंधित है। ये तत्व उन मांगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आम जनता, सरकार या बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, इस प्रकार आरबीआई की देनदारियां बनती हैं। **(इसलिए विकल्प d) सही है)।**

32.**b**

स्पष्टीकरण:

- सरकारी राजस्व /कमाई को दो मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया गया है: राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ।
- राजस्व प्राप्तियों में वह प्राप्तियाँ शामिल होती है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी दायित्व या सरकारी संपत्ति में कमी नहीं होती है। इस श्रेणी में कर प्राप्तियाँ और गैर-कर प्राप्तियाँ दोनों शामिल हैं, जैसे शुल्क, जुर्माना, **स्पेक्ट्रम और सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्त आय, साथ ही विदेशी** सरकारों से अनुदान सहायता। ये प्राप्तियाँ सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से अर्जित वर्तमान आय का प्रतिनिधित्व करती हैं। **(अत: कथन 2 और 3 सही हैं)**
- दूसरी ओर, सरकारी प्राप्तियाँ जो या तो (i) उधार लेने जैसे दायित्व पैदा करती हैं, या (ii) **विनिवेश जैसी परिसंपत्तियों को कम करती हैं,** उन्हें पूंजीगत प्राप्तियाँ कहा जाता है। इसलिए, जब सरकार किसी देनदारी के जरिए या अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर धन प्राप्त करती है, तो यह पूंजीगत प्राप्तियों के वर्गीकरण के अंतर्गत आती है। परिणामस्वरूप, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश को पूंजीगत प्राप्तियों के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। **(इसलिए कथन 1 गलत है)**

33.**b**

स्पष्टीकरण:

राजकोषीय फिसलन (Fiscal slippage) उस स्थिति को संदर्भित करती है जहां सरकार अपने नियोजित राजकोषीय लक्ष्यों, जैसे बजट घाटे या ऋण स्तर से भटक जाती है। ऐसा तब हो सकता है जब वास्तविक व्यय अनुमानित व्यय से अधिक हो या जब राजस्व अनुमान से कम हो। इससे अक्सर सरकार के वित्त में असंतुलन पैदा होता है, जिससे संभावित रूप से आर्थिक स्थिरता और नीतिगत उद्देश्य प्रभावित होते हैं।

इसके अर्थव्यवस्था पर कई संभावित परिणाम हो सकते हैं।

- बांड प्रतिफल /यील्ड में वृद्धि: राजकोषीय फिसलन से घाटे को कवर करने के लिए सरकार द्वारा उधारी में वृद्धि हो सकती है। जब बाजार में उधारी अधिक होती है तो सरकारी बांड की मांग बढ़ जाती है। हालाँकि, यदि बांड की आपूर्ति मांग से अधिक हो जाती है, तो बांड की कीमतें कम हो जाती हैं, और परिणामस्वरूप, बांड यील्ड (प्रतिफल दरें) बढ़ जाती हैं। सरकार के राजकोषीय कुप्रबंधन से जुड़े कथित बढ़े हुए जोखिम की भरपाई के लिए निवेशक अधिक प्रतिफल की मांग करेंगे। **(अतः कथन 1 सही है)**
- बाजार ब्याज दरों में वृद्धि: राजकोषीय फिसलन से बाजार ब्याज दरों में वृद्धि होने की अधिक संभावना है। जब सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए अधिक उधार लेती है, तो वह धन के लिए बाजार में अन्य उधारकर्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। उधार लेने की यह बढ़ी हुई मांग ब्याज दरों को और अधिक बढ़ा सकती है, कम नहीं। **(इसलिए कथन 2 गलत है)**
- कुल मांग में वृद्धि: राजकोषीय गिरावट के परिणामस्वरूप उच्च सरकारी व्यय और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए संभावित कर कटौती हो सकती है। इससे व्यक्तियों के लिए प्रयोज्य आय में वृद्धि हो सकती है और सरकारी व्यय में वृद्धि हो सकती है, जो दोनों उच्च कुल मांग में योगदान कर सकते हैं। हालाँकि, क्या वास्तव में ऐसा होता है यह राजकोषीय फिसलन के जवाब में सरकार द्वारा लागू की गई विशिष्ट नीतियों पर निर्भर करता है। **(अतः कथन 3 सही है)**

34.**c**

स्पष्टीकरण:

- जीएसटी के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप करों की संख्या में कमी आई है, जिससे एक समान कर दर स्थापित हुई है जो सभी वस्तुओं और सेवाओं पर देश भर में लागू होती है। करों के इस मानकीकरण को **कर सामंजस्य** (**tax harmonisation**) कहा जाता है। निर्यात के मामले में, सरकार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया जीएसटी वापस कर देती है, जिससे संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला से जीएसटी प्रभावी रूप से समाप्त हो जाता है। इस प्रथा को 'शून्य-रेटेड' निर्यात के रूप में जाना जाता है। **(अतः दोनों कथन सही हैं)**
- केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत के दौरान, कर राजस्व में संभावित गिरावट और जीएसटी ढांचे के भीतर अतिरिक्त कर लगाने की उनकी क्षमता पर सीमाओं के बारे में राज्यों के बीच चिंताएं पैदा हुईं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने लगातार तीन वर्षों - 2012-13 से 2013-14, 2013-14 से 2014-15, और 2014-15 से 2015-16 तक राज्य अप्रत्यक्ष करों की वार्षिक वृद्धि की गणना की और एक औसत निर्धारित किया। वार्षिक वृद्धि दर 14% थी। सरकार ने राज्यों को आश्वासन दिया कि यदि जीएसटी कार्यान्वयन के बाद उनकी अप्रत्यक्ष राजस्व वृद्धि सालाना 14% से कम हो जाती है, तो विलासिता और अवगुण वस्तुओं पर उपकर लगाया जाएगा। फिर उत्पन्न राजस्व राज्यों को 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2022 तक पांच साल की अवधि में मुआवजे/ क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 अधिनियमित किया गया था।
- इस ढांचे के तहत, भारत सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर एकत्र करती है, इसे भारत के सार्वजनिक खाते के भीतर "जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष" में स्थानांतरित करने से पहले भारत के समेकित कोष में रखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पैसा

राज्यों के लिए निर्धारित किया जाता है और इसे सरकार का धन नहीं माना जाता है। अंततः, धनराशि संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हस्तांतरित कर दी जाती है।

- जीएसटी की शुरुआत के बाद, राजस्व में कमी आई और राज्यों को मुआवजा मिला। हालाँकि, COVID-19 महामारी ने इन कमियों को इस हद तक बढ़ा दिया कि विलासिता और अवगुण वस्तुओं पर उपकर बढ़ाना इस महत्वपूर्ण घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। नवंबर 2020 तक, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर एक विवाद सामने आया। अंततः, एक प्रस्ताव पर पहुंचा गया कि "केंद्र" (केंद्र सरकार) महामारी के कारण हुई अतिरिक्त कमी की राशि उधार लेगी। यह उधार ली गई राशि राज्यों को "बैक-टू-बैक" आधार पर ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। भविष्य में इस ऋण पर मूलधन और ब्याज चुकाने की जिम्मेदारी राज्यों की होगी। विशेष रूप से, केंद्र की डिफ़ॉल्ट करने में असमर्थता और इसकी मजबूत क्रेडिट रेटिंग के कारण राज्यों की तुलना में केंद्र की उधार लेने की लागत कम है।

35.**b**

स्पष्टीकरण:

- सरकार के लिए आय या राजस्व का प्राथमिक स्रोत लगाए गए करों और शुल्कों से उत्पन्न होता है। यह धनराशि परिचालन और विकासात्मक दोनों आवश्यकताओं के लिए आवंटित की जाती है। आमतौर पर, सरकार की आय को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ।
- पूंजीगत प्राप्तियों में वह आय शामिल होती है जिसके परिणामस्वरूप देनदारियां होती हैं या वित्तीय संपत्तियां कम हो जाती हैं। इसके विपरीत, गैर-ऋण प्राप्तियां वे हैं जो सरकार पर भविष्य के पुनर्भुगतान दायित्वों का बोझ नहीं डालती हैं।

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- ऋण और अग्रिम वसूली: इस श्रेणी में राज्य सरकारों, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों, विदेशी सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और अन्य स्वायत्त संस्थाओं से ऋण और अग्रिम की वसूली शामिल है। हालाँकि, ये वसूली समग्र गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। अतः कथन 1 सही है
- विविध पूंजीगत प्राप्तियां: इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के माध्यम से उत्पन्न आय शामिल है। इस आय को आगे विभाजित किया गया है:
  - **विनिवेश आय**
  - रणनीतिक विनिवेश
  - **शेयर बाजारों में सार्वजनिक उपक्रमों की सूची**
  - बोनस शेयर जारी करना **(इसलिए कथन 2 सही है)**
- ऋण प्राप्तियों के लिए सरकार द्वारा पुनर्भुगतान की आवश्यकता होती है। सरकारी व्यय का लगभग एक चौथाई हिस्सा उधार के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। पूंजीगत प्राप्तियों में आम जनता, विदेशी सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से ऋण शामिल होते हैं। ऋण पूंजी प्राप्तियों के उदाहरणों में बाजार ऋण, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां, विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां, अल्पकालिक उधार, ट्रेजरी बिल, छोटी बचत से जुड़ी प्रतिभूतियां, राज्य भविष्य निधि, बचत बांड, स्वर्ण बांड, बाह्य ऋण, और अन्य जैसे कई उपकरण शामिल हैं। ये ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के उदाहरण दर्शाते हैं। **(इसलिए कथन 3 गलत है)**

36.**d**

स्पष्टीकरण:

- सरकार या अन्य संस्थाओं द्वारा कोई भी विदेशी उधार हमारे राष्ट्र के लिए ऋण या दायित्व बनाता है। जब हम किसी विदेशी कंपनी के शेयर हासिल करते हैं, तो ये शेयर हमारे (हमारे देश) के लिए संपत्ति बन जाते हैं और संबंधित विदेशी देश या कंपनी के लिए देनदारियां बन जाते हैं। नतीजतन, भारत में किया गया कोई भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), जो अक्सर शेयरों के माध्यम से किया जाता है, भारतीय कंपनी और देश दोनों के लिए एक दायित्व बन जाता है।
- उदाहरण के लिए, यदि मेरी कंपनी विदेश से उधार लेती है, तो विदेशी बैंक के पास मौजूद ऋण पत्र विदेशी देश या बैंक के लिए संपत्ति और मेरी कंपनी या देश के लिए देनदारी बन जाता है।
- शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) हमारे राष्ट्र द्वारा रखी गई विदेशी संपत्ति (व्यक्तियों, कंपनियों और सरकार सहित) और हमारे देश की संपत्ति के विदेशी स्वामित्व के बीच असमानता को मापती है।
- जैसे-जैसे हमारे देश में एफडीआई प्रवाह बढ़ता है, यह हमारी कंपनी या देश के लिए दायित्व बोझ को बढ़ाता है, या इसके विपरीत, यह विदेशियों द्वारा रखी गई हमारे देश की संपत्ति के विदेशी स्वामित्व को बढ़ाता है। अधिक विदेशी उधार या एफडीआई निवेश जमा करने से हम पर बोझ पड़ता है, क्योंकि हमें अंततः इसे ब्याज, मूलधन या लाभांश के माध्यम से चुकाना होगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरह हमारे निवासियों द्वारा रखे गए विदेशी मुद्रा भंडार अनिवार्य रूप से गैर-निवासियों पर दावे का गठन करते हैं। इस प्रकार, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों की अधिक मात्रा हमारी एनआईआईपी स्थिति को मजबूत करती है, जिससे हमारी समग्र आर्थिक स्थिति बढ़ती है।
- **(अतः सभी कथन सही हैं)**

37.**b**

स्पष्टीकरण:

प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised unemployment)

प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें किसी रोज़गार के कुशल कामकाज के लिए वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है, जिससे व्यक्तिगत उत्पादकता कम हो जाती है। यह आमतौर पर कृषि में होता है, जहां अतिरिक्त श्रमिक ऐसे कार्यों में संलग्न होते हैं जिन्हें उत्पादन को प्रभावित किए बिना छोटे कार्यबल द्वारा संभाला जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप सीमांत या शून्य सीमांत उत्पादकता होती है, जो दर्शाता है कि यदि इनमें से कुछ अधिशेष श्रमिकों को निकाल दिया जाए, तो कुल उत्पादन प्रभावित नहीं होगा।

ऐसी स्थिति में यदि हम अधिक पूंजी जोड़ते हैं, तो उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन यदि हम अधिक श्रम जोड़ते हैं, तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। **(इसलिए कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है)**

तो, पूंजी की सीमांत उत्पादकता = उत्पादन में परिवर्तन = पूंजी में सकारात्मक परिवर्तन होगा

श्रम की सीमांत उत्पादकता = उत्पादन में परिवर्तन = श्रम में शून्य परिवर्तन होगा

38.**a**

स्पष्टीकरण:

- ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी), जिसे अक्सर ब्रिक्स बैंक के रूप में जाना जाता है, ब्रिक्स देशों - ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना 2014 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। एनडीबी का लक्ष्य उन परियोजनाओं का समर्थन करना है जिनका आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और पर्यावरणीय स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- बैंक के प्राथमिक फोकस क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन, जल आपूर्ति और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं जो सतत विकास को बढ़ावा देती हैं। एनडीबी अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ काम करता है, लेकिन इसका उद्देश्य उन परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना है जो इसके सदस्य देशों की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप हों।
- ब्रिक्स बैंक के पांच सदस्य हैं लेकिन कोई भी देश जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है वह ब्रिक्स बैंक का सदस्य बनने के लिए पात्र है।

39.**c**

स्पष्टीकरण:

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) एक देश से दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों, व्यवसायों या संस्थाओं द्वारा किए गए निवेश को संदर्भित करता है। इसमें किसी विदेशी कंपनी, प्रतिष्ठान या परियोजना में पर्याप्त स्वामित्व हिस्सेदारी या नियंत्रण प्राप्त करना शामिल है। एफडीआई देशों के बीच पूंजी प्रवाह का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसका उद्देश्य मेजबान देश की अर्थव्यवस्था में सतत हित, प्रभाव और नियंत्रण स्थापित करना है। यह रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आर्थिक विकास जैसे लाभ प्रदान कर सकता है, लेकिन संप्रभुता, बाजार एकाग्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को भी उठाता है।
- स्वचालित मार्ग या सरकारी मार्ग के माध्यम से क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है।
- स्वचालित रूट के तहत, न तो अनिवासी और न ही भारतीय कंपनियों को भारत सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, सरकारी मार्ग के लिए भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। सरकारी मार्ग के तहत विदेशी निवेश के प्रस्तावों की समीक्षा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है।

जिन क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई अधिकृत है उनमें शामिल हैं:

- कृषि और पशुपालन, जिसमें फूलों की खेती, बागवानी, मधुमक्खी पालन और सब्जियों और मशरूम की नियंत्रित खेती शामिल है
- बीज और रोपण सामग्री का विकास और उत्पादन

- पशुपालन (कुत्ते प्रजनन सहित), मछली पालन, और जलीय कृषि **(इसलिए 4 सही है)**
- धातु और गैर-धातु अयस्कों का खनन और अन्वेषण, जिसमें हीरा, सोना, चांदी और कीमती अयस्क शामिल हैं, लेकिन टाइटेनियम वाले खनिजों और उसके अयस्कों को छोड़कर है। (**इसलिए 3 सही है)**
- प्रसारण
- टेलीपोर्ट्स (अप-लिंकिंग हब/टेलीपोर्ट्स)
- डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाएं **(इसलिए 1 सही है)**
- केबल नेटवर्क (राष्ट्रीय, राज्य या जिला स्तर पर काम करने वाले मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और डिजिटलीकरण और एड्रेसेबिलिटी अपग्रेड में शामिल)
- मोबाइल टीवी
- स्काई ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (HITS)

जिन क्षेत्रों में एफडीआई के लिए प्रतिबंध है उनमें शामिल हैं:

- लॉटरी व्यवसाय, जिसमें सरकारी/निजी लॉटरी और ऑनलाइन लॉटरी शामिल हैं।
- चिट फंड
- हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) में व्यापार।
- सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट (तंबाकू या तंबाकू के विकल्प) का विनिर्माण।
- कैसीनो सहित जुआ और सट्टेबाजी।
- निधि कंपनियाँ। **(इसलिए 2 गलत है)**
- रियल एस्टेट व्यवसाय या फार्म हाउस का निर्माण।

40.**d**

स्पष्टीकरण:

- न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) एक निचली कीमत सीमा स्थापित करता है जिसके परे निर्यात निषिद्ध है। एमईपी लगाने का उद्देश्य घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं में संभावित व्यवधानों को रोकने और अनुचित मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए निर्यात को प्रतिबंधित करना है। यह रणनीति मुख्य रूप से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए तैयार की गई है।
- उदाहरण के लिए, ऐसे परिदृश्य पर विचार करें जहां प्याज का वैश्विक बाजार मूल्य 600 डॉलर प्रति टन है। घरेलू उपलब्धता और स्थिर मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए, सरकार $650 प्रति टन का एमईपी घोषित कर सकती है। इसका प्रभावी अर्थ यह है कि निर्यातक 650 डॉलर प्रति टन की सीमा से नीचे लेनदेन में संलग्न नहीं हो सकते हैं। 600 डॉलर प्रति टन की कम अंतरराष्ट्रीय कीमत को देखते हुए, यह निर्यात को हतोत्साहित करता है । **(अत: कथन 1 और 2 सही हैं)**
- दूसरी ओर, न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) न्यूनतम मूल्य स्तर को दर्शाता है जिसके नीचे आयात की अनुमति नहीं है। एमआईपी को आयात पर अंकुश लगाने और घरेलू उत्पादकों, विशेषकर किसानों को बचाने के इरादे से पेश किया गया है।

- उदाहरण के लिए, यदि गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय कीमत गिरकर, मान लीजिए, रु. 15 प्रति किलोग्राम, और घरेलू कीमत 18 रुपये प्रति किलोग्राम पर बनी हुई है। सस्ता आयातित गेहूं भारतीय बाजार में बाढ़ ला सकता है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय किसानों से खरीद कम हो सकती है। इन किसानों के हितों की रक्षा के लिए, सरकार 20 रुपये प्रति किलोग्राम का एमआईपी निर्धारित कर सकती है। इसका मतलब यह होगा कि भारत के आयातक 20 रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे गेहूं नहीं खरीद सकते। वास्तविक रूप से, घरेलू स्तर पर उत्पादित गेहूं की उपलब्धता को देखते हुए, भारतीय आयातक इस कीमत से ऊपर खरीदारी करने में अनिच्छुक होंगे। **(अत: कथन 3 और 4 सही हैं)**

41.**d**

स्पष्टीकरण:

रिफ़्लेशन/ पुन:मुद्रास्फीति:

- रिफ्लेशन एक आर्थिक अवधारणा है जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और कीमतों में वृद्धि के लिए सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए जानबूझकर किए गए प्रयासों को संदर्भित करती है, खासकर सुस्त आर्थिक गतिविधि या अपस्फीति दबाव के समय में। रिफ्लेशनरी उपायों का उद्देश्य अपस्फीति (कीमतों में सामान्य कमी) को उलटना और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना है।

रिफ्लेशन में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का संयोजन शामिल है:

- राजकोषीय प्रोत्साहन: इसमें उपभोक्ता और व्यावसायिक खर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खर्च में वृद्धि या कर में कटौती शामिल है। अर्थव्यवस्था में अधिक पैसा डालकर, राजकोषीय प्रोत्साहन वस्तुओं और सेवाओं की मांग को उत्तेजित करता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में वृद्धि हो सकती है।
- मौद्रिक प्रोत्साहन: केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कि ब्याज दरों को कम करना या मात्रात्मक सहजता (अर्थव्यवस्था में पैसा लगाने के लिए वित्तीय संपत्ति खरीदना) में संलग्न होना। कम ब्याज दरें उधार लेना सस्ता बनाती हैं, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को उधार लेने और खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जिससे आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है।
- रिफ्लेशन का लक्ष्य एक सकारात्मक आर्थिक चक्र बनाना है: बढ़े हुए खर्च से उच्च उत्पादन होता है, जो अधिक आय और खपत उत्पन्न करता है, जिससे आगे आर्थिक विकास होता है। अपस्फीति के दबावों को संबोधित करके और आर्थिक गतिविधि को उत्तेजित करके, रिफ्लेशन का उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना, रोजगार बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक ठहराव की अवधि में गिरने से रोकना है।
- आर्थिक मंदी की अवधि के दौरान या जब मुद्रास्फीति बेहद कम हो, तो रिफ्लेशन विशेष रूप से प्रासंगिक होता है। हालाँकि, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और अत्यधिक मुद्रास्फीति से बचने के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। यदि रिफ्लेशनरी नीतियां अत्यधिक आक्रामक हैं, तो वे अत्यधिक तप्त अर्थव्यवस्था और उच्च मुद्रास्फीति को जन्म दे सकती हैं, जिसके लंबे समय में नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।

(अत: सभी कथन सही हैं)

KUMAR'S IAS

42.**a**

स्पष्टीकरण:

नाइजर (रामतिल) की खेती:

- नाइजर (रामतिल) की खेती खरीफ, देर से खरीफ और रबी मौसम के दौरान वर्षा आधारित स्थितियों में की जाती है। इसे एकल फसल के रूप में उगाया जा सकता है या विभिन्न राज्यों में छोटे बाजरा, बाजरा, मोती बाजरा, मूंगफली या दलहन फसलों के साथ मिलाया जा सकता है। **(इसलिए कथन 2 गलत है)**

मसूर की खेती

- मसूर (दाल) एक स्टार्चयुक्त दाल है जिसका उपयोग ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। इसकी खेती शुरुआती सर्दियों के महीनों के दौरान की जाती है, जिसमें उपयुक्त तापमान लगभग 18-20 डिग्री सेल्सियस और लगभग 100 सेमी वर्षा होती है। इसलिए, इसे रबी फसल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। **(इसलिए कथन 2 गलत है)**

दलहन उत्पादन, उपभोग और व्यापार में भारत की भूमिका:

- भारत को विश्व में दालों का अग्रणी उत्पादक, आयातक और उपभोक्ता होने का गौरव प्राप्त है। यह वैश्विक उत्पादन का लगभग 25%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 15% और वैश्विक खपत का 27% है। **(अत: कथन 1 सही है)।**

नाइजर (रामतिल) की खेती के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी):

- नाइजर या रामतिल (गुइज़ोटिया एबिसिनिका) उन 14 ख़रीफ़ फसलों में से एक है जिसके लिए सरकार सालाना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जारी करती है। यह कम प्रसिद्ध तिलहन उच्चतम एमएसपी में से एक है, जो उत्पादन लागत और बाजार की मांग के आधार पर स्थापित किया जाता है। 2020-21 सीज़न में, इसका खेती का क्षेत्र 80% कम हो गया, और 0.1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक तक पहुंच गया। एमएसपी वाली 14 ख़रीफ़ फसलों में यह सबसे छोटा क्षेत्र है।
- पिछले तीन दशकों में नाइजर का कृषि क्षेत्र लगातार कम हुआ है। इसके विपरीत, सरसों की खेती 84.76 लाख हेक्टेयर (24.9% की वृद्धि) तक बढ़ गई है। **(इसलिए कथन 3 गलत है)**

43.**a**

स्पष्टीकरण:

परिभाषा और महत्व:

कोयला एक ज्वलनशील काली या भूरी-काली तलछटी चट्टान है जो मुख्य रूप से कार्बन के साथ-साथ हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे अन्य तत्वों की अलग-अलग मात्रा से बनी होती है। बिजली उत्पादन, औद्योगिक प्रक्रियाओं और ताप उत्पादन में अपनी भूमिका के कारण यह सदियों से एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन रहा है।

कोयले के प्रकार:

कोयले को उसकी कार्बन सामग्री और ऊर्जा सामग्री के आधार पर चार मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- एन्थ्रेसाइट: उच्चतम कार्बन सामग्री, कठोर, चमकदार और कम अशुद्धियाँ। उच्च ताप उत्पादन प्रदान करता है लेकिन कम प्रचुर मात्रा में होता है।
- बिटुमिनस: इसमें उप-बिटुमिनस और लिग्नाइट कोयले की तुलना में अधिक कार्बन सामग्री होती है। बिजली उत्पादन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- उप-बिटुमिनस: निम्न कार्बन सामग्री, उच्च नमी सामग्री, और आमतौर पर नए कोयला भंडार में पाया जाता है।
- लिग्नाइट: सबसे निम्न कार्बन सामग्री और उच्चतम नमी सामग्री। अक्सर इसे "भूरा कोयला" कहा जाता है।

कोयले का उपयोग:

- बिजली उत्पादन: बिजली संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए कोयला ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है।
- औद्योगिक प्रक्रियाएँ: इसका उपयोग स्टील, सीमेंट और कागज निर्माण जैसे उद्योगों में किया जाता है।
- ताप: कोयले का उपयोग घरों, इमारतों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को गर्म करने के लिए किया जाता रहा है।
- खाना पकाने और चारकोल का उत्पादन: कुछ क्षेत्रों में, कोयले का उपयोग खाना पकाने और चारकोल के उत्पादन के लिए किया जाता है।

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता है, जबकि चीन उत्पादन और खपत दोनों में शीर्ष स्थान हासिल करता है। **(अत: कथन 1 ग़लत और 2 सही है)**

इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका कोयला उत्पादन और खपत के मामले में भारत के बाद है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, भारत का कोयला उत्पादन 778 मिलियन मीट्रिक टन था, जबकि कोयला आयात, जिसमें कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयला दोनों शामिल थे, कुल मिलाकर लगभग 209 मिलियन मीट्रिक टन था। **(इसलिए कथन 3 गलत है)**

44.**d**

स्पष्टीकरण:

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एक विशिष्ट समय सीमा, आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य शामिल होता है।

किसी राष्ट्र के घरेलू क्षेत्र में शामिल हैं:

- प्रादेशिक जलक्षेत्रों को घेरने वाली राजनीतिक सीमाएँ।
- जहाज और विमान देश के निवासियों द्वारा संचालित होते हैं, यहां तक कि कई देशों के बीच यात्रा करते समय भी, जैसे एयर इंडिया की क्रॉस-कंट्री सेवाएं।
- मछली पकड़ने के जहाज, तेल और प्राकृतिक गैस रिग, और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म देश के निवासियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय जल या उन क्षेत्रों में संचालित होते हैं जहां विशेष परिचालन अधिकार हैं।

- विदेशी देशों में स्थित देश के दूतावास, वाणिज्य दूतावास और सैन्य प्रतिष्ठान, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में भारतीय दूतावास। इसमें भारत के भीतर विदेशी दूतावास, वाणिज्य दूतावास, सैन्य प्रतिष्ठान और अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्यालय शामिल नहीं हैं।
- संक्षेप में, घरेलू क्षेत्र को किसी देश की राजनीतिक सीमाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें क्षेत्रीय जल के साथ-साथ जहाज, विमान, इसके निवासियों द्वारा संचालित मछली पकड़ने वाले जहाज और विदेशी राजनयिक मिशन शामिल हैं। यदि कोई गतिविधि अंतरराष्ट्रीय जल या हवाई क्षेत्र में होती है जिस पर किसी देश का दावा नहीं है, तो उस गतिविधि को उस देश के सकल घरेलू उत्पाद में एकीकृत किया जाएगा जिसके निवासी उक्त व्यवसाय के मालिक हैं या गतिविधि में संलग्न हैं।
  (इसलिए सभी भारत की जीडीपी में शामिल हैं)

45.**b**

स्पष्टीकरण:

सिग्नियोरेज (Seigniorage) मुद्रा सृजन के माध्यम से उत्पन्न लाभ/आय से संबंधित है, जो सरकारों को पारंपरिक कराधान का सहारा लिए बिना धन जुटाने का एक साधन प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक लाभ के रूप में संपत्ति अर्जित करते हैं, जिसे बाद में केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है। **(इसलिए विकल्प बी सही है)**

यह लाभ निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जाता है:

- मुद्रा जारी करते समय, आरबीआई द्वारा बनाए रखे गए भंडार से प्रचलन में कुल मुद्रा (मुद्रा उत्पादन लागत घटाकर) के आधार पर ब्याज आय प्राप्त होती है।
- ब्याज केंद्रीय बैंकों के पास रखे गए बैंक शेष से अर्जित होता है, जो बैंकों द्वारा अपनी निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरक्षित निधि बनाए रखने की आवश्यकता से उत्पन्न होता है। ये भंडार ब्याज-मुक्त शेष (सीआरआर) के रूप में या बाजार मानदंड से कम दरों पर हो सकते हैं।
- मुद्रास्फीति कर की अवधारणा उत्पन्न होती है, जिसकी गणना मुद्रास्फीति दर और मौद्रिक आधार के उत्पाद के रूप में की जाती है। (मुद्रास्फीति के कारण जनता के पास मौजूद मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, जिससे आरबीआई की देनदारी में कमी आती है।)

46.**b**

स्पष्टीकरण:

मूल्यह्रास (Depreciation) से तात्पर्य किसी संपत्ति के मूल्य में समय के साथ टूट-फूट, अप्रचलन या अन्य कारकों के कारण धीरे-धीरे होने वाली कमी से है। यह एक लेखांकन पद्धति है जिसका उपयोग किसी परिसंपत्ति की लागत को उसके उपयोगी जीवन में आवंटित करने के लिए किया जाता है, जो कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इसके घटते मूल्य को दर्शाता है। किसी व्यवसाय की वास्तविक वित्तीय स्थिति की गणना करते समय और प्रत्येक लेखांकन अवधि को पहचानने के लिए व्यय की उचित मात्रा निर्धारित करते समय यह अवधारणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है।

रुपये के मूल्यहास से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई प्रभाव पड़ सकते हैं:

- निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता: कमजोर रुपया विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय निर्यात को अधिक किफायती बनाता है, संभावित रूप से निर्यात को बढ़ावा देता है और व्यापार संतुलन में सुधार करता है। **(अत: कथन 1 सही है)**
- आयात लागत: रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण आयात अधिक महंगा हो जाता है, जिससे कच्चे माल और आवश्यक वस्तुओं सहित आयातित वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है। **(अत: कथन 2 सही है)**
- मुद्रास्फीति: आयात की बढ़ी हुई लागत उच्च मुद्रास्फीति में योगदान कर सकती है, जिससे नागरिकों के जीवनयापन की कुल लागत प्रभावित हो सकती है।
- चालू खाता घाटा: जबकि निर्यात बढ़ सकता है, उच्च आयात लागत भी चालू खाता घाटे को बढ़ा सकती है क्योंकि देश आयात पर अधिक खर्च करता है।
- विदेशी ऋण: यदि किसी देश पर विदेशी ऋण है, तो कमजोर रुपया ऐसे ऋण को चुकाने का बोझ बढ़ा सकता है। **(इसलिए कथन 3 गलत है)**
- निवेशकों का विश्वास: मुद्रा का मूल्यहास निवेशकों के विश्वास को कम कर सकता है क्योंकि यह आर्थिक स्थिरता और विदेशी निवेश के आकर्षण के बारे में चिंताएँ पैदा करता है।
- पर्यटन: वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती सामर्थ्य के कारण कमजोर मुद्रा भारत को विदेशी पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बना सकती है।
- प्रेषण: घर वापस पैसा भेजने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए, कमजोर रुपये का मतलब है कि उनके प्रेषण से भारत में क्रय शक्ति अधिक होगी।
- मौद्रिक नीति: मुद्रास्फीति और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने के लिए केंद्रीय बैंक को अपनी मौद्रिक नीति को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है।
- अटकलें: मुद्रा का मूल्यहास विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी गतिविधियों को आकर्षित कर सकता है, जिससे मुद्रा की अस्थिरता संभावित रूप से बढ़ सकती है।
- सरकारी वित्त: यदि भारत बड़ी मात्रा में सामान आयात करता है, तो तेल सहित आयात की उच्च लागत के कारण रुपये का मूल्यह्रास सरकारी वित्त पर दबाव डाल सकता है।

47.**a**

स्पष्टीकरण:

- प्रचलन में मुद्रा में नोट और सिक्के दोनों शामिल हैं। जबकि सभी मुद्रा नोट (एक रुपये के नोट को छोड़कर) आरबीआई की देनदारियां मानी जाती हैं, एक रुपये के नोट और सिक्के भारत सरकार द्वारा उत्पादित किए जाते हैं और इस प्रकार इसकी देनदारियां हैं। **(इसलिए कथन 1 गलत है)।**
- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रचलन में मौजूद सभी मुद्राएँ, मुद्रा आपूर्ति में योगदान नहीं करती हैं। विशेष रूप से, केवल जनता के पास मौजूद मुद्रा को ही मुद्रा आपूर्ति का हिस्सा माना जाता है। बैंकों द्वारा रखी गई मुद्रा को मुद्रा आपूर्ति गणना में शामिल नहीं किया जाता है। **(अत: कथन 2 ग़लत है)।**

- प्रचलन में मुद्रा के लिए समीकरण है: प्रचलन में मुद्रा = जनता के पास मुद्रा + बैंकों के पास मुद्रा।
- भारत सरकार द्वारा एक रुपये के नोट और सिक्के ढाले जाने के बावजूद, आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार अर्थव्यवस्था में सभी मुद्रा नोटों और सिक्कों को प्रसारित करने के लिए आरबीआई उत्तरदायी है। (इसलिए कथन 3 **सही है)**

48.**c**

स्पष्टीकरण:

- "भारत बॉन्ड ईटीएफ" एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड है जो भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई), केंद्रीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (सीपीएफआई) और अन्य सरकारी संगठनों द्वारा जारी बांड में निवेश को सक्षम करने के लिए बनाया गया है।
- इन ईटीएफ का उद्देश्य निवेशकों की तरलता में सुधार करना, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करना तथा भरोसेमंद और लगातार निवेश विकल्प प्रदान करना है। **(अत: कथन 1 सही है)**
- प्रत्येक ईटीएफ की विशिष्ट परिपक्वता तिथियां होती हैं और निवेशक विभिन्न परिपक्वता अवधि वाले विभिन्न ईटीएफ में से चयन कर सकते हैं।
- ये ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं, जिससे निवेशकों के लिए सुविधाजनक खरीद और बिक्री की सुविधा मिलती है।
- हालाँकि इन ईटीएफ के प्राथमिक दर्शक संस्थागत निवेशक हैं, खुदरा निवेशक भी द्वितीयक बाजार के माध्यम से इनमें निवेश करके भाग ले सकते हैं। **(अत: कथन 4 सही है)**
- भारत बॉन्ड ईटीएफ की शुरूआत भारतीय बॉन्ड बाजार की उन्नति में योगदान देती है और निवेशकों को सरकार से जुड़ी ऋण प्रतिभूतियों में संलग्न होने का अवसर प्रदान करती है। **(अत: कथन 2 सही है)**
- न्यूनतम बांड का आकार 1000 रुपये पर निर्धारित किया गया है, **खुदरा व्यक्तियों को खरीदारी करने में सक्षम बनाता है। (इसलिए कथन 3 गलत है)**
- यह प्रावधान "कॉर्पोरेट बांड बाजार" को व्यापक जन के लिए सुलभ बनाकर इसे गहरा करने का कार्य करता है।

49.**a**

स्पष्टीकरण:

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) विदेशी मुद्रा प्रवाह राशि के बराबर सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार में बिक्री करता है, इस प्रकार उच्च- शक्ति वाली मुद्रा और कुल मुद्रा आपूर्ति के स्तर को बनाए रखता है। यह प्रथा, जिसे स्टेरीलाईज़ेशन के रूप में जाना जाता है, चीजों को संतुलित रखते हुए, प्रतिकूल बाहरी प्रभावों से अर्थव्यवस्था की रक्षा करती है। **(अत: कथन 1 सही है)।**

KUMAR'S IAS

- मुद्रा अभिमूल्यन या मुद्रास्फीति के जोखिमों का मुकाबला करने के लिए, केंद्रीय बैंक अक्सर पूंजी प्रवाह को निष्फल करने में लगे रहते हैं। इस प्रक्रिया में भंडार के प्रवाह को संतुलित करने के लिए मौद्रिक आधार (बैंक भंडार और मुद्रा सहित) के घरेलू घटक को अस्थायी रूप से कम करना शामिल है। सैद्धांतिक रूप से, इसे विदेशी निजी निवेश को प्रोत्साहित करने या स्थानीय बाजार से विदेशी उधार लेने की अनुमति देने जैसे तरीकों से हासिल किया जा सकता है। परंपरागत रूप से, खुले बाज़ार का संचालन स्टेरीलाईज़ेशन का प्राथमिक साधन रहा है । अतिरिक्त तकनीकों में वाणिज्यिक बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बढ़ाने या कुल विस्तारित ऋण पर सीमा लगाने जैसे उपाय शामिल हैं। **(इसलिए कथन 2 गलत है)**

50.**d**

स्पष्टीकरण:

- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) की उत्पत्ति 1966 में हुई जब मोरारजी देसाई ने कृषि और छोटे उद्योगों के लिए ऋण पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता को चिन्हित किया। फिर भी, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की औपचारिक परिभाषा 1972 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट राष्ट्रीय क्रेडिट काउंसिल को प्रस्तुत किए जाने के बाद स्थापित की गई थी।
- प्राथमिकता के आधार पर विशिष्ट क्षेत्रों, उत्पादन सेवाओं, विनिर्माण, व्यक्तियों और समूहों को समय पर और पर्याप्त ऋण प्रदान करने के इरादे से, प्राथमिकता क्षेत्र के भीतर कुछ योग्य श्रेणियों में शामिल हैं:
  - कृषि: कृषि ऋण (कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ), कृषि अवसंरचना और सहायक गतिविधियों के लिए ऋण
  - पारंपरिक/गैर-पारंपरिक वृक्षारोपण, बागवानी और संबद्ध गतिविधियों के लिए फसल ऋण
  - **किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण**
  - **प्रधानमंत्री जन-धन योजना** (पीएमजेडीवाई) खाताधारकों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा
  - **कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों के तहत निर्यात ऋण**
  - **आवास एवं शिक्षा ऋण**
  - सामाजिक अवसंरचना
  - **नवीकरणीय ऊर्जा**
  - कारीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, जिनकी व्यक्तिगत ऋण सीमा 71 लाख से अधिक नहीं है
  - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), और मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्व-रोज़गार योजना (एसएमएस) जैसी सरकार प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी
  - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

(इसलिए सभी को बैंकों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण माना जाता है)

51.**b**

स्पष्टीकरण:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस): अवलोकन, कार्यप्रणाली, सीमाएँ और सुधार

पीडीएस का अवलोकन और कार्यप्रणाली:

- **गरीबों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न की आपूर्ति करके खाद्य सुरक्षा** सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।
- यह वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित करके खुले बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकता है। **(अत: कथन 1 सही है)**
- भारतीय पीडीएस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भोजन की कमी के जवाब में स्थापित एक व्यापक नेटवर्क है।
- यह उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से देश भर में उपभोक्ताओं के लिए सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
- वितरित की गई प्रमुख वस्तुएं: गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल, आदि।
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इस प्रणाली की देखरेख करता है।
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में खाद्यान्न की खरीद और भंडारण की देखरेख के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण **विभाग जिम्मेदार है। (इसलिए कथन 2 गलत है)**
- तमिलनाडु प्रभावी पीडीएस कार्यान्वयन के लिए अग्रणी है।

वर्तमान पीडीएस की सीमाएँ:

- पात्र परिवारों की पहचान एक चुनौती बनी हुई है।
- खाद्यान्न खरीद और उत्पादन स्तर के बीच विसंगतियाँ।
- खाद्यान्नों के लिए अपर्याप्त भण्डारण सुविधाएँ।
- सरकार पर खाद्य सब्सिडी का भारी बोझ।
- गरीबों के लिए खाद्यान्न का रिसाव और दुरुपयोग।
- एफपीएस और भंडारण सुविधाओं सहित पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव।

पीडीएस में सुधार:

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की शुरूआत का उद्देश्य गरीबों को सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराना है।
- टीपीडीएस में किसानों से खाद्यान्न खरीदना और लाभार्थियों के लिए राशन की दुकानों तक पहुंचाना शामिल है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ने भोजन के अधिकार को न्यायसंगत बना दिया।
- पात्र परिवारों की सटीक पहचान पर ध्यान देना।
- खरीद और भंडारण सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर देना।
- खाद्य सब्सिडी प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना।
- रिसाव एवं डायवर्जन को रोकने के उपाय लागू करना।
- टीपीडीएस दक्षता बढ़ाने के लिए विकल्प तलाशना।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य:

KUMAR'S IAS

- सभी, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आपूर्ति-मांग असंतुलन को ठीक करना तथा **जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना**। **(अत: कथन 3 सही है)**
- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हुए बुनियादी आवश्यकताओं को समान रूप से वितरित करना।
- कीमतों को स्थिर करना और बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तुओं की उपलब्धता।
- गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों, ग्रामीण रोजगार और शैक्षिक भोजन पहल का समर्थन करना।

52.**b**

स्पष्टीकरण:

पीडीएस में सुधार:

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की शुरूआत का उद्देश्य गरीबों को सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराना है।
- टीपीडीएस में किसानों से खाद्यान्न खरीदना और लाभार्थियों के लिए राशन की दुकानों तक पहुंचाना शामिल है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ने भोजन के अधिकार को न्यायसंगत बना दिया।
    - **इसने इसे एक न्यायसंगत अधिकार बना दिया:** अधिनियम ने भोजन के अधिकार को एक न्यायसंगत अधिकार तक बढ़ा दिया, जिसका अर्थ है कि यदि भोजन तक पहुंच के उनके अधिकार को बरकरार नहीं रखा जाता है तो व्यक्ति अब कानूनी उपचार ले सकते हैं। **(अत: कथन 1 सही है)**
- पात्र परिवारों की सटीक पहचान पर ध्यान देना।
- खरीद और भंडारण सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर देना।
- खाद्य सब्सिडी प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना।
- रिसाव एवं डायवर्जन को रोकने के उपाय लागू करना।
- टीपीडीएस दक्षता बढ़ाने के लिए विकल्प तलाशना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में

कार्यान्वयन एवं संरेखण

- अधिनियम 12 सितंबर 2013 को हस्ताक्षरित होकर कानून बन गया (5 जुलाई 2013 से पूर्वव्यापी)।
- संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य दो के साथ संरेखित।
- लक्ष्य 2 2030 तक भूखमरी ख़त्म करने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने पर केंद्रित है। **(इसलिए कथन 2 सही है)**
- लाभार्थियों को प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले परिवारों में वर्गीकृत किया गया है।
- पात्रता: प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न (5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह)।

KUMAR'S IAS

- लागत: गेहूं रु. 2 प्रति किलो, चावल रु. 3 प्रति किलोग्राम, और मोटा अनाज रु. 1 प्रति किग्रा. (केंद्रीय बजट 2022 में खाद्यान्न की कीमतों में कोई संशोधन नहीं।) **(इसलिए कथन 3 गलत है)**

उद्देश्य और कवरेज

- उद्देश्य: स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त, उच्च गुणवत्ता वाला भोजन सुनिश्चित करना।
- इसमें मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), और एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) जैसी योजनाएं शामिल हैं।
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया।

53.**c**

स्पष्टीकरण:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का तार्किक प्रबंधन:

खाद्यान्न की खरीद:

- टीपीडीएस के लिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्न खरीदा गया।
- केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों से खरीद की देखरेख करती है।
- केंद्रीकृत और विकेन्द्रीकृत खरीद विधियाँ:
- केंद्रीकृत: एफसीआई द्वारा सीधे किसानों से किया जाता है।
- विकेंद्रीकृत: स्थानीय खरीद के लक्ष्य के साथ एफसीआई की ओर से 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित।

लाभार्थियों की पहचान:

- केंद्र और राज्य एनएसएसओ तथा योजना आयोग के डेटा को शामिल करने वाली एक प्रक्रिया के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की पहचान करते हैं।
- गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) परिवारों के लिए कोई पहचान नहीं; पात्र परिवार राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- भूमि जोत, कपड़ा, खाद्य सुरक्षा और आजीविका के साधन जैसे मानदंडों के आधार पर राशन कार्ड आवंटन। **(अत: कथन 1 सही है)**

राशन कार्ड जारी करना:

- उचित मूल्य की दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाने वाला राशन कार्ड।
- एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय परिवारों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्ड।
- आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण, निवास प्रमाण के लिए मौके पर पूछताछ, जारी करने की समयसीमा।

भंडारण प्रबंधन:

- केंद्र सरकार आपात स्थिति के लिए न्यूनतम बफर स्टॉक रखती है।
- **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** केंद्रीय पूल स्टॉक भंडारण के लिए उत्तरदायी है। **(अत: कथन 2 सही है)**
- गोदामों, साइलो और खुले स्थानों (सीएपी) में भंडारण।
- एफसीआई स्टॉक को समायोजित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों से जगह किराए पर लेता है।
- सीएजी ने एफसीआई और राज्यों में भंडारण क्षमता के कम उपयोग का उल्लेख किया।

खाद्यान्न का आवंटन:

- केंद्र सरकार बीपीएल, एएवाई और एपीएल परिवारों को वितरण के लिए राज्यों को खाद्यान्न आवंटित करती है।
- चिन्हित परिवारों के आधार पर बीपीएल और एएवाई आवंटन।
- **केंद्रीय पूल स्टॉक उपलब्धता और राज्यों द्वारा पिछले उठान के आधार पर एपीएल आवंटन। (अत: कथन 3 सही है)**
- आपात्कालीन स्थिति के दौरान तदर्थ आवंटन।

खाद्यान्न का परिवहन:

- रोडवेज और रेलवे के माध्यम से खाद्यान्न का परिवहन किया गया।
- चयन आयतन और दूरी पर निर्भर करता है।
- छोटी दूरी के लिए सड़क मार्ग, लंबी दूरी के लिए रेलवे।

उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) संचालन:

- इन्हें राशन की दुकानों के नाम से भी जाना जाता है।
- राशन कार्ड के आधार पर खाद्यान्न जारी करना।
- कम कीमत पर अनाज बेचने के लिए राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना।

उपभोक्ता:

- न्यूनतम बाजार मूल्य पर एफपीएस से खाद्यान्न खरीदने वाले व्यक्ति।
- खरीदारी के लिए वैध राशन कार्ड की आवश्यकता है।

54.**d**

स्पष्टीकरण:

कृषि में निजी निवेश का प्रसार:

वास्तव में, कोविड-19 महामारी के बाद भी कृषि में निजी निवेश में वृद्धि देखी गई। इस आश्चर्यजनक प्रवृत्ति के लिए कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। सबसे पहले, महामारी ने कृषि क्षेत्र की आवश्यक प्रकृति पर प्रकाश डाला, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में

इसकी भूमिका पर जोर दिया। इस मान्यता ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशकों को कृषि में धन लगाने के लिए प्रेरित किया, इसे अपेक्षाकृत स्थिर और मंदी-प्रतिरोधी क्षेत्र माना। **(इसलिए कथन 1 गलत है)**

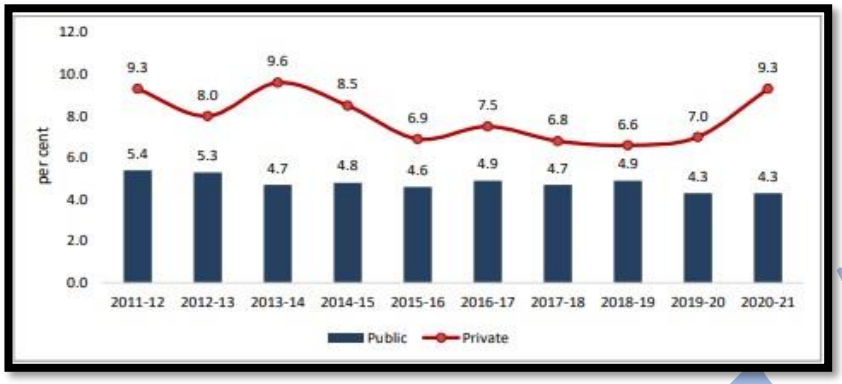

कोविड-19 के झटके के बावजूद कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने लचीला विकास दिखाया है

कोविड-19 झटके के प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद, कृषि और संबद्ध क्षेत्र वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सकारात्मक वृद्धि हासिल करने में कामयाब रहे। विशेष रूप से, उनका लचीलापन स्पष्ट हो गया क्योंकि उन्होंने न केवल महामारी से उत्पन्न प्रारंभिक चुनौतियों का सामना किया, बल्कि बाद के समय में इससे उबरने और सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करने में भी कामयाब रहे। **(इसलिए कथन 2 गलत है)**

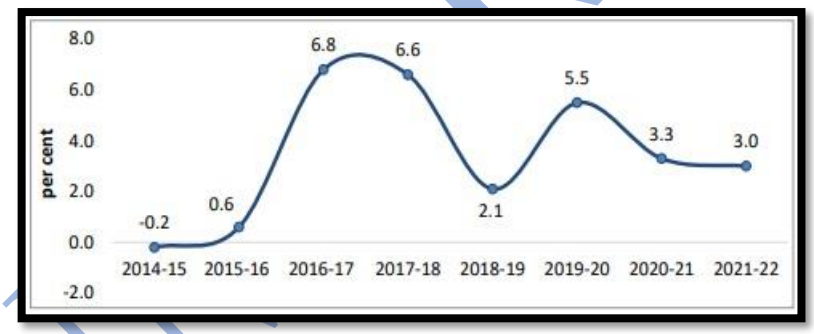

55.**c**

स्पष्टीकरण:

खाद्यान्न का उत्पादन

- **रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन:** 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान से खाद्यान्न और तिलहन उत्पादन में साल-दर-साल (YoY) लगातार वृद्धि का पता चलता है। **(अत: कथन 1 सही है)**
- दालों का उत्पादन: विशेष रूप से, दालों का उत्पादन पांच साल के औसत 23.8 मिलियन टन से अधिक हो गया है। यह दालों के उत्पादन में सकारात्मक रुझान का संकेत देता है।

- जलवायु प्रभाव: बदलते जलवायु पैटर्न ने कृषि पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। 2022 में, गेहूं की कटाई के मौसम के दौरान शुरुआती हीट वेव के कारण गेहूं के उत्पादन में कमी आई। इसके अलावा, ख़रीफ़ सीज़न में कम वर्षा और मानसून में देरी के कारण धान की खेती के लिए बोया गया क्षेत्र कम हो गया।
- धान की खेती: 2022-23 (केवल खरीफ) के लिए पहला अग्रिम अनुमान पिछले वर्ष (2021-22 खरीफ सीजन) की तुलना में धान की खेती के क्षेत्र में लगभग 3.8 लाख हेक्टेयर की कमी का संकेत देता है।
- रबी सीज़न का विस्तार: चालू रबी सीज़न में, रबी धान का रकबा पिछले वर्ष (12 जनवरी, 2023 तक) की तुलना में 6.6 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है।
- ख़रीफ़ खाद्यान्न उत्पादन: 2022-23 (केवल ख़रीफ़) के लिए पहले अग्रिम अनुमान में कुल खाद्यान्न उत्पादन 149.9 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले पाँच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के औसत ख़रीफ़ खाद्यान्न उत्पादन को पार कर गया है।
- **ख़रीफ़ चावल उत्पादन:** ख़रीफ़ धान की खेती के क्षेत्र में कमी के बावजूद, 2022-23 के लिए ख़रीफ़ चावल का अनुमानित उत्पादन 104.9 मिलियन टन है, जो पिछले पाँच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के औसत, जो 100.5 मिलियन टन था, ख़रीफ़ चावल उत्पादन से अधिक है। । **(अत: कथन 2 सही है)**

56.**c**

स्पष्टीकरण:

चयनित ख़रीफ़ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹/क्विंटल):

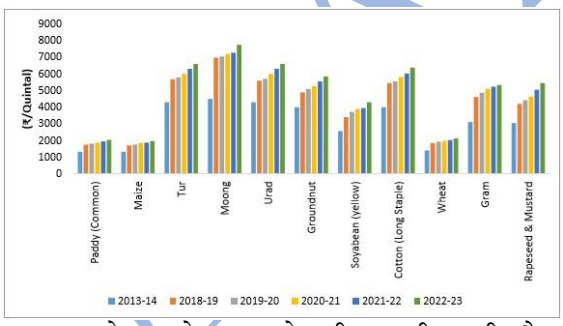

- उत्पादन लागत आश्वासन के लिए एमएसपी: 2018-19 के केंद्रीय बजट ने एक महत्वपूर्ण उपाय पेश किया जिसमें भारतीय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित किया जाएगा जो उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना होगा। **(अत: कथन 1 सही है)**
- प्रगतिशील एमएसपी कार्यान्वयन: कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से, सरकार ने सभी 22 खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में लगातार वृद्धि की है। यह वृद्धि अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत के मार्जिन के साथ निर्धारित की गई है। **(अत: कथन 2 सही है)**
- पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान: बढ़ती आहार संबंधी आदतों और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने दालों और तिलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कदम उठाए हैं। इससे इन विशिष्ट फसलों के लिए अपेक्षाकृत उच्च एमएसपी की स्थापना हुई है। **(अत: कथन 3 सही है)**

57.**b**

स्पष्टीकरण:

जैविक और प्राकृतिक खेती के लाभ:

- जैविक और प्राकृतिक खेती रसायन-मुक्त खाद्यान्न और फसलें प्रदान करती है, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाती है और पर्यावरण प्रदूषण को कम करती है।
- भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक है। **(अत: कथन 1 सही है)**
- 2021-22 तक लगभग 59.1 लाख हेक्टेयर भूमि जैविक खेती के लिए समर्पित की गई।

सिक्किम का अग्रणी जैविक प्रयास:

- **सिक्किम ने** 2010 में प्रक्रिया शुरू करते हुए स्वेच्छा से जैविक खेती को अपनाया।
- यह विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया, जिसने त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के लक्ष्यों को प्रेरित किया। **(इसलिए कथन 2 गलत है)**

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल:

- सरकार ने **दो समर्पित योजनाएँ शुरू कीं:**
- परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास (MOVCDNER)
- पीकेवीवाई को किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने पर ध्यान देने के साथ समूहों में लागू किया गया है।
- पीकेवीवाई के तहत किसानों को जैविक आदानों के लिए प्रोत्साहन सहित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- नमामि गंगे कार्यक्रम जैविक खेती के तहत एक महत्वपूर्ण भूमि क्षेत्र को कवर करता है।
- MOVCDNER एफपीओ के माध्यम से उत्तर पूर्व क्षेत्र में विशिष्ट फसलों की जैविक खेती को प्रोत्साहित करता है। **(अत: कथन 3 सही है)**

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा:

- भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) उप-योजना 2019-20 में शुरू की गई।
- बीपीकेपी शून्य-बजट प्राकृतिक खेती (जेडबीएनएफ) सहित पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को अपनाने का समर्थन करता है।
- फोकस क्षेत्रों में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, चैंपियन किसान प्रदर्शन और ऑन-फील्ड मार्गदर्शन शामिल हैं।
- बीपीकेपी ने आठ राज्यों में 4.09 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती को अपनाया है।
- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु।

58.**b**

स्पष्टीकरण:

कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund -AIF):

KUMAR'S IAS

- 2020-21 से 2032-33 तक परिचालन वाला एआईएफ, **फसल कटाई के बाद** प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों की स्थापना का समर्थन करता है। **(अत: कथन 1 गलत है)**
- यह 3% ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता जैसे लाभ प्रदान करता है **। (अत: कथन 2 सही है)**
- 2020-21 से 2025-26 के लिए ₹1 लाख करोड़ का प्रावधान आवंटित किया गया है, जिसमें ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी 2032-33 तक बढ़ाई गई है।
- एआईएफ योजना कृषि में महत्वपूर्ण निवेश की संभावनाओं को प्रदर्शित करते हुए अन्य राज्य या केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के साथ सहयोग कर सकती है। **(अत: कथन 3 सही है)**

स्वीकृत परियोजनाएँ और वित्त पोषण:

- इसकी स्थापना के बाद से, देश भर में कृषि बुनियादी ढांचे के लिए कुल ₹13,681 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
- 18,133 से अधिक परियोजनाओं को कवर किया गया है, जिसमें विविध क्षेत्र शामिल हैं:
    - 8,076 गोदाम
    - 2,788 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयाँ
    - 1,860 कस्टम हायरिंग सेंटर
    - 937 छँटाई और ग्रेडिंग इकाइयाँ
    - 696 कोल्ड स्टोर परियोजनाएं
    - 163 परख इकाइयाँ (assaying units)
    - लगभग 3613 अन्य फसलोत्तर प्रबंधन परियोजनाएँ और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियाँ।

59.**d**

स्पष्टीकरण:

जलवायु-स्मार्ट खेती पद्धतियाँ:

- जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को धीरे-धीरे अपनाया जा रहा है, जिसमें सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाना भी शामिल है।
- किसानों को स्थानीय ग्रिड में अतिरिक्त सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली का योगदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
- मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन के उपयोग का उपयोग करके फसल उपज भविष्यवाणी मॉडल को लागू करने की पहल चल रही है।
- स्मार्ट कृषि पद्धतियाँ फसल विविधीकरण को बढ़ावा देती हैं, जिससे किसान पानी के लिए मानसून पर अपनी निर्भरता कम कर पाते हैं। **(इसलिए विकल्प d) अन्य की तुलना में अधिक उपयुक्त है)**

एग्रीटेक स्टार्ट-अप:

- भारत 1,000 से अधिक एग्रीटेक स्टार्ट-अप के संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र का दावा करता है।

- ये स्टार्ट-अप किसानों को उनकी कृषि तकनीकों और प्रथाओं को बढ़ाने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

60.**c**

स्पष्टीकरण:

संबद्ध क्षेत्र: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विकास:

- पशुधन, वानिकी और लॉगिंग, तथा मछली पकड़ने और जलीय कृषि, जिन्हें सामूहिक रूप से संबद्ध क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है, उत्तरोत्तर मजबूत विकास के स्रोत और बेहतर कृषि आय के संभावित रास्ते के रूप में उभर रहे हैं।

पशुधन क्षेत्र की प्रगति:

- 2014-15 से 2020-21 तक, पशुधन क्षेत्र ने 7.9% (स्थिर कीमतों पर) की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) प्रदर्शित की है।
- स्थिर मूल्यों पर कुल कृषि सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में इसका योगदान 2014-15 में 24.3% से बढ़कर 2020-21 में 30.1% हो गया है। **(अत: कथन 1 सही है)**

मत्स्य पालन क्षेत्र का विकास:

- 2016-17 से, मत्स्य पालन क्षेत्र ने लगभग 7% की औसत वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखी है।
- कुल कृषि जीवीए में इसकी हिस्सेदारी लगभग 6.7% है। **(अत: कथन 2 सही है)**

संबद्ध क्षेत्रों में उच्च वृद्धि के निहितार्थ:

- फसल क्षेत्र की तुलना में संबद्ध क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि का महत्वपूर्ण प्रभाव है, जो समग्र कृषि सकल मूल्य वर्धित में पूर्व के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। **(अत: कथन 3 सही है)**

संबद्ध क्षेत्रों की समिति की मान्यता:

- किसानों की आय दोगुनी करने पर समिति (डीएफआई, 2018) संबद्ध क्षेत्रों के बढ़ते महत्व को स्वीकार करती है।
- डेयरी, पशुधन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और बागवानी को उच्च विकास इंजन के रूप में चिन्हित किया गया है।
- समिति संबद्ध क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रित नीति ढांचे और संबंधित सहायता प्रणाली की सिफारिश करती है।

61.**a**

स्पष्टीकरण:

कृषि सब्सिडी के प्रकार:

स्पष्ट इनपुट सब्सिडी (Explicit Input Subsidies):

- उत्पादन से पहले इनपुट लागत कम करने के लिए किसानों को विशेष लागत सब्सिडी प्रदान की गई।
- मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों पर लक्षित है जो गुणवत्तापूर्ण इनपुट खरीदने के लिए संघर्ष करते हैं।
- आधुनिक प्रौद्योगिकियों को शामिल करके उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य। **(अत: कथन 1 सही है)**

अंतर्निहित इनपुट सब्सिडी (Implicit Input Subsidies):

- सब्सिडी जो प्रत्यक्ष भुगतान नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इनपुट कीमतों को प्रभावित करती है।
- उदाहरण: कम बिजली लागत जो उत्पादन इनपुट की लागत को प्रभावित करती है।

आउटपुट सब्सिडी:

- व्यापार प्रतिबंधों के कारण घरेलू बाजार में कीमतें अपने स्तर से ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं।

भुगतान विधि के आधार पर वर्गीकरण:

प्रत्यक्ष सब्सिडी: इसमें प्राप्तकर्ताओं को सीधे हस्तांतरण या भुगतान शामिल है।

अप्रत्यक्ष सब्सिडी: इसमें प्रत्यक्ष भुगतान शामिल नहीं है, बल्कि कम कीमत, क्रेडिट, बीमा आदि जैसे लाभ मिलते हैं।

अप्रत्यक्ष सब्सिडी:

- कोई सीधा नकद हस्तांतरण नहीं; इसके बजाय, मूल्य में कमी, कल्याण सहायता, किफायती ऋण इत्यादि जैसे तंत्रों के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है।
- अक्सर इनपुट उपयोग से जुड़ा होता है और इनपुट भुगतान की मात्रा से निकटता से संबंधित होता है।
- उदाहरणों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कर कोड समायोजन और गैर-नकद लाभ शामिल हैं।
- भारत की जीडीपी का लगभग 2% प्रतिनिधित्व करता है।
- अप्रत्यक्ष सब्सिडी के उदाहरण **: (इसलिए कथन 2 गलत है)**
    - एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) सब्सिडी: उत्पाद की कीमतें बाजार दरों से कम निर्धारित करना।
    - उर्वरक सब्सिडी: किसानों की सहायता के लिए उर्वरकों की लागत कम करना।
    - क्रेडिट सब्सिडी: कम ब्याज दरों पर कृषि ऋण की पेशकश।
    - सिंचाई सब्सिडी: किफायती सिंचाई विकल्पों के लिए सहायता प्रदान करना।

62.**c**

स्पष्टीकरण:

एकीकृत किसान सेवा मंच (यूएफएसपी)

यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म (यूएफएसपी) कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा, एप्लिकेशन और टूल्स के साथ एक एकीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो देश भर में कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सार्वजनिक और निजी आईटी प्रणालियों के बीच निर्बाध अंतरसंचालनीयता की सुविधा प्रदान करता है। **(अत: कथन 1 सही है)**

यूएफएसपी की भूमिकाओं में शामिल हैं:

- केंद्रीय एजेंसी की भूमिका: ई-भुगतान में यूपीआई की तुलना में, यूएफएसपी कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- पंजीकरण सुविधा: यूएफएसपी सेवा प्रदाताओं (सार्वजनिक और निजी) और किसान सेवाओं दोनों के लिए पंजीकरण सक्षम बनाता है। **(अत: कथन 2 सही है)**
- सेवा नियमों का प्रवर्तन: यूएफएसपी सेवा वितरण प्रक्रिया के दौरान आवश्यक नियमों और मान्यताओं को लागू करता है।
- मानक रिपॉजिटरी: यह सभी प्रासंगिक मानकों, एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस) और प्रारूपों के लिए एक रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करता है।
- डेटा विनिमय माध्यम: यूएफएसपी विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के बीच डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान करता है, जिससे किसानों को व्यापक सेवा वितरण सुनिश्चित होता है। **(अत: कथन 3 सही है)**

63.**b**

स्पष्टीकरण:

सिंचाई के तरीके:

सतही सिंचाई (Surface Irrigation):

- भूमि की सतह पर पानी अलग-अलग समय पर अलग-अलग मात्रा में बहता है।
- तकनीकें: बेसिन, सीमा, नाली, अनियंत्रित बाढ़।

बेसिन सिंचाई:

- चावल, जलमग्न जड़ों वाली फसलों के लिए उपयुक्त।
- लंबे समय तक नमी के प्रति असहिष्णु फसलों के लिए आदर्श नहीं है।

कुंड/ नाली सिंचाई (Furrow Irrigation):

- खाइयाँ पंक्तियों के बीच पानी ले जाती हैं।
- पंक्ति और पेड़ वाली फसलों के लिए उपयुक्त, पौधों के सीधे संपर्क से बचा जाता है। **(अत: जोड़ी 1 सही सुमेलित है)**

सीमा सिंचाई (Border Irrigation):

- खेत बाँट दिए जाते हैं, मेड़ों के बीच की पट्टियाँ जलमग्न की जाती हैं।
- लंबे खेतों के लिए बेसिन सिंचाई का विस्तार।

अनियंत्रित बाढ़:

- पानी बिना नियंत्रण के फैल जाता है।

KUMAR'S IAS

- चरागाहों के लिए उपयुक्त; सस्ता **(अतः जोड़ी 3 ग़लत सुमेलित है)**

स्प्रिंकलर सिंचाई:

- पानी का छिड़काव, वर्षा जैसा।
- असमान भूमि, उथली मिट्टी के लिए आदर्श; धान को छोड़कर कई फसलें। **(अतः जोड़ी 2 सही सुमेलित है)**

कुआँ एवं ट्यूबवेल सिंचाई:

- भारत में लोकप्रिय, हरित क्रांति में योगदान दिया।
- प्रकार: उथले, गहरे, ट्यूबवेल।

नहर सिंचाई:

- महत्वपूर्ण स्रोत, विशेषकर उत्तरी मैदानी इलाकों में।
- प्रकार: बाढ़ (बरसात का मौसम), बारहमासी (वर्ष भर)।

टैंक सिंचाई:

- छोटे-छोटे बांध वर्षा जल को संग्रहित करते हैं।
- विभिन्न भारतीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण।

ड्रिप सिंचाई:

- कुशल, सीधे पानी और पोषक तत्व पहुंचाता है।
- कटाव, खरपतवार को कम करता है; उच्च प्रारंभिक लागत

सर्ज सिंचाई (Surge Irrigation):

- स्पंदित जल आपूर्ति, तेज़ अग्रिम पंक्ति।

खाई सिंचाई (Ditch Irrigation):

- खाइयों में पौधों की पंक्तियाँ, नहरों के माध्यम से पानी।

उप-सिंचाई (Sub-Irrigation):

- नीचे से दिया गया पानी, पानी और पोषक तत्वों का संरक्षण करता है।
- संसाधनों का संरक्षण करते हुए उच्च जल स्तर वाली फसलों में उपयोग किया जाता है।

64.**a**

स्पष्टीकरण:

KUMAR'S IAS

सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई निधि (MIF):

पहल अनुमोदन:

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने नाबार्ड में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत एक समर्पित एमआईएफ के लिए 5,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष को मंजूरी दी। **(इसलिए कथन 1 गलत है)**

आवंटन और ऋण विस्तार:

- एमआईएफ आवंटन: 2018-19 में 2,000 करोड़ रु.- 2019-20 में 3,000 करोड़ रु.।
- नाबार्ड एमआईएफ के तहत राज्य सरकारों को ऋण देता है।
- प्रस्तावित उधार दर: नाबार्ड की धन जुटाने की लागत से 3% कम।

कर्ज का भुगतान:

- राज्य दो साल की छूट अवधि सहित कुल सात वर्षों में ऋण चुकाते हैं।
- ब्याज छूट का अनुमानित वित्तीय निहितार्थ: लगभग रु. 750 करोड़

फ़ायदे:

- एमआईएफ प्रभावी ढंग से पीएमकेएसवाई के प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक का पूरक है।
- नवीन सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं का उपयोग करके लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है। **(अत: कथन 2 सही है)**
- राज्यों को संसाधन जुटाने, अतिरिक्त सब्सिडी कार्यान्वयन और वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करता है।

कार्यान्वयन रणनीति:

- राज्य पीपीपी मोड सहित एकीकृत सिंचाई परियोजनाओं के लिए एमआईएफ तक पहुंच बनाते हैं।
- टॉप-अप सब्सिडी के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई का समर्थन करता है।
- राज्य गारंटी या संपार्श्विक के साथ किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों, राज्य स्तरीय एजेंसियों के लिए उपलब्ध है।
- नवीन क्लस्टर-आधारित सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं के लिए सुलभ निधि।

सलाहकार और संचालन समितियाँ:

- सलाहकार समिति नीति निर्देश, समन्वय और परियोजना निगरानी प्रदान करती है।
- संचालन समिति राज्य परियोजनाओं की जांच और अनुमोदन करती है।

कवरेज:

- सूक्ष्म सिंचाई निधि (MIF) पूरे देश को कवर करती है।
- सूक्ष्म सिंचाई अपनाने में पिछड़े राज्यों को निधि से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

KUMAR'S IAS

- राज्य-संचालित समुदाय और नवीन परियोजनाएं सूक्ष्म सिंचाई कवरेज का विस्तार करती हैं। **(अत: कथन 3 सही है)**

65.**b**

स्पष्टीकरण:

A. भारत में चावल की खेती और जलवायु:

भारत चावल की खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके लिए पर्याप्त क्षेत्र समर्पित हैं।

ऐतिहासिक उत्पत्ति:

- इंडिका चावल (Indica rice) की प्रारंभिक खेती पूर्वी हिमालय की तलहटी में हुई, जो दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली हुई थी।
- जैपोनिका किस्म (Japonica variety) को दक्षिणी चीन में जंगली चावल से अपनाया गया, जिसे भारत में लाया गया।

जंगली चावल की दृढ़ता:

- बारहमासी जंगली चावल असम और नेपाल में पाया जाता है।
- उत्तरी मैदानी इलाकों में इसे अपनाने के बाद लगभग 1400 ईसा पूर्व दक्षिणी भारत में इसका उदय हुआ।

जलवायु विविधता:

- चावल पूरे भारत में अलग-अलग ऊंचाई और जलवायु में उगता है।
- 8 से 35°N अक्षांशों, समुद्र तल से 3000 मीटर तक खेती की जाती है।

जलवायु संबंधी आवश्यकताएँ:

- चावल गर्म, आर्द्र वातावरण की मांग करता है।
- उच्च आर्द्रता, लंबे समय तक धूप और लगातार पानी की आपूर्ति में फलता-फूलता है।
- 150-300 सेमी वर्षा और गहरी चिकनी और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। **(अत: कथन 1 सही है)**
- तापमान की रेंज:
    - औसत तापमान की आवश्यकता: 21 से 37°C. **(इसलिए कथन 2 गलत है)**
    - अधिकतम तापमान सहनशीलता: 40 से 42°C

बी. भारत में गेहूं की खेती और अनुकूलनशीलता:

- गेहूं भारत की प्राथमिक खाद्य फसल के रूप में कार्य करता है।
- भारतीय गेहूं ज्यादातर नरम/मध्यम-कठोर, मध्यम प्रोटीन वाला होता है, जो अमेरिकी कठोर सफेद गेहूं के समान होता है।
- मध्य और पश्चिमी भारत का गेहूं कठोर होता है, इसमें प्रोटीन और ग्लूटेन की मात्रा अधिक होती है।
- भारत में 1.0-1.2 मिलियन टन ड्यूरम गेहूं का उत्पादन होता है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में।

KUMAR'S IAS

- बाज़ार की चुनौतियाँ भारतीय ड्यूरम गेहूं के पृथक विपणन को रोकती हैं।

गेहूं परिदृश्य का विकास:

- 1961 में, सरकार ने फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए मूल्यांकन शुरू किया।
- सरकारी प्रयासों और 'हरित क्रांति' के कारण, भारत आयात से गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर स्थानांतरित हो गया।

अनुकूलनशीलता और जलवायु:

- गेहूं सुदूर उत्तर (60 डिग्री अक्षांश से परे) सहित उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और ठंडे क्षेत्रों में पनपता है।
- अत्यधिक ठंड और बर्फबारी को सहन करता है, वसंत ऋतु में विकास फिर से शुरू करता है।
- 3300 मीटर तक समुद्र तल के लिए उपयुक्त।
- तापमान और अंकुरण:
    - इष्टतम अंकुरण तापमान: 20-25°C
    - बुआई के बाद बारिश से अंकुरण में बाधा आती है, अंकुरों में झुलसा रोग को बढ़ावा मिलता है।
    - गर्म, नम जलवायु के लिए अनुपयुक्त।

चुनौतियाँ और मौसमी परिस्थितियाँ:

- अत्यधिक उच्च/निम्न तापमान, शीर्ष की ओर बढ़ने (heading) और पुष्पन अवस्था के दौरान सूखा हानिकारक है।
- बादल, आर्द्र परिस्थितियाँ रस्ट के हमले को प्रोत्साहित करती हैं।
- भारत में मुख्य रूप से रबी (सर्दी) मौसम की फसल। **(अतः कथन 3 सही है)**

66.**a**

स्पष्टीकरण:

भारत में विभिन्न फसल प्रणालियाँ प्रचलित हैं:

- **मोनोक्रॉपिंग/ एकल फसल:** एक खेत में हर मौसम में केवल एक ही फसल लगाना, जो मिट्टी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। **(अतः कथन 1 सही है)**
- **फसल चक्रण:** प्रत्येक मौसम या वर्ष में खेत में उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार को बदलना, मिट्टी की संरचना, उर्वरता को बढ़ाना और खरपतवार, कीट और रोग प्रबंधन में सहायता करना। **(इसलिए कथन 2 गलत है)**
- अनुक्रमिक फसल: एक वर्ष के भीतर एक ही खेत में क्रमिक रूप से दो फसलें उगाना।
- **अंतरफसल :** एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाना।

KUMAR'S IAS

- **मिश्रित अंतरफसल:** मुख्य फसल को पंक्तियों में बोना और उनके बीच कवर फसलों की तरह अंतरफसल के बीज बोना। **(अत: कथन 3 सही है)**
- पंक्ति अंतरफसल: मुख्य फसल और अंतरफसल दोनों को अलग-अलग पंक्तियों में लगाना, मिश्रित अंतरफसल की तुलना में निराई और कटाई को आसान बनाता है।
- पट्टीदार फसल: पूरे खेत में कई फसलों की चौड़ी पट्टी बोना।

67.**c**

स्पष्टीकरण:

भारत सरकार द्वारा दलहन स्टॉक की निगरानी:

- मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण संभावित उपज में कमी की चिंताओं के जवाब में, भारत सरकार ने देश के भीतर दाल स्टॉक स्तर की निगरानी शुरू कर दी है।
- भारत का दाल उत्पादन: भारत विश्व के सबसे बड़े दाल उत्पादक का खिताब रखता है, जो वैश्विक उत्पादन में 25% का योगदान देता है। **(अत: कथन 1 सही है)**
- वर्ष 2021-22 के लिए दलहन उत्पादन कुल 27.3 मिलियन टन था, और इस वर्ष का लक्ष्य 29.55 मिलियन टन निर्धारित किया गया था।
- दाल की खपत: भारत दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो वैश्विक खपत का 27% है।
- दाल आयात: इसके अतिरिक्त, भारत दालों का सबसे बड़ा आयातक है, जो वैश्विक दाल व्यापार का 14% कवर करता है। **(अत: कथन 3 सही है)**
- प्रमुख दलहनी फसलें: भारत में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण दलहनी फसलों में चना (41% हिस्सेदारी), तुअर (16% हिस्सेदारी), उड़द और मूंग शामिल हैं।
- शीर्ष उत्पादक राज्य: राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक भारत में दालों की खेती के लिए अग्रणी राज्य हैं।
- भौगोलिक स्थितियाँ: ये फसलें 20-27°C तापमान और लगभग 25-60 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में फलती-फूलती हैं। आदर्श मिट्टी का प्रकार रेतीली-दोमट है।
- फसल पैटर्न: मिट्टी के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए दलहनी फसलों की खेती अक्सर अन्य फसलों के साथ चक्र में की जाती है। **(अत: कथन 2 सही है)**
- मध्याह्न भोजन के लिए राज्य दालों की खरीद: भारत सरकार ने राज्यों को पीएम-पोषण कार्यक्रम के तहत मध्याह्न भोजन के लिए NAFED से दालें खरीदने की सलाह दी है।
- निर्देश के पीछे का कारण: यह निर्देश NAFED के माध्यम से दालों के बफर स्टॉक बनाए रखने की सरकार की प्रथा से उपजा है।
- सरकार राज्यों से बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने और छात्र भोजन के लिए रियायती दरें प्राप्त करने के लिए NAFED से स्रोत प्राप्त करने की मांग कर रही है।

- सरकारी पहल: भारत ने दलहन की खेती को समर्थन देने और उत्पादन बढ़ाने के लिए दलहन के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, दलहन विकास योजना और दलहन पर तकनीकी मिशन लागू किया है।

68.**c**

स्पष्टीकरण:

संशोधित घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश:

- प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अद्यतन घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है।
- ये दिशानिर्देश ओएनजीसी/ओआईएल, एनईएलपी ब्लॉकों और प्री-एनईएलपी ब्लॉकों के नामांकन क्षेत्रों से उत्पादित गैस पर लागू होते हैं, पीएससी सरकार की कीमत अनुमोदन निर्धारित करती है।
- मासिक अधिसूचना के अधीन, मूल्य निर्धारण फॉर्मूला भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत के 10% पर निर्धारित किया गया है।
- नामांकन ब्लॉकों से ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा उत्पादित गैस में एक फर्श और छत के साथ एक प्रशासित मूल्य तंत्र (एपीएम) होगा। नए कुओं या हस्तक्षेपों को एपीएम मूल्य पर 20% प्रीमियम प्राप्त होगा।
- विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी

नए दिशानिर्देशों के उद्देश्य:

- दिशानिर्देशों का उद्देश्य घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए स्थिर मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना और **उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करते हुए उत्पादकों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करना है**।
- सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.5% से बढ़ाकर 15% करना है।
- सुधारों का उद्देश्य प्राकृतिक गैस की खपत को बढ़ावा देना, उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों में योगदान देना और शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ना है। **(अत: कथन 1 सही है)**

उपभोक्ता संरक्षण और मूल्य में कमी:

- ये सुधार उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय गैस कीमतों में बढ़ोतरी से बचाने की सरकार की पहल को जारी रखते हैं।
- शहरी गैस वितरण क्षेत्र में घरेलू गैस का आवंटन उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया गया है।
- इससे घरों के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) और परिवहन के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की कीमतें कम हो जाएंगी। **(अत: कथन 2 सही है)**
- कम कीमतों से उर्वरक सब्सिडी का बोझ कम होगा और घरेलू बिजली क्षेत्र को समर्थन मिलेगा।

निवेश और उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन:

KUMAR'S IAS

- नए कुओं के लिए न्यूनतम कीमतें और प्रीमियम पेश करके, सुधार ओएनजीसी और ओआईएल को अपस्ट्रीम क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- इससे प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम होगी।

पिछले दिशानिर्देशों से परिवर्तन:

- पिछले मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश महत्वपूर्ण समय अंतराल और अस्थिरता के साथ चार गैस ट्रेडिंग केंद्रों पर निर्भर थे।
- संशोधित दिशानिर्देश उद्योग प्रथाओं और वैश्विक तरलता के अनुरूप कीमतों को कच्चे तेल से जोड़ते हैं।
- पिछले महीने की भारतीय क्रूड बास्केट की कीमत एपीएम गैस की कीमतें निर्धारित करेगी।

69.**b**

स्पष्टीकरण:

पीएम-कुसुम योजना की समय सीमा विस्तार:

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने पीएम-कुसुम के तहत ग्रामीण भारत में 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने की समय सीमा मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। (इसलिए कथन **1 सही है)**
- पीएम-कुसुम की शुरुआत 2019 में एमएनआरई द्वारा की गई थी।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड सौर पंप स्थापित करना और जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करना है।

पीएम-कुसुम के घटक:

- 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्राउंड-माउंटेड ग्रिड-कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।
- 20 लाख सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना।
- 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर पंपों में परिवर्तित करना।

पीएम-कुसुम के उद्देश्य:

- किसानों को अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने और इसे ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाना।
- किसानों को अतिरिक्त सौर ऊर्जा बेचने की अनुमति देकर उनकी आय बढ़ाएँ। **(अत: कथन 2 सही है)**
- **योजना में शहरी क्षेत्रों के बारे में कभी बात नहीं की गई (इसलिए कथन 3 गलत है)**

योजना का महत्व:

- अतिरिक्त सौर ऊर्जा बेचकर, ग्रामीण विद्युतीकरण बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना।
- कुशल भूजल उपयोग को बढ़ावा देने और डीजल से संक्रमण को बढ़ावा देकर जलवायु प्रभाव को रोकने में सहायता करता है।
- 32 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जन में संभावित कमी।

- सौर परियोजना स्थापना, रखरखाव और संचालन में रोजगार के अवसर पैदा करता है।
- ग्रामीण समुदायों को ऊर्जा स्वायत्तता और नियंत्रण के साथ सशक्त बनाना।

संबद्ध चुनौतियाँ:

- उच्च परियोजना लागत और सीमित वित्तपोषण के कारण वित्तीय और तार्किक चुनौतियाँ।
- सब्सिडी वाली बिजली के कारण जल स्तर में गिरावट, जल संसाधनों पर असर।
- ग्रिड एकीकरण और तकनीकी स्थिरता संबंधी चिंताओं के लिए नियामक बाधाएँ।

भविष्य की दिशाएं:

- सफलता केंद्र, राज्यों और हितधारकों के बीच आम सहमति पर निर्भर करती है।
- जल और ऊर्जा संरक्षण के लिए किसानों को ड्रिप सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- प्रतिस्पर्धी बेंचमार्क मूल्य निर्धारण और कार्यान्वयन चुनौतियों के समाधान के माध्यम से योजना का आकर्षण।

70.**c**

स्पष्टीकरण:

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) :

- एनआईपी को परियोजना की तैयारी बढ़ाने तथा आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे दोनों में निवेश आकर्षित करने के लिए पेश किया गया था, जो वित्त वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। (इसलिए **कथन 1 सही है)**
- इसमें रोजगार, आय सृजन और समग्र आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

एनआईपी का महत्व:

- $5 ट्रिलियन का लक्ष्य: एनआईपी बुनियादी ढांचे में लगभग $1.4 ट्रिलियन (100 लाख करोड़ रुपये) के निवेश की आवश्यकता के कारण $5 ट्रिलियन जीडीपी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है।
- समावेशी विकास: सतत और समावेशी व्यापक-आधारित विकास के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे की समान उपलब्धता महत्वपूर्ण है।
- ख़राब बुनियादी ढांचे को संबोधित करना: विभिन्न क्षेत्रों में कमियों ने देश की विकास क्षमता में बाधा उत्पन्न की है।
- निवेशकों का विश्वास बढ़ाना: एनआईपी सावधानीपूर्वक परियोजना की तैयारी, सक्रिय निगरानी, तनाव जोखिम को कम करने और एनपीए को कम करने के माध्यम से निवेशकों के विश्वास में सुधार करता है।

एनआईपी के उद्देश्य:

KUMAR'S IAS

- सामाजिक समावेशिता: एनआईपी सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देते हुए व्यवसायों, रोजगार, बेहतर जीवन स्तर और बुनियादी ढांचे तक समान पहुंच को बढ़ावा देता है।
- आर्थिक गतिविधि और राजकोषीय स्थान: यह आर्थिक गतिविधि को संचालित करता है, सरकारी राजस्व को बढ़ाकर राजकोषीय क्षमता का विस्तार करता है, और उत्पादक क्षेत्रों पर खर्च को अनुकूलित करता है।
- नियोजित विकास: एनआईपी परियोजना नियोजन, **कम आक्रामक बोली** और निवेशक विश्वास के माध्यम से वित्त तक उन्नत पहुंच सुनिश्चित करता है। **(इसलिए कथन 2 गलत है)**

एनआईपी का महत्व:

- आर्थिक विकास: वर्तमान विकास को बनाए रखने के लिए 2030 तक आवश्यक $4.5 ट्रिलियन बुनियादी ढांचे के खर्च में तेजी लाने के लिए एनआईपी महत्वपूर्ण है।
- रोजगार और समावेशी विकास: अच्छी तरह से संरचित एनआईपी परियोजनाओं, व्यवसायों, नौकरियों, बेहतर जीवन स्थितियों और न्यायसंगत बुनियादी ढांचे तक पहुंच को जन्म देता है। **(अत: कथन 3 सही है)**
- राजकोषीय दक्षता: विकसित बुनियादी ढाँचा आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देता है, सरकार के कर आधार को बढ़ाता है, और उत्पादक डोमेन पर खर्च पर ध्यान केंद्रित करता है। **(अत: कथन 4 सही है)**
- उन्नत परियोजनाएँ: एनआईपी प्रभावी परियोजना योजना, बोली की तीव्रता में कमी, परियोजना विफलताओं को कम करना और बढ़े हुए निवेशक विश्वास के माध्यम से अधिक पूंजी पहुंच सुनिश्चित करता है।
- कृषि और ग्रामीण विकास: यह सिंचाई और ग्रामीण परियोजनाओं सहित कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाता है।
- कनेक्टिविटी: एनआईपी सड़क और रेलवे निवेश के माध्यम से ग्रामीण और राष्ट्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करता है।

एनआईपी की सीमाएँ:

- बैंकिंग तनाव: एनआईपी सुधार कर रहे बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव डाल सकता है, जिससे एनपीए की समस्याएँ और भी बदतर हो सकती हैं।
- जटिल कार्यान्वयन: एनआईपी का व्यापक स्तर जटिल कार्यान्वयन की मांग करता है और सरकारी स्तरों पर समन्वय की आवश्यकता होती है।
- भूमि अधिग्रहण चुनौतियाँ: भूमि खरीद बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने में कठिनाइयाँ पैदा करती है।
- विस्थापन और पुनर्वास: एनआईपी के परिमाण के कारण प्रभावित समुदायों के विस्थापन और पुनर्वास की चुनौतियों से निपटना आवश्यक हो गया है।

71.**b**

स्पष्टीकरण:

लॉजिस्टिक्स / रसद प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई):

- व्यापार रसद चुनौतियों और वृद्धि के अवसरों को चिन्हित करने में देशों की सहायता के लिए **विश्व बैंक** द्वारा प्रकाशित सूचकांक। **(इसलिए कथन 1 गलत है)**

- देशों को उनके व्यापार लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है।
- 2023 एलपीआई संस्करण में 139 देशों को स्थान दिया गया।
- 2023 एलपीआई ने पहले के संस्करणों के विपरीत केवल अंतरराष्ट्रीय पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें घरेलू सर्वेक्षण शामिल थे।
- एलपीआई 2023 पर सिंगापुर सर्वश्रेष्ठ रैंक वाला देश था
- भारत 2018 की तुलना में 2023 में 6 स्थान सुधरकर **38वें स्थान पर पहुंच** गया। **(इसलिए कथन 2 सही है)**

भारत के सुधार के कारण:

- बंदरगाहों को आर्थिक केंद्रों से जोड़ने वाले व्यापार-संबंधित बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी और इलेक्ट्रॉनिक बंदरगाह प्रणालियों के माध्यम से बंदरगाह उत्पादकता में वृद्धि।
- ट्रैकिंग समाधानों का कार्यान्वयन - कंटेनरों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग।
- कार्गो ट्रैकिंग से विशाखापत्तनम बंदरगाह पर रुकने का समय 32.4 से घटकर 5.3 दिन हो गया है।
- भारत में औसत कंटेनर ठहराव समय घटकर 2.6 दिन हो गया।
- भारतीय बंदरगाहों पर रुकने के समय में काफी कमी आई, जो लगभग तीन दिन तक पहुंच गई।
- केवल 0.9 दिनों के औसत टर्नअराउंड समय (टीआरटी) के साथ प्रभावशाली बंदरगाह परिचालन दक्षता।
- बंदरगाह और शिपिंग बुनियादी ढांचे, तकनीकी प्रगति और सार्वजनिक-निजी भागीदारी में निवेश का परिणाम।
- प्रमुख बंदरगाहों पर क्षमता 2015 में 871 एमएमटी से बढ़कर 2023 में 1,617 एमएमटी हो गई।
- कुल भारतीय बंदरगाह क्षमता 2015 में 1,560 एमएमटी से बढ़कर 2,600 एमएमटी से अधिक हो गई।
- प्रमुख बंदरगाहों पर पीपीपी परियोजनाओं के परिचालन मूल्य में लगभग 150% की वृद्धि, 2015 में 16,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 40,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। **(अत: कथन 3 सही है)**

72.**c**

स्पष्टीकरण:

जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी):

जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) भारतीय वित्त मंत्री द्वारा जुलाई 2014 के बजट भाषण के दौरान पेश की गई थी। इसे भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और इसे विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मिल रही है। इस परियोजना के वर्ष 2023 तक पूरा होने का अनुमान है। **(इसलिए कथन 1 सही है)**

जेएमवीपी क्या है?

- जेएमवीपी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने और सड़क और रेल की भीड़, कार्बन पदचिह्न और संसाधन की कमी को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

- IWAI, जहाजरानी मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय, परियोजना विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार है।
- इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

मुख्य उद्देश्य:

- वाराणसी और हल्दिया के बीच 3 मीटर की गहराई के साथ 1380 किमी की दूरी तय करने वाला एक नौगम्य फ़ेयरवे विकसित करना।
- अनुमानित परियोजना लागत: रु. 5369 करोड़ की लागत से छह साल में पूरा करने का लक्ष्य।

परियोजना लक्ष्य:

- पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी परिवहन का तरीका पेश करना। **(अत: कथन 2 सही है)**
- देश के भीतर कम लॉजिस्टिक लागत।
- मल्टी-मॉडल और इंटर-मॉडल टर्मिनल, नौका सेवाएं, नेविगेशन सहायता और रोल ऑन-रोल ऑफ (रो-रो) सुविधाएं स्थापित करना।
- सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देना और रोजगार पैदा करना।

पहल:

- वाराणसी में मल्टी-मॉडल टर्मिनल निर्माण (अनुमानित लागत: 169.59 करोड़ रुपये)।
- हल्दिया, पश्चिम बंगाल में मल्टी-मॉडल टर्मिनल निर्माण (लागत: 517.36 करोड़ रुपये)।
- साहिबगंज में एक मल्टी-मॉडल टर्मिनल का निर्माण (अनुमोदित लागत: 280.90 करोड़ रुपये, अक्टूबर 2016 में प्रदान किया गया)।
- फरक्का बैराज पर नए नेविगेशन लॉक का निर्माण (अनुमानित लागत: 359.19 करोड़ रुपये)।
- वाराणसी और हल्दिया के बीच नौगम्य फ़ेयरवे का विकास (1380 किमी, 3 मीटर गहराई)।
- IWAI द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड के तहत कोलकाता और पटना टर्मिनलों का विकास।
- अगस्त 2016 में हस्ताक्षरित एक अनुबंध के माध्यम से NW-1 पर नेविगेशन के लिए जहाजों को डिजाइन करना।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर नदी सूचना सेवा (आरआईएस) की स्थापना।

73.**c**

स्पष्टीकरण:

- ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डा: ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डा एक ऐसे हवाई अड्डे को संदर्भित करता है जो अविकसित भूमि पर बनाया जाता है, जो अक्सर मौजूदा शहरी क्षेत्रों से दूर होता है। इस प्रकार के हवाई अड्डे को आधुनिक मानकों को पूरा करने और भविष्य के विकास को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। **(अत: जोड़ी 1 सही सुमेलित है)**

KUMAR'S IAS

- ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा: ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा एक मौजूदा हवाई अड्डे को संदर्भित करता है जो महत्वपूर्ण नवीकरण, विस्तार या उन्नयन से गुजरता है। इस शब्द का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि हवाई अड्डे को शून्य से शुरू किए बिना और अधिक विकसित किया जा रहा है। **(अत: जोड़ी 2 सही सुमेलित है)**
- रिलीवर हवाई अड्डा: रिलीवर हवाई अड्डे प्रमुख हवाई अड्डों के पास स्थित छोटे हवाई अड्डे हैं, जिन्हें भीड़भाड़ को कम करने तथा सामान्य विमानन और छोटे विमानों के लिए अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- संयुक्त-उपयोग हवाई अड्डा: एक संयुक्त-उपयोग हवाई अड्डा वह है जो नागरिक और सैन्य संचालन दोनों को पूरा करता है। बुनियादी ढांचे और सुविधाएं नागरिक और सैन्य विमान दोनों द्वारा साझा की जाती हैं। **(अत: जोड़ी 3 सही सुमेलित है)**
- सैटेलाइट हवाई अड्डा: सैटेलाइट हवाई अड्डा एक छोटा हवाई अड्डा है जो बड़े हवाई अड्डे के लिए अतिरिक्त सुविधा के रूप में कार्य करता है। यह भीड़भाड़ को कम करने में मदद करता है और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करता है।
- गैर-टावर वाले हवाई अड्डे: गैर-टावर वाले हवाई अड्डों में हवाई यातायात नियंत्रण टावर नहीं होता है। टेकऑफ़, लैंडिंग और अन्य गतिविधियों के समन्वय के लिए पायलट रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं।
- सीप्लेन बेस: सीप्लेन बेस जल निकायों पर स्थित एक हवाई अड्डा है, जिसे सीप्लेन संचालन को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सीप्लेन पानी और रनवे दोनों पर उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं।
- स्पेसपोर्ट: स्पेसपोर्ट एक सुविधा है जो अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने और प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें अंतरिक्ष यात्रा के लिए लॉन्च पैड, नियंत्रण केंद्र और अन्य बुनियादी ढांचे शामिल हैं।

74.**d**

स्पष्टीकरण:

कवच पहल

"कवच" पहल रेल नेटवर्क पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण रेलवे सुरक्षा कार्यक्रम है। यह पहल सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और ट्रेन संचालन से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और आधुनिक तरीकों का लाभ उठाने पर केंद्रित है। "कवच" का अंग्रेजी में अनुवाद "ढाल" है, जो संभावित दुर्घटनाओं और दुर्घटनाओं के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करने के परियोजना के उद्देश्य का प्रतीक है।

कवच पहल के प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं:

- उन्नत सुरक्षा प्रौद्योगिकियाँ: इस पहल में संभावित खतरों का पता लगाने और आपात स्थिति के मामले में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ट्रैकसाइड सेंसर, सीसीटीवी कैमरे, उन्नत सिग्नलिंग सिस्टम और वास्तविक समय की निगरानी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है।
- **उन्नत बुनियादी ढाँचा:** "कवच" में रेलवे पटरियों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना शामिल है ताकि उनकी मजबूती और स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके, जिससे संरचनात्मक विफलताओं के कारण दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके। **(इसलिए 3 गलत है)**

- स्वचालित चेतावनी प्रणाली: यह पहल स्वचालित चेतावनी प्रणालियों को एकीकृत करती है, जो सड़क उपयोगकर्ताओं को आने वाली ट्रेनों के बारे में सचेत करने के लिए रोशनी, अलार्म और बाधाओं का उपयोग करती है, जिससे इन क्रॉसिंगों पर दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है।
- सुरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता: "कवच" रेलवे कर्मियों और यात्रियों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षित प्रथाओं, आपातकालीन प्रोटोकॉल और सुरक्षा दिशानिर्देशों के पालन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने पर जोर देता है।
- लक्षित उन्नयन: कार्यक्रम दुर्घटना-संभावित क्षेत्रों की पहचान करता है और जोखिमों को कम करने के लिए उचित सुरक्षा उपायों के साथ रणनीतिक रूप से उन्हें उन्नत करता है।
- **सहयोग:** "कवच" पहल में प्रभावी सुरक्षा रणनीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों, अनुसंधान संस्थानों और संबंधित हितधारकों के साथ सहयोग शामिल है। **(इसलिए 1 सही है)**
- **डेटा-संचालित दृष्टिकोण:** यह पहल पैटर्न और संभावित जोखिम कारकों की पहचान करने, सक्रिय हस्तक्षेप और केंद्रित सुरक्षा सुधारों को सक्षम करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करती है। **(अत: 2 सही है)**
- **सतत निगरानी:** सुरक्षा उपायों की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन पहल का अभिन्न अंग है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कार्यान्वित रणनीतियाँ बदलती परिस्थितियों के प्रति प्रभावी और उत्तरदायी बनी रहें। **(अत: 4 सही है)**

75.**a**

स्पष्टीकरण:

भारतीय विमानन उद्योग पर ICRA की रिपोर्ट:

- घरेलू हवाई यात्री यातायात: मई 2023 में, भारत में घरेलू हवाई यात्री यातायात लगभग 131.8 लाख तक पहुंच गया, जो अप्रैल 2023 के 128.9 लाख की तुलना में लगभग 2.3% की मामूली वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा, मई 2022 की तुलना में साल-दर-साल लगभग 15% की वृद्धि हुई। विशेष रूप से, मई 2023 में यात्री यातायात मई 2019 के पूर्व-कोविड स्तर से लगभग 8% अधिक था।
- एयरलाइंस की क्षमता तैनाती: मई 2023 के दौरान, एयरलाइंस ने मई 2022 की तुलना में लगभग 1.4% अधिक क्षमता तैनात की, जो मई 2019 में देखे गए पूर्व-कोविड स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंच गई।
- यात्री भार कारक (पीएलएफ): घरेलू विमानन उद्योग मई 2023 में लगभग 94% के अनुमानित यात्री भार कारक पर संचालित हुआ। यह मई 2022 में लगभग 83% और मई 2019 में लगभग 90% (पूर्व-कोविड स्तर) से एक महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है।
- उद्योग के सामने चुनौतियाँ: सकारात्मक रुझानों के बावजूद, घरेलू विमानन क्षेत्र को उच्च विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्यह्रास के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये कारक एयरलाइंस की लागत संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। जबकि एटीएफ की कीमतों में पिछले पांच महीनों में क्रमिक गिरावट देखी गई, लेकिन पूर्व-कोविड युग की तुलना में वे ऊंची बनी हुई हैं।
- लाभप्रदता के लिए प्रयास: एयरलाइंस इनपुट लागत में वृद्धि के अनुरूप किराया वृद्धि को समायोजित करके लाभप्रदता मार्जिन का प्रबंधन करने के लिए काम कर रही हैं। स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और इंजन के मुद्दों सहित आपूर्ति-श्रृंखला

की चुनौतियों के कारण कुछ विमानों को खड़ा करना पड़ा है, जिससे एयरलाइंस की समग्र क्षमता और नकदी प्रवाह सृजन पर असर पड़ा है।

- **घरेलू यात्री यातायात में तेजी से सुधार के कारण** भारतीय विमानन उद्योग पर आईसीआरए का आउटलुक नकारात्मक से स्थिर हो गया है। यह प्रवृत्ति वित्त वर्ष 2024 में जारी रहने की उम्मीद है। बेहतर मूल्य निर्धारण शक्ति, बेहतर पैदावार और प्रति उपलब्ध सीट किलोमीटर राजस्व - प्रति उपलब्ध सीट किलोमीटर लागत (आरएएसके-सीएएसके) प्रसार ने इस सकारात्मक दृष्टिकोण में योगदान दिया है। **(इसलिए विकल्प ए) सही है)**

76.**c**

स्पष्टीकरण:

बजट 2023-24 में बुनियादी ढाँचा विकास:

- बुनियादी ढांचे के विविध पहलू: बुनियादी ढांचे को विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण विकास उत्प्रेरक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें पारंपरिक रूप से सड़क, बंदरगाह और बिजली लाइनों जैसी भौतिक संपत्तियां शामिल हैं। हालाँकि, भारत के विकास पथ ने भौतिक विकास के साथ-साथ सामाजिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे को भी अपनाया है।
- बजट का त्रि-आयामी जोर: बजट 2023 समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तीन बुनियादी ढांचे आयामों- भौतिक, सामाजिक और डिजिटल-पर जोर देता है। इन डोमेन में रणनीतिक निवेश कनेक्टिविटी, रोजगार सृजन, निजी निवेश और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के खिलाफ लचीलेपन में तेजी लाते हैं।
- पिछला फोकस और भविष्य का दृष्टिकोण: बजट 2022-23 में बुनियादी ढांचे के निवेश के माध्यम से आर्थिक पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी गई है। आगामी बजट 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने की भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप इस जोर को जारी रखता है।
- 2023-24 में प्रस्तावित बजट आवंटन:
  - पूंजीगत व्यय प्रवृत्ति: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का पूंजीगत व्यय 2014 में 1.7% से बढ़कर 2022-23 में लगभग 2.9% हो गया।
  - बुनियादी ढाँचा आवंटन: 2023-24 के बजट में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.3%) का पर्याप्त आवंटन नामित किया गया है – जो 2019 से तीन गुना वृद्धि है। (इसलिए कथन 1 सही है **)**
- सबसे बड़ा सेक्टर आवंटन:
  - रेल मंत्रालय: 2.4 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड-उच्च आवंटन, 2013-14 के आवंटन का लगभग नौ गुना। **(अत: कथन 2 सही है)**
  - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय: बजट 36% बढ़कर लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
- राज्यों को बढ़ावा: केंद्र राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के एक साल के विस्तार के साथ अपने प्रत्यक्ष पूंजी निवेश को पूरक बनाता है। यह रणनीति 1.3 लाख करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण संवर्धित परिव्यय के साथ बुनियादी ढांचे के खर्च और पूरक नीतिगत कार्रवाइयों को प्रोत्साहित करती है। इसका परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शहरी और पेरी-शहरी बुनियादी ढांचे का विकास है।

- पीएम आवास योजना: पीएम आवास योजना के लिए आवंटन में 66% की वृद्धि न केवल ग्रामीण श्रमिकों के लिए आवास प्रदान करेगी बल्कि रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगी।

77.**a**

स्पष्टीकरण:

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस):

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) COVID-19 महामारी के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को समर्थन देने के लिए शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एक महत्वपूर्ण घटक है। आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई यह योजना भौतिक, सामाजिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देती है। मई 2020 में लॉन्च किया गया, ECLGS समय के साथ विकसित और विस्तारित हुआ है, जो मई 2021 में ECLGS 4.0 की शुरुआत के साथ है। यह नवीनतम संस्करण ऑन-साइट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों के लिए सहायता प्रदान करके स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को लक्षित करता है और 7.5 % की अधिकतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। योजना का विकास महामारी से उत्पन्न उभरती चुनौतियों का समाधान करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के रणनीतिक प्रयास को दर्शाता है।

ईसीएलजीएस की मुख्य विशेषताएं

- एमएसएमई और मुद्रा उधारकर्ताओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त फंडिंग। **(अत: कथन 1 सही है)**
- आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा
- गारंटीशुदा आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) सुविधा बढ़ाई गई।
- घोषणा से 31 अक्टूबर, 2020 (बाद में विस्तारित) तक ऋण के लिए लागू।
- 3 लाख करोड़ रुपये या 3 सितंबर, 2021 तक की गारंटी जारी की गई।
- 31 दिसंबर, 2021 तक संवितरण की अनुमति।

ईसीएलजीएस के उद्देश्य

- ऋण देने वाली संस्थाओं को 100% गारंटी कवरेज प्रदान करना। **(अत: कथन 2 सही है)**
- एमएसएमई और मुद्रा उधारकर्ताओं के लिए वित्त पोषण तक पहुंच बढ़ाना।
- आर्थिक संकट को कम करना, कम लागत वाले ऋण की पेशकश करना।
- विनिर्माण को फिर से शुरू करना और परिचालन देनदारियों को बढ़ावा देना।

पात्रता मापदंड

- 250 करोड़ रुपये तक का कारोबार (वित्त वर्ष 2019-20), 50 करोड़ रुपये तक बकाया ऋण (29 फरवरी, 2020)। **(इसलिए कथन 3 गलत है)**
- जीईसीएल बकाया क्रेडिट का 20% तक क्रेडिट करता है (29 फरवरी, 2020)।
- अधिकतम ऋण राशि: रु. 5 करोड़

अवधि एवं ब्याज दरें

- आरंभिक 4 वर्ष की ऋण अवधि, 1 वर्ष की अधिस्थगन।
- ब्याज दरों की सीमा: बैंकों के लिए 9.25%, एनबीएफसी के लिए 14%
- एनसीजीटीसी गारंटी शुल्क नहीं लेता है।

विस्तार: ईसीएलजीएस 4.0

- मई 2021: ईसीएलजीएस 4.0 पेश किया गया।
- हेल्थकेयर सेक्टर को 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर 100% गारंटी कवर, 7.5% ब्याज।
- पात्र उधारकर्ताओं को 5 साल का कार्यकाल मिलता है।
- पात्र उधारकर्ताओं को ईसीएलजीएस 1.0 के तहत अतिरिक्त सहायता।
- ईसीएलजीएस 3.0 के तहत 500 करोड़ रुपये की ऋण सीमा बंद कर दी गई।
- अधिकतम अतिरिक्त सहायता 40% या 200 करोड़ रु. तक सीमित है।

नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बारे में

- कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 2014 में स्थापित।
- भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में।
- भूमिका: क्रेडिट गारंटी कार्यक्रम डिज़ाइन करना, ऋण जोखिम साझा करना, वित्तीय पहुंच की सुविधा प्रदान करना।

78.**c**

स्पष्टीकरण:

मानव विकास सूचकांक (HDI)

- मानव विकास का महत्व: सामाजिक उन्नति के लिए मानव विकास महत्वपूर्ण है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव और रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसी चुनौतियों ने वैश्विक विकास रुझानों को प्रभावित किया है।
- मानव विकास में वैश्विक गिरावट: महामारी और संघर्ष प्रभावों के जवाब में, वैश्विक मानव विकास सूचकांक (HDI) में गिरावट आई है। यूएनडीपी ने बताया कि लगभग 90% देशों में 2020 या 2021 में एचडीआई मूल्यों में कमी देखी गई, जो वैश्विक मानव विकास में 32 साल की रुकावट को दर्शाता है। **(अतः कथन 1 सही है)**
- भारत की एचडीआई रैंकिंग: 2021/2022 एचडीआई रिपोर्ट में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर है। 2021 में इसका एचडीआई मान 0.633 है जो इसे 2019 में 0.645 से नीचे मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखता है। हालांकि, भारत का एचडीआई दक्षिण एशिया के औसत से अधिक है और सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में निवेश के कारण 1990 के बाद से लगातार ऊपर की ओर रुझान दिखा है। **(अतः कथन 2 सही है)**
- भारत में लैंगिक असमानता: भारत का लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) 2021 में 0.490 था, जो विश्व स्तर पर 122वें स्थान पर था। यह स्कोर दक्षिण एशिया के GII (0.508) से बेहतर और विश्व औसत (0.465) के करीब है। ये

आंकड़े समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा और लिंग-उत्तरदायी विकास नीतियों को बढ़ावा देने में सरकार के प्रयासों को दर्शाते हैं।

Table VI.2: India's position and trends in the Global HDI 2021

	HDI 2021		HDI Rank 2020	Life expectancy at birth (years)	Expected years of schooling (years)	Mean years of schooling (years)	Gross national income per capita (2017 PPP $)
	Rank	Value					
Switzerland	1	0.962	3	84.0	16.5	13.9	66,933
Norway	2	0.961	1	83.2	18.2	13.0	64,660
United Kingdom	18	0.929	17	80.7	17.3	13.4	45,225
Japan	19	0.925	19	84.8	15.2	13.4	42,274
United States	21	0.921	21	77.2	16.3	13.7	64,765
China	79	0.768	82	78.2	14.2	7.6	17,504
Brazil	87	0.754	86	72.8	15.6	8.1	14,370
South Africa	109	0.713	102	62.3	13.6	11.4	12,948
Indonesia	114	0.705	116	67.6	13.7	8.6	11,466
India	**132**	**0.633**	**130**	**67.2**	**11.9**	**6.7**	**6,590**
South Asian region		0.632		67.9	11.6	6.7	6,481
World average		0.732		71.4	12.8	8.6	16,752

Source: 2021/2022 Human Development Report, UNDP

79.**a**

स्पष्टीकरण:

ई-श्रम पोर्टल और श्रमिक की गरिमा:

- श्रमिक की गरिमा बढ़ाने पर सरकार के फोकस में श्रमिकों के हितों की रक्षा करना तथा **संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कल्याण को बढ़ावा देना शामिल है। (इसलिए कथन 1 गलत है)**
- श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) ने असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए एक मंच, ई-श्रम पोर्टल शुरू किया है ।
- यह डेटाबेस आधार के माध्यम से सत्यापित होता है और नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक पृष्ठभूमि, कौशल आदि जैसे महत्वपूर्ण विवरण एकत्र करता है।
- पोर्टल का उद्देश्य रोजगार क्षमता में सुधार करना और प्रवासियों, गिग श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ पहुंचाना है।

ई-श्रम पोर्टल का महत्व और दायरा:

- ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों के लिए पहला राष्ट्रीय डेटाबेस बनाता है, जिसमें प्रवासी मजदूरों, निर्माण श्रमिकों, गिग श्रमिकों आदि जैसी विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। (**इसलिए कथन 2 सही है)**
- एनसीएस और एएसईईएम पोर्टल के साथ पोर्टल का एकीकरण सेवा प्रावधान और समर्थन को सुव्यवस्थित करता है।

पंजीकरण और जनसांख्यिकी:

- 31 दिसंबर, 2022 तक, ई-श्रम पोर्टल ने 28.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को सफलतापूर्वक पंजीकृत किया था।

- महिला पंजीकरण कुल का 52.8% था, और 18-40 वर्ष के आयु वर्ग का पंजीकरण 61.7% था।
- राज्य-वार वितरण से पता चला कि उत्तर प्रदेश (29.1%), बिहार (10.0%), और पश्चिम बंगाल (9.0%) सभी पंजीकरणों में से लगभग आधे के लिए उत्तरदायी हैं।

क्षेत्रवार वितरण:

- अधिकांश पंजीकरण **कृषि क्षेत्र से आए**, जिसमें कुल का 52.4% शामिल है। **(इसलिए कथन 3 गलत है)**
- घरेलू और घरेलू श्रमिकों ने पंजीकरण में 9.8% का योगदान दिया, जबकि निर्माण श्रमिकों का योगदान 9.1% था।

80.**d**

स्पष्टीकरण:

राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना:

- जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया, एनसीएस विविध रोजगार और करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाला एक एकीकृत मंच है।
- इसका उद्देश्य नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच अंतर को पाटना तथा प्रशिक्षण और करियर मार्गदर्शन प्रदान करना है। **(इसलिए विकल्प d) सही है)**
- एनसीएस एक ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से नौकरी मेलों की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें मॉडल कैरियर केंद्रों, नोडल अधिकारियों, नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को शामिल किया जाता है।

पंजीकरण और गतिविधि सांख्यिकी:

- 5 जनवरी, 2023 तक, एनसीएस में 2.8 करोड़ नौकरी चाहने वालों और 6.8 लाख नियोक्ताओं का पंजीकरण हुआ है।
- 2.5 लाख सक्रिय रिक्तियां और 1.2 करोड़ कुल रिक्तियां जुटाईं।
- परियोजना के ढांचे के भीतर 9,100 से अधिक नौकरी मेलों का आयोजन किया गया।

साझेदारी और प्रशिक्षण पहल:

- NCS ने मुफ्त ऑनलाइन/ऑफ़लाइन "कैरियर कौशल" प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिजीसक्षम कार्यक्रम के तहत निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की ।
- प्रशिक्षण नौकरी चाहने वालों को सॉफ्ट स्किल, डिजिटल कौशल और उन्नत कंप्यूटिंग क्षेत्रों से लैस करता है।

सहयोग और एकीकरण:

- छात्रों तक पहुंचने के लिए शिक्षा मंत्रालय, एआईसीटीई और अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के साथ सहयोग करता है।
- नियोक्ता-उम्मीदवार कनेक्शन के लिए ईपीएफओ और ईएसआईसी के साथ एकीकृत।
- दस्तावेज़ अपलोड और तेजी से नियुक्ति के लिए डिजिलॉकर से जोड़ा गया।

KUMAR'S IAS

पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और एकीकरण:

- ई-श्रम, उद्यम और स्किल इंडिया पोर्टल से जुड़ा, रोज़गार खोज और मिलान को बढ़ाया गया।
- ई-श्रम एकीकरण के कारण 10 लाख से अधिक पंजीकरण हुए और 1.2 लाख उम्मीदवारों को नौकरियों के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया।
- स्किल इंडिया पोर्टल एकीकरण से 46 लाख कुशल उम्मीदवार जुड़े।

अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के अवसर:

- मार्च 2022 में एक 'इंटरनेशनल जॉब' मॉड्यूल पेश किया गया, जो विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत नियोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय नौकरी के अवसर पोस्ट करने में सक्षम बनाता है।
- 400 से अधिक भर्ती एजेंटों ने पंजीकरण कराया, 1400 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रिक्तियां पोस्ट कीं।

81.**d**

स्पष्टीकरण:

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई):

- AB PM-JAY विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसे स्वास्थ्य देखभाल लागत से संबंधित लक्षित लाभार्थियों के जेब से खर्च (ओओपीई) को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए **प्रति वर्ष प्रति परिवार** ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। **(इसलिए कथन 1 गलत है)**
- 10.7 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवार (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) कवर किए गए हैं, जिनकी पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (एसईसीसी 2011) और राज्य योजनाओं से वंचित और व्यवसाय जैसे मानदंडों के आधार पर भारतीय आबादी के निचले 40% से की जाती है।
- 4 जनवरी, 2023 तक, योजना के तहत लगभग 21.9 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है, जिसमें राज्य आईटी प्रणालियों के माध्यम से 3 करोड़ शामिल हैं।
- 26,055 से अधिक अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से लगभग 4.3 करोड़ अस्पताल प्रवेश, कुल ₹50,409 करोड़ को अधिकृत किया गया है।

निम्नलिखित श्रेणियों के परिवार इस योजना के लाभ के लिए पात्र हैं:

- एक कमरे और रसोई वाले घरों में रहने वाले परिवार।
- ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
- ऐसे परिवार जिनमें महिला सदस्य घर का नेतृत्व करती हैं और 16 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क पुरुष नहीं है।
- ऐसे परिवार जिनमें विकलांग सदस्यों की देखभाल के लिए कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है।
- परिवार एससी/एसटी वर्ग के हैं।

KUMAR'S IAS

- भूमिहीन परिवार अपनी आजीविका का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम से प्राप्त करते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आश्रय विहीन घरों वाले परिवार वंचित हैं, दान पर जीवन यापन करते हैं, हाथ से शिकार करते हैं, आदिम जनजातियाँ हैं और कानूनी रूप से मुक्त बेगार हैं।
- निम्नलिखित व्यवसायों में शामिल शहरी क्षेत्रों के परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं: (**इसलिए कथन 2 गलत है)** (घरेलू काम, कूड़ा बीनना और भीख मांगना, सड़क पर सामान बेचना, फेरी लगाना, जूता बनाना, या कोई अन्य सड़क सेवाएं प्रदान करना। प्लंबर, मजदूर, राजमिस्त्री, और निर्माण श्रमिक, सुरक्षा गार्ड, वेल्डिंग श्रमिक भी पात्र हैं। सिर पर बोझ उठाने वाले श्रमिक जैसे कुली, और स्वच्छता कार्यकर्ता। कलाकार, दर्जी, चित्रकार और अन्य शिल्प श्रमिक। परिवहन कर्मचारी जैसे ड्राइवर, कंडक्टर और रिक्शा चालक। दुकान कर्मचारी जैसे वेटर, डिलीवरी सहायक और सहायक के रूप में। मैकेनिक, धोबी, इलेक्ट्रीशियन और अन्य मरम्मत कर्मचारी आदि।)

आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (AB-HWCs):

- यह योजना समुदायों के निकट व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एसएचसी और पीएचसी को अपग्रेड करके 1.5 लाख एबी-एचडब्ल्यूसी स्थापित करने की कल्पना करती है।
- एबी-एचडब्ल्यूसी व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं, जिसमें प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, संचारी और गैर-संचारी रोगों की सेवाएं शामिल हैं।

31 दिसंबर, 2022 तक के आंकड़े:

- पहले HWC का उद्घाटन 14 अप्रैल, 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में किया गया था।
- पूरे देश में 1,54,070 एचडब्ल्यूसी कार्यरत हैं।
- 135 करोड़ से अधिक संचयी आगमन।
- गैर-संचारी रोगों के लिए 87.0 करोड़ से अधिक संचयी जांच।
- योग सहित 1.6 करोड़ से अधिक वेलनेस सत्र।
- कार्यात्मक एचडब्ल्यूसी के माध्यम से ई-संजीवनी टेलीपरामर्श मंच के माध्यम से 9.3 करोड़ से अधिक टेली-परामर्श प्रदान किए गए।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम):

- एबीडीएम का लक्ष्य खुले, इंटरऑपरेबल डिजिटल मानकों के आधार पर एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करना है।
- यह प्लेटफ़ॉर्म नागरिकों की सहमति से उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच और आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें हेल्थ आईडी, हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री और स्वास्थ्य रिकॉर्ड शामिल हैं।
- यह पहुंच और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य देखभाल में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है।

10 जनवरी 2023 तक उपलब्धियाँ:

- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (पहले हेल्थ आईडी) बनाए गए: 31,11,96,965

KUMAR'S IAS

- स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री पर सत्यापित सुविधाएं: 1,92,706
- हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री पर सत्यापित हेल्थकेयर पेशेवर: 1,23,442
- संबद्ध स्वास्थ्य रिकॉर्ड: 7,52,01,236

82.**d**

स्पष्टीकरण:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) :

- विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं और संबद्ध क्षेत्रों में आय-सृजन गतिविधियों के लिए ₹10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया। **(अत: कथन 1 सही है)**
- इसमें कृषि से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं, जैसे मुर्गीपालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन, आदि।
- पीएमएमवाई के तहत सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों जरूरतों को पूरा किया जाता है।
- ऋण बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) सहित सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) द्वारा वितरित किए जाते हैं।

पीएमएमवाई की मुख्य विशेषताएं:

- तीन उत्पाद: 'शिशु' (₹50,000 तक के ऋण), 'किशोर' (₹50,000 से अधिक और ₹5 लाख तक के ऋण), और 'तरुण' (₹5 लाख से अधिक और ₹10 लाख तक के ऋण) अलग-अलग विकास के चरण और वित्त पोषण की जरूरतों को पूरा करते हैं।
- ऋण अनुमोदन के दौरान संपार्श्विक की कोई आवश्यकता नहीं। **(अत: कथन 2 सही है)**
- ऋण देने वाली संस्था द्वारा निर्धारित ब्याज दर; ब्याज केवल रात भर रखे गए धन पर लगाया जाता है। **(अत: कथन 3 सही है)**
- सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) एमएलआई द्वारा पीएमएमवाई के तहत पात्र सूक्ष्म इकाइयों को ऋण और प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों के तहत ओवरड्राफ्ट की गारंटी देता है।
- स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ₹10 लाख से ₹20 लाख के बीच स्वीकृत ऋण वित्तीय वर्ष 2011 से सीजीएफएमयू कवरेज के लिए पात्र हैं।

वर्तमान स्थिति:

- योजना की शुरुआत के बाद से ₹21.5 लाख करोड़ के 38.4 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए।
- नए उद्यमियों/खातों को कुल ₹6.8 लाख करोड़ के 8.2 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए, जो कुल ऋण का लगभग 21% है।
- लगभग 68% ऋण महिला उद्यमियों को दिया गया। **(अत: कथन 4 सही है)**

KUMAR'S IAS

83.**b**

स्पष्टीकरण:

नवीकरणीय ऊर्जा 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट

- भारत नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए उत्तरोत्तर एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है।
- नवीकरणीय ऊर्जा 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट से निवेश डेटा:
- 2014 और 2021 के बीच की अवधि में भारत के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा में कुल 78.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश देखा गया।
- नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश 2016 से लगातार सालाना 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है या उससे अधिक हो गया है।
- 2020 के दौरान निवेश में गिरावट आई, जिसका श्रेय संभवतः कोविड-19 प्रतिबंधों को दिया गया।
- हालाँकि, 2018 से 2020 तक निवेश में कमी आई है **(इसलिए कथन 1 गलत है)**

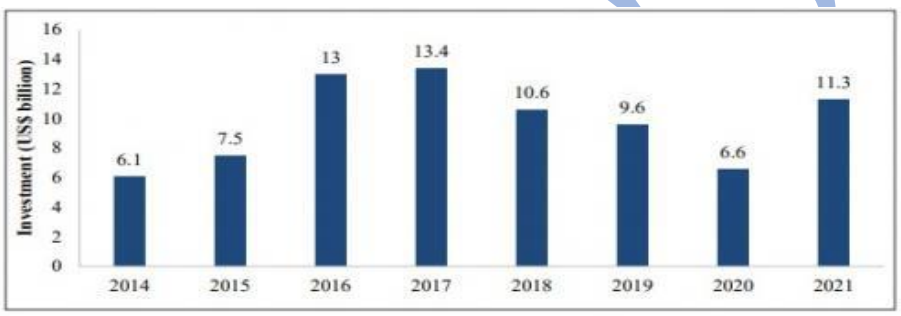

Source: REN 21. Renewables 2022 Global Status Report

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) प्रक्षेपण:

- सीईए ने 2029-30 के लिए बिजली की मांग और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आदर्श उत्पादन क्षमता मिश्रण की रूपरेखा तैयार की है।
- यह प्रक्षेपण बढ़ी हुई दक्षता पर विचार करता है और इसका उद्देश्य तकनीकी और वित्तीय सीमाओं के भीतर समग्र सिस्टम व्यय को कम करना है।
- 2029-30 तक अनुमानित स्थापित क्षमता:
  - 2029-30 के अंत तक अनुमानित स्थापित क्षमता 800 गीगावॉट से अधिक होने का अनुमान है।

KUMAR'S IAS

- इस क्षमता के भीतर, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावॉट से अधिक का योगदान होने की उम्मीद है। **(अत: कथन 2 सही है)**

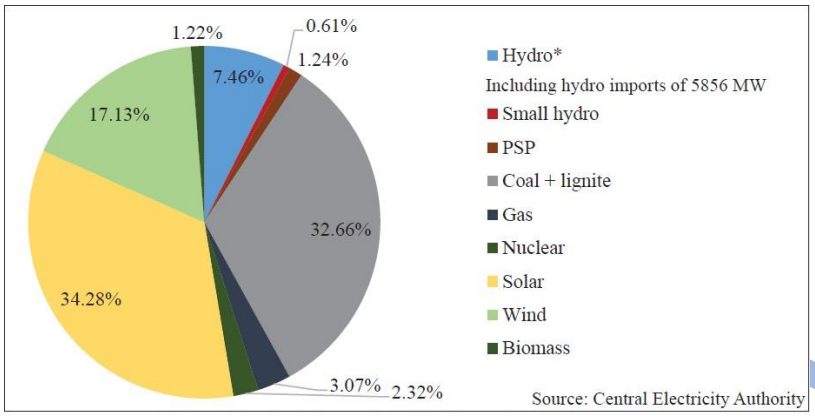

Projected optimal mix of installed capacity for 2029-30

84.**c**

स्पष्टीकरण:

वित्तीय समावेशन:

- इसका उद्देश्य **सुलभ और किफायती** वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करना है। यह बेहतर आजीविका के लिए वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी को रोकने वाली बाधाओं को दूर करना चाहता है। इसे समावेशी वित्त के रूप में भी जाना जाता है। **(अत: कथन 1 सही है)**
- उद्देश्य: उचित लागत पर व्यापक वैश्विक आबादी तक वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना।
- दायरा: भौगोलिक क्षेत्रों, लिंग-विशिष्ट उपभोक्ताओं, विशिष्ट आयु समूहों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों सहित विभिन्न आयामों को शामिल करता है।
- लाभ: नवाचार, आर्थिक विकास और उपभोक्ता ज्ञान को बढ़ावा देता है।
- **दैनिक जीवन**, वित्तीय योजना, जोखिम प्रबंधन और निवेश की सुविधा प्रदान करके जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाता है। **(अत: कथन 2 सही है)**
- फिनटेक प्रगति: तकनीकी नवाचार, जैसे डिजिटल लेनदेन, वित्तीय समावेशन की आसान उपलब्धि में योगदान करते हैं।
- बाधाओं पर काबू पाना: विभिन्न पहलू वित्तीय समावेशन की ऐतिहासिक बाधाओं को दूर कर रहे हैं, व्यापक दर्शकों को पहले से दुर्गम वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
- वित्तीय उद्योग की भूमिका: वित्तीय उद्योग विश्व स्तर पर उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने के लिए नए तरीके विकसित करता है, जिससे अक्सर मुनाफा होता है। फिनटेक समाधान वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **समावेशिता आयाम:** वित्तीय समावेशन उम्र, लिंग, नस्ल, भूगोल, विकलांगता और सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे कारकों पर विचार करता है। **(अत: कथन 3 सही है)**
- फोकस के क्षेत्र: वित्तीय समावेशन में कई अवधारणाएँ शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं: वित्तीय, आर्थिक और उद्यमशीलता पहलू।

KUMAR'S IAS

85.**a**

स्पष्टीकरण:

जैम ट्रिनिटी (JAM Trinity):

परिचय:

- JAM जन धन योजना, आधार और मोबाइल नंबर को दर्शाता है।
- उद्देश्य: महत्वपूर्ण सुधार लागू करना - स्वतंत्र भारत में गरीबों को सीधे सब्सिडी हस्तांतरण।
- पीडीएस और मनरेगा जैसी वर्तमान सब्सिडी अप्रत्यक्ष मार्ग का अनुसरण करती है और इसमें बिचौलियों को शामिल किया जाता है।
- मुद्दे: राजकोष के लिए महंगा, भ्रष्टाचार की संभावना, लाभ इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता है।

JAM ट्रिनिटी के लाभ:

- **आधार** वंचित नागरिकों की प्रत्यक्ष बायोमेट्रिक पहचान को सक्षम बनाता है। **(इसलिए विकल्प ए) सही है)**
- जन धन बैंक खाते और मोबाइल फोन बिचौलियों को खत्म करते हुए सीधे फंड ट्रांसफर की अनुमति देते हैं।
- मौजूदा सब्सिडी योजनाओं में महँगाई, भ्रष्टाचार और रिसाव के मुद्दों को संबोधित करता है।
- सब्सिडी के उद्देश्यों के अनुरूप गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।
- JAM ट्रिनिटी सब्सिडी दक्षता बढ़ाने और जरूरतमंदों तक पहुंचने के सरकार के प्रयासों को प्रदर्शित करता है।
- आधार और मोबाइल प्रौद्योगिकी के साथ इसका एकीकरण प्रभावी शासन और सामाजिक समर्थन का उदाहरण है।

महत्व:

- सरकार सब्सिडी के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 4.2% आवंटित करती है, लेकिन अक्षमताएँ बनी रहती हैं।
- वर्तमान प्रणाली में कुशल लक्ष्यीकरण का अभाव है; लाभ अक्सर संपन्न लोगों द्वारा हड़प लिया जाता है।
- रिसाव पर्याप्त हैं: पीडीएस चावल, गेहूं और चीनी का नुकसान एक महत्वपूर्ण प्रतिशत है।
- JAM ट्रिनिटी इच्छित प्राप्तकर्ताओं को सीधा लाभ सुनिश्चित करके एक संभावित समाधान प्रदान करता है।

JAM ट्रिनिटी का सशक्तिकरण:

- आधार से जुड़ी जन धन योजना, COVID-19 लॉकडाउन के दौरान भारतीयों की सहायता करती है।
- लाभार्थियों के बैंक खातों में त्वरित और भ्रष्टाचार मुक्त धन हस्तांतरण।
- प्रधानमंत्री ने लाखों लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला।
- JAM ट्रिनिटी लॉकडाउन के दौरान एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, जिससे वित्तीय तनाव का सामना कर रहे परिवारों को सहायता मिलती है।

KUMAR'S IAS

86.**b**

स्पष्टीकरण:

भारत में, बुनियादी ढांचे के कार्यक्रमों में निजी भागीदारी विभिन्न पीपीपी मॉडल का समर्थन करती है, जिनमें शामिल हैं:

- प्रबंधन अनुबंध: इन मॉडलों में बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी), डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर (डीबीएफओटी), रिहैबिलिटेट-ऑपरेट-ट्रांसफर (आरओटी), हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम), और टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) शामिल हैं।
- बीओटी वेरिएंट: बीओटी मॉडल के भीतर, दो वेरिएंट मौजूद हैं - बीओटी (टोल) और बीओटी (एन्युटी)। उनके बीच का चुनाव यातायात जोखिम वहन करने के लिए जिम्मेदार इकाई पर निर्भर करता है।
- बीओटी (टोल): इस प्रकार में, पीपीपी रियायतग्राही यातायात जोखिम को मानता है।
- बीओटी (एन्युटी): इस मामले में, सार्वजनिक प्राधिकरण यातायात जोखिम वहन करता है।

बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी)

- बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी) **एक परियोजना वितरण पद्धति है जिसका उपयोग आमतौर पर बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं में किया जाता है।** इसमें बुनियादी ढांचे की संपत्तियों के डिजाइन, वित्त, निर्माण, संचालन और अंततः हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी कंपनियों के बीच सहयोग शामिल है। बीओटी का प्राथमिक उद्देश्य सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करते हुए आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाना है। **(अतः कथन 1 सही है)**

यहां बताया गया है कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल कैसे काम करता है:

- निर्माण: प्रारंभिक चरण में, निजी क्षेत्र का भागीदार (आमतौर पर एक कंसोर्टियम या कंपनी) बुनियादी ढांचा परियोजना के डिजाइन, वित्तपोषण और निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें अपनी स्वयं की पूंजी निवेश करना और परियोजना के निर्माण के लिए बाहरी धन की व्यवस्था करना शामिल है।
- संचालन: निर्माण चरण पूरा होने के बाद, निजी क्षेत्र का भागीदार एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधा का संचालन और रखरखाव करता है, जो अक्सर कई वर्षों से लेकर कुछ दशकों तक होता है। इस परिचालन चरण के दौरान, निजी भागीदार सुविधा के रखरखाव, रखरखाव और इसके कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
- स्थानांतरण: एक बार संचालन और रखरखाव की सहमत अवधि पूरी हो जाने पर, बुनियादी ढांचे की संपत्ति का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र को वापस स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस बिंदु पर, सार्वजनिक क्षेत्र सुविधा के संचालन और रखरखाव पर नियंत्रण रखता है। हस्तांतरण को विभिन्न कानूनी और संविदात्मक तंत्रों के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है, जिससे स्वामित्व का निर्बाध परिवर्तन सुनिश्चित होता है।

बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल की विशेषताओं और फायदों में शामिल हैं:

KUMAR'S IAS

- **जोखिम साझा करना:** निजी क्षेत्र परियोजना से जुड़े वित्तीय, परिचालन और प्रदर्शन जोखिमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है, **जो सरकार पर बोझ को कम कर सकता है। (इसलिए कथन 2 गलत है)**
- दक्षता और नवाचार: निजी क्षेत्र के भागीदार अक्सर विशेषज्ञता, तकनीकी जानकारी और नवाचार लाते हैं जिससे अधिक कुशल परियोजना वितरण और संचालन हो सकता है।
- समय पर निष्पादन: चूंकि निजी क्षेत्र परियोजना के वित्तपोषण और वितरण के लिए जिम्मेदार है, इसलिए परियोजना को समय पर और बजट के भीतर पूरा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
- राजस्व सृजन: निजी क्षेत्र का भागीदार अनुबंधित अवधि के दौरान सुविधा के संचालन के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करता है, जो उनके प्रारंभिक निवेश की भरपाई करने में मदद कर सकता है।
- सार्वजनिक लाभ: बीओटी परियोजनाएं महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दे सकती हैं जो **सरकार पर तत्काल वित्तीय बोझ डाले बिना जनता को लाभ पहुंचाती हैं। (अत: कथन 3 सही है)**
- पारदर्शिता और जवाबदेही: सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संविदात्मक समझौते जिम्मेदारियों, प्रदर्शन मानकों और रिपोर्टिंग तंत्र की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिससे परियोजना निष्पादन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

87.**b**

स्पष्टीकरण:

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी):

समाचार में:

- असम ने अब वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) लागू कर दिया है, जिससे यह कार्यक्रम अपनाने वाला 36वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। **(अत: कथन 1 सही है)**
- यह ओएनओआरसी के संपूर्ण राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन का प्रतीक है, जो पूरे भारत में पोर्टेबल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- ओएनओआरसी के लाभों को बढ़ाने के लिए 'मेरा राशन' मोबाइल ऐप भी पेश किया गया है, जो 13 भाषाओं में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है।
- ओएनओआरसी ने महामारी के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थियों, विशेषकर प्रवासी व्यक्तियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ओएनओआरसी संकल्पना:

- भारत भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से पीडीएस लाभ प्राप्त करने के लिए प्रवासी श्रमिकों और परिवारों के लिए राष्ट्रीय राशन कार्ड।
- मौजूदा राशन कार्ड ओएनओआरसी में तब्दील। **(नए कार्ड के लिए आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है) (इसलिए कथन 3 गलत है)**
- प्रत्येक एनएफएसए लाभार्थी को यूनिवर्सल राशन कार्ड सौंपा गया।

- लाभार्थी मूल स्थान की परवाह किए बिना गंतव्य शहर की उचित मूल्य की दुकान से सब्सिडी वाला खाद्यान्न खरीद सकते हैं। **(अत: कथन 2 सही है)**
- ईपीओएस उपकरणों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस) पोर्टल और अन्नवितरण पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी।

ओएनओआरसी के लाभ:

- पूरे भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सब्सिडी वाले खाद्यान्न की पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।
- विभिन्न राज्यों में लाभार्थियों के लिए समान राशन सुनिश्चित करता है।
- समस्या होने पर तुरंत वैकल्पिक एफपीएस पर स्विच करना।
- सामाजिक पहचान बाधाओं से निपटते हुए, महिलाओं और वंचित समूहों को लाभ पहुँचाता है।
- भारत की वैश्विक भूखमरी सूचकांक रैंक को बढ़ाकर, 2030 तक भूखमरी को खत्म करने के संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य का समर्थन करता है।

चुनौतियाँ:

- आधार-लिंक्ड प्रक्रियाओं के कारण बहिष्करण त्रुटियाँ, आधार कार्ड के बिना कुछ वर्गों को वंचित करना।
- ऐतिहासिक अधिवास-आधारित योजनाएं बाधित हुईं।
- माइग्रेशन-आधारित मांग परिवर्तनों के कारण एफपीएस पर आपूर्ति में संभावित व्यवधान।

योजना का प्रदर्शन:

- अगस्त 2019 से 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए तेजी से कार्यान्वयन।
- 2019 से लगभग 71 करोड़ पोर्टेबल लेनदेन, खाद्य सब्सिडी में लगभग 40,000 करोड़ रुपये के बराबर खाद्यान्न वितरित किया गया।
- लगभग 3 करोड़ पोर्टेबल लेनदेन का मासिक औसत, लाभार्थियों को लचीलेपन के साथ एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई खाद्यान्न प्रदान करता है।

88.**d**

स्पष्टीकरण:

व्यापक रोज़गार की स्थिति में रुझान

रोजगार श्रेणियों के संदर्भ में, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के रुझानों से प्रभावित होकर, 2019-20 की तुलना में 2020-21 में **स्व-रोज़गार व्यक्तियों के अनुपात में वृद्धि हुई** और नियमित वेतन/वेतनभोगी श्रमिकों के प्रतिशत में कमी आई। इसके अलावा, आकस्मिक मजदूरों का हिस्सा थोड़ा कम हो गया, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव के कारण है। **(इसलिए कथन 1 गलत है)**

Figure VI.3: Trends in broad employment status *(Persons, rural+urban)*

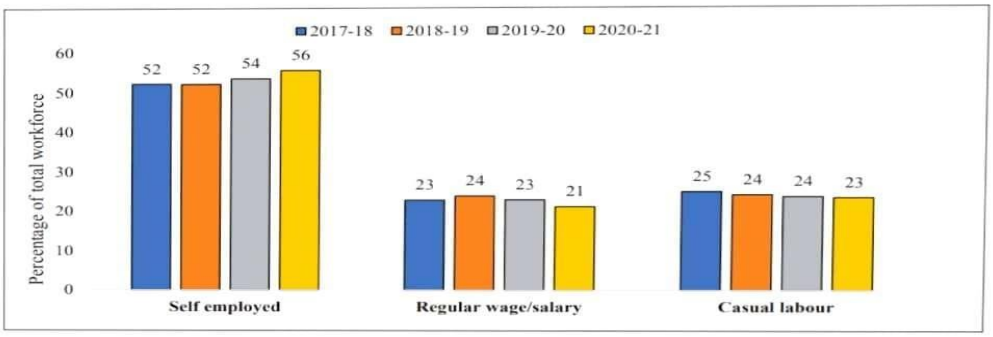

Source: Annual PLFS, MoSPI

महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर)

- कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में 2019-20 में 45.6% से मामूली वृद्धि हुई और 2020-21 में 46.5% हो गई।
- विनिर्माण क्षेत्र (manufacturing) में श्रमिकों की हिस्सेदारी में 11.2% से 10.9% की **मामूली गिरावट देखी गई। (इसलिए कथन 2 गलत है)**
- निर्माण क्षेत्र (construction sector) की हिस्सेदारी 11.6% से बढ़कर 12.1% हो गई।
- इसी अवधि के दौरान व्यापार, होटल और रेस्तरां क्षेत्र की हिस्सेदारी 13.2% से घटकर 12.2% हो गई।
- इन बदलावों को विनिर्माण और सेवा रोजगार पर कोविड के प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है (2020-21 डेटा जुलाई 2020 से जून 2021 तक फैला हुआ है), जबकि कृषि विकास मजबूत रहा।
- 2017-18 से 2020-21 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) में सामान्य स्थिति के लिए 9.5 प्रतिशत अंक (पीपी) और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के लिए 8.3 प्रतिशत की वृद्धि एक सकारात्मक लिंग-संबंधी विकास है।
- यह वृद्धि ग्रामीण सुविधाओं में सुधार के कारण महिलाओं के समय की बचत और निरंतर कृषि विकास के कारण हो सकती है।

89.**b**

स्पष्टीकरण:

शून्य-आधारित बजटिंग निम्नलिखित तरीकों से पारंपरिक बजटिंग से भिन्न है:

प्रस्थान बिंदु:

- शून्य-आधारित बजटिंग (जेडबीबी): बजट प्रक्रिया शून्य की आधार रेखा से शुरू होती है, जहां प्रत्येक खर्च को शुरू से ही उचित ठहराने की आवश्यकता होती है।
- पारंपरिक बजटिंग: पिछली अवधि के बजट को संदर्भ बिंदु के रूप में शुरू करता है और वृद्धिशील परिवर्तनों के आधार पर समायोजन करता है। **(अत: कथन 1 सही है)**

दृष्टिकोण:

- ZBB: सभी खर्चों की गहन समीक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें प्रत्येक लागत मद के लिए औचित्य की आवश्यकता होती है।
- पारंपरिक: ऐतिहासिक डेटा पर निर्भर करता है और इसमें अक्सर पिछले बजट में वृद्धिशील समायोजन शामिल होता है।

निर्णय लेना:

- ZBB: इसमें निर्णय लेने वाले सभी खर्चों का गंभीर मूल्यांकन करते हैं, अनावश्यक लागतों को समाप्त करते हैं और वर्तमान प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों को पुनः आवंटित करते हैं।
- पारंपरिक: मानता है कि चल रहे खर्च उचित हैं और मुख्य रूप से वृद्धिशील परिवर्तनों पर केंद्रित है।

दक्षता और लागत नियंत्रण:

- ZBB: आवश्यक खर्चों की पहचान और प्राथमिकता देकर संसाधनों के कुशल आवंटन पर जोर देता है, जिससे लागत नियंत्रण को बढ़ावा मिलता है।
- पारंपरिक: इससे अक्षमताएं हो सकती हैं क्योंकि पिछले आवंटनों को कठोर जांच के बिना बनाए रखा जाता है। **(अतः कथन 2 सही है)**

लचीलापन:

- ZBB: बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करता है, क्योंकि सभी खर्चों का मूल्यांकन शुरुआत से किया जाता है।
- पारंपरिक: ऐतिहासिक डेटा पर निर्भरता के कारण गतिशील स्थितियों में आवश्यक अनुकूलनशीलता की कमी हो सकती है। **(इसलिए कथन 3 गलत है)**

संसाधनों का आवंटन:

- ZBB: यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का आवंटन वर्तमान जरूरतों और उद्देश्यों के आधार पर किया जाए, पिछले आवंटनों को स्वचालित रूप से आगे बढ़ाने के जाल से बचा जाए।
- पारंपरिक: यदि ऐतिहासिक व्यय पैटर्न वर्तमान आवश्यकताओं के साथ संरेखित नहीं होता है तो अकुशल संसाधन आवंटन कायम रह सकता है।

बजट बनाने की प्रक्रिया:

- ZBB: प्रत्येक खर्च को उचित ठहराने की आवश्यकता के कारण अधिक गहन और समय लेने वाली प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।
- पारंपरिक: तेज़ हो सकता है क्योंकि इसमें मौजूदा बजट आंकड़ों में समायोजन करना शामिल है। **(अतः कथन 4 ग़लत है)**

जोखिम प्रबंधन:

KUMAR'S IAS

- ZBB: प्रत्येक व्यय से जुड़े जोखिमों की पहचान करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे बेहतर जोखिम प्रबंधन होता है।
- पारंपरिक: पिछले बजट से किए गए खर्चों से संबंधित जोखिमों का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

90.**c**

स्पष्टीकरण:

बाबा कल्याणी समिति की सिफारिशें:

- समिति का गठन: भारत के मौजूदा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) का विश्लेषण करने और एक रणनीतिक नीति ढांचा तैयार करने के लिए 2018 में श्री बाबा कल्याणी के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना की गई थी। **(अत: कथन 1 सही है)**
- एसईजेड का नाम बदलना: भारत में एसईजेड का नाम बदलकर "3ई"- रोजगार और आर्थिक एन्क्लेव करने का प्रस्ताव। **(अत: कथन 2 सही है)**
- रूपरेखा में बदलाव: निर्यात वृद्धि पर जोर देने से लेकर व्यापक रोजगार और आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा में बदलाव की सिफारिश की गई।
- विभेदित नियम: विनिर्माण और सेवा-उन्मुख एसईजेड के लिए अलग-अलग नियम और प्रक्रियाओं का सुझाव दिया गया।
- व्यवसाय करने में आसानी: 3ई के लिए व्यवसाय करने में आसानी (EoDB) वातावरण में प्रस्तावित सुधार, जिसमें नए निवेश के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल भी शामिल है।
- सनसेट क्लॉज एक्सटेंशन: सनसेट क्लॉज को बढ़ाने और कर या शुल्क लाभ बरकरार रखने की वकालत की गई।
- एकीकृत आईएफएससी नियामक: अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) के लिए एक एकीकृत नियामक की स्थापना का समर्थन किया।
- विवाद समाधान: प्रभावी विवाद समाधान के लिए मध्यस्थता और वाणिज्यिक अदालतों का उपयोग करने की सिफारिश की गई।

91.**a**

स्पष्टीकरण:

सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम (Law of Diminishing Marginal Utility):

- सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो बताती है कि किसी वस्तु या सेवा की अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि या उपयोगिता उपभोग की मात्रा बढ़ने के साथ कम हो जाती है, जबकि अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं। **(अत: कथन 1 सही है)**

- सरल शब्दों में, यह सुझाव देता है कि जैसे-जैसे आप किसी विशेष उत्पाद या सेवा का अधिक उपभोग करते हैं, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से आपको मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि या खुशी धीरे-धीरे कम हो जाएगी। यह सिद्धांत मनुष्य द्वारा अपने संसाधनों को आवंटित करने और उपभोग विकल्प चुनने के तरीके में निहित है।

यहां अवधारणा का अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है:

- उपयोगिता: अर्थशास्त्र में, उपयोगिता संतुष्टि या खुशी के स्तर को संदर्भित करती है जो व्यक्तियों को वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से प्राप्त होती है। यह एक व्यक्तिपरक माप है और यह व्यक्ति-दर-व्यक्ति भिन्न हो सकता है।
- सीमांत उपयोगिता: सीमांत उपयोगिता से तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा की एक और इकाई के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि से है। यह उपभोग की गई मात्रा में एक छोटे से परिवर्तन के परिणामस्वरूप कुल उपयोगिता में परिवर्तन है।
- सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम: यह कानून बताता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति एक निश्चित समय अवधि के भीतर किसी वस्तु या सेवा की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, अन्य सभी कारकों (जैसे उनकी प्राथमिकताएं, आय और अन्य वस्तुओं की कीमतें) को स्थिर रखता है, सीमांत उपयोगिता प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता कम हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, जितना अधिक आप किसी चीज़ का उपभोग करते हैं, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई आपकी समग्र संतुष्टि में उतना ही कम योगदान देती है।

इस अवधारणा को चॉकलेट जैसी सामान्य वस्तु का उपयोग करके एक सरल उदाहरण से चित्रित किया जा सकता है:

- मान लीजिए कि आपको चॉकलेट पसंद है, और आपके पास उसका पहला टुकड़ा है। उस पहले टुकड़े से आपको जो संतुष्टि मिलती है वह बहुत अधिक है - उपयोगिता के मामले में यह 10 में से 10 हो सकता है। जैसे-जैसे आप अधिक टुकड़ों का उपभोग करते हैं, आपकी संतुष्टि अभी भी बढ़ती है, लेकिन कम वृद्धि से। अतिरिक्त संतुष्टि के मामले में दूसरा टुकड़ा 10 में से 9 हो सकता है। तीसरा 8, चौथा 6, इत्यादि हो सकता है। अंततः, जैसे-जैसे आप चॉकलेट के अधिक से अधिक टुकड़ों का उपभोग करते हैं, वृद्धिशील संतुष्टि कम हो जाती है, एक ऐसे बिंदु पर पहुँच जाती है जहाँ आप दूसरा टुकड़ा भी नहीं चाहेंगे क्योंकि अतिरिक्त संतुष्टि बहुत कम होती है।
- यह घटना उपभोक्ता व्यवहार का एक मूलभूत पहलू है और इसका मूल्य निर्धारण, उपभोग पैटर्न और संसाधन आवंटन सहित विभिन्न आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ता है। इससे यह समझाने में भी मदद मिलती है कि लोग अक्सर किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं में अपने उपभोग में विविधता क्यों लाते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की घटती सीमांत उपयोगिता संतुलित उपभोग दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है।
- सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम बताता है कि जैसे-जैसे एकल वस्तु की खपत बढ़ती है, उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। संतुष्टि में यह कमी व्यक्तियों को **वैकल्पिक वस्तुओं की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है,** जिससे **विभिन्न वस्तुओं में उपभोग का विविधीकरण होता है। (इसलिए कथन 2 गलत है)**

92.**d**

स्पष्टीकरण:

उपभोक्ता की इष्टतम पसंद:

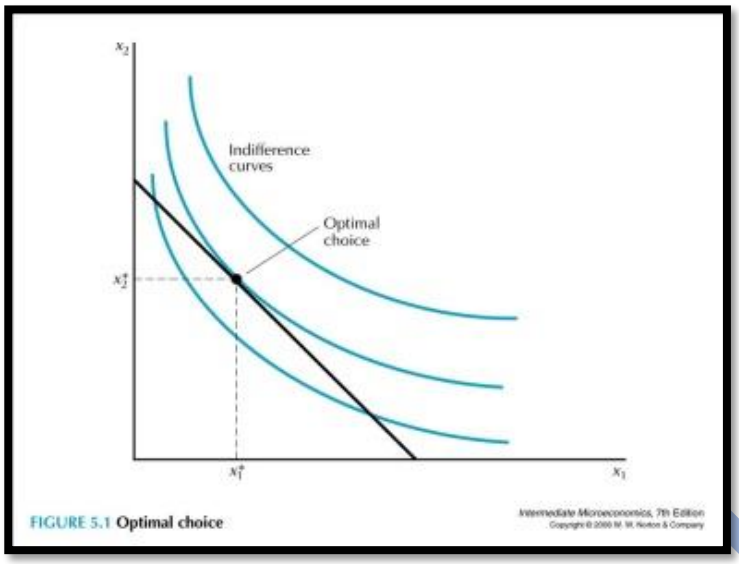

- अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के लिए इष्टतम बंडल वस्तुओं और सेवाओं के संयोजन को संदर्भित करता है जो उपभोक्ता की बजट बाधा को देखते हुए उसकी संतुष्टि या उपयोगिता को अधिकतम करता है। दूसरे शब्दों में, यह वस्तुओं का संयोजन है जो उपभोक्ता को उनकी आय और वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए उच्चतम स्तर की संतुष्टि प्रदान करता है। **(इसलिए विकल्प d) सही है)**
- उच्च उदासीनता वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इष्टतम बंडल आवश्यक रूप से उच्चतम वक्र पर स्थित नहीं है। यह उपभोक्ता के बजट की कमी और वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करता है । **(इसलिए विकल्प ए) गलत है)**
- कुल व्यय को अधिकतम करना उपभोक्ता अनुकूलन का लक्ष्य नहीं है। उपभोक्ताओं का लक्ष्य अपने बजट की सीमाओं के भीतर अपनी उपयोगिता या संतुष्टि को अधिकतम करना है। **(इसलिए विकल्प बी गलत है)**
- यह विकल्प इष्टतम बंडल होने की संभावना नहीं है। ग्राफ़ की उत्पत्ति आमतौर पर दोनों वस्तुओं की शून्य खपत को दर्शाती है, और एक इष्टतम बंडल में आम तौर पर उन वस्तुओं की सकारात्मक खपत शामिल होती है जो उपयोगिता को अधिकतम करती हैं। **(इसलिए विकल्प सी) भी गलत है)**
- इष्टतम बंडल उन वस्तुओं का संयोजन है जिसे उपभोक्ता खरीद सकता है और जो उच्चतम स्तर की संतुष्टि प्रदान करता है। यह वह बिंदु है जहां बजट रेखा उदासीनता वक्र को छूती है, यह दर्शाता है कि उपभोक्ता अपनी आय को इस तरह से आवंटित कर रहा है जो उन्हें उस वक्र पर वस्तुओं के वैकल्पिक संयोजनों के बीच उदासीन बनाता है।

93.**c**

स्पष्टीकरण:

सामान्य वस्तुएं (Normal Goods):

- उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ मांग की मात्रा बढ़ती है। **(अत: कथन 1 सही है)**
- बढ़ती आय के साथ अधिकांश वस्तुओं की मांग बढ़ती है; ये सामान्य वस्तुएं हैं।
- सामान्य वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की मांग आय के समान दिशा में चलती है।

सस्ती वस्तुएं (Inferior Goods):

- उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ मांग की मात्रा घट जाती है। **(अतः कथन 2 सही है)**
- कुछ वस्तुओं की मांग आय परिवर्तन के विपरीत चलती है; ये घटिया वस्तुएं हैं।
- उदाहरण: मोटे अनाज जैसे निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ।
- आय बढ़ने से घटिया वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और इसका विपरीत भी होता है।

वस्तुओं की गतिशील प्रकृति:

- विभिन्न आय स्तरों के आधार पर कोई वस्तु सामान्य या निम्नतर हो सकती है।
- कम आय पर, घटिया वस्तुओं की मांग आय के साथ बढ़ सकती है।
- एक सीमा के बाद, अधिक आय से घटिया वस्तुओं की खपत कम हो जाती है।

संपूरक वस्तुएं (Complementary Goods)**:**

- एक पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरे की मांग कम हो जाती है। **(इसलिए कथन 3 गलत है)**
- एक साथ सेवन करना, जैसे चाय और चीनी, जूते और मोज़े।
- उदाहरण: चीनी की ऊंची कीमत से चाय की मांग कम हो जाती है।
- आम तौर पर, मांग पूरक वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन के विपरीत चलती है।

स्थानापन्न वस्तुएँ (Substitute Goods):

- किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन उसके स्थानापन्न की मांग को प्रभावित करता है।
- एक दूसरे की जगह ले सकता है, उदाहरण के लिए, चाय और कॉफ़ी।
- यदि कॉफी की कीमत बढ़ती है, तो चाय की मांग बढ़ सकती है (प्रतिस्थापन प्रभाव)।
- अगर कॉफी की कीमत घटी तो चाय की मांग घट सकती है।
- मांग आमतौर पर स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन की दिशा का अनुसरण करती है। **(अतः कथन 4 सही है)**

94.**a**

स्पष्टीकरण:

पूर्ण प्रतिस्पर्धा में लाभ अधिकतमीकरण का विश्लेषण:

पूर्ण प्रतिस्पर्धा की परिभाषित विशेषताएं:

एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाज़ार की विशेषता होती है:

- असंख्य खरीदार और विक्रेता
- प्रत्येक फर्म द्वारा समान उत्पादों का उत्पादन और बिक्री

- फर्मों के लिए निःशुल्क प्रवेश और निकास

बड़ी संख्या का महत्व:

- कुल बाज़ार आकार की तुलना में बाज़ार भागीदार छोटे हैं।
- कोई भी व्यक्ति अपने आकार के कारण बाज़ार को प्रभावित नहीं कर सकता।

सजातीय उत्पाद:

- सभी कंपनियाँ समान सामान का उत्पादन करती हैं।
- खरीदार किसी भी फर्म को चुन सकते हैं क्योंकि उत्पाद अप्रभेद्य हैं।

निःशुल्क प्रवेश और निकास:

- कंपनियाँ आसानी से बाज़ार में प्रवेश कर सकती हैं या छोड़ सकती हैं।
- बड़ी संख्या में फर्मों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण।

बिल्कुल सही जानकारी:

- खरीदारों और विक्रेताओं को कीमतों, गुणवत्ता और बाज़ार के बारे में व्यापक जानकारी होती है।

कीमत वसूलने वाला व्यवहार:

- पूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषता
- फर्म और खरीदार प्रचलित बाजार मूल्य को दिए गए अनुसार लेते हैं।

फर्मों के लिए मूल्य निर्धारण:

- बिक्री को अधिकतम करने के लिए फर्म बाजार मूल्य पर या उससे नीचे मूल्य निर्धारित करती है।
- बाज़ार मूल्य से ऊपर सेट करने पर बिक्री नहीं होती है।

खरीदारों के लिए मूल्य निर्धारण:

- खरीदार न्यूनतम कीमत पसंद करते हैं लेकिन बाजार मूल्य स्वीकार करते हैं।
- बाजार मूल्य से कम कीमत पर कोई विक्रेता नहीं मिलता।

मूल्य निर्धारण की तर्कसंगतता:

- यह तब लागू होता है जब बाज़ार में कई कंपनियाँ हों और ख़रीदारों को अच्छी तरह से जानकारी हो।
- जब एक फर्म बाजार मूल्य से विचलित हो जाती है, तो वह सभी खरीदारों को खो देती है।
- अनेक फर्मों के कारण कोई समायोजन समस्या नहीं।

KUMAR'S IAS

- बड़ी संख्या में फर्मों, सूचित खरीदारों और बाजार मूल्य से विचलन के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य निर्धारण व्यवहार उचित है।

95.**c**

स्पष्टीकरण:

मूल्य सीमा (Price Ceiling):

ऐसी स्थितियों का सामना करना असामान्य नहीं है जिनमें सरकारें विशिष्ट वस्तुओं की कीमत पर ऊपरी सीमा स्थापित करती हैं। **सरकार द्वारा लगाई गई इस ऊपरी सीमा को मूल्य सीमा कहा जाता है** । मूल्य सीमा आमतौर पर चावल, गेहूं, मिट्टी का तेल और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए निर्धारित की जाती है, और उन्हें बाजार-निर्धारित मूल्य से नीचे स्थापित किया जाता है। यह आबादी के उन वर्गों के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित करता है जिन्हें अन्यथा इन वस्तुओं को खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। **(अत: कथन 1 सही है)**

मूल्य आधार/ स्तर (Price Floor):

कुछ वस्तुओं और सेवाओं के मामले में, एक निश्चित सीमा से नीचे कीमत में कमी को अनुकूल नहीं माना जाता है। इसे संबोधित करने के लिए, सरकारें **इन वस्तुओं और सेवाओं के लिए न्यूनतम कीमतें निर्धारित करती हैं, जिन्हें मूल्य स्तर के रूप में जाना जाता है** । मूल्य स्तर उस कीमत पर सरकार की निचली सीमा का प्रतिनिधित्व करता है जिसे किसी विशिष्ट वस्तु या सेवा के लिए वसूला जा सकता है। मूल्य स्तर के प्रमुख उदाहरणों में कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम और न्यूनतम वेतन कानून शामिल हैं। **(अत: कथन 2 सही है)**

96.**c**

स्पष्टीकरण:

अर्थशास्त्र में बाह्यताएँ (Externalities):

- परिभाषा: बाह्यताएँ गतिविधि में शामिल नहीं होने वाले पक्षों पर आर्थिक गतिविधियों के अनपेक्षित प्रभाव को संदर्भित करती हैं। ये प्रभाव सकारात्मक (लाभकारी) या नकारात्मक (हानिकारक) हो सकते हैं। **(अत: कथन 1 सही है)**
- सकारात्मक बाह्यता: तब होता है जब कोई आर्थिक गतिविधि तीसरे पक्ष को लाभ पहुंचाती है जो लेनदेन का हिस्सा नहीं हैं। उदाहरणों में अधिक सूचित समाज की ओर ले जाने वाली शिक्षा और बीमारियों के प्रसार को कम करने वाले व्यक्तियों का टीकाकरण शामिल है।
- नकारात्मक बाह्यता: तब उत्पन्न होती है जब कोई आर्थिक गतिविधि तीसरे पक्ष पर लागत थोपती है। कारखानों से होने वाला प्रदूषण हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है और निर्माण से होने वाला ध्वनि प्रदूषण नकारात्मक बाहरी कारक हैं।
- प्रभाव: बाह्यताएँ बाज़ारों की दक्षता को बाधित करती हैं, क्योंकि वे वस्तुओं और सेवाओं के कम उत्पादन या अधिक उत्पादन का कारण बनती हैं जिसके परिणामस्वरूप बाहरी प्रभाव पड़ते हैं। बाज़ार कीमतें इन बाहरी लागतों या लाभों को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं।

- सार्वजनिक वस्तुएँ: सकारात्मक बाह्यताओं के कारण सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन कम हो सकता है। सरकारें अपनी गैर-बहिष्कृत प्रकृति के कारण सार्वजनिक वस्तुओं को प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप करती हैं। **(अत: कथन 2 सही है)**
- निजी समाधान और सरकारी हस्तक्षेप: बाह्यताओं के मामलों में, निजी समाधान पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। सरकारी हस्तक्षेप में बाहरी लागतों या लाभों को आंतरिक बनाने के लिए कर, सब्सिडी या नियम शामिल हो सकते हैं।
- कोसे प्रमेय: रोनाल्ड कोसे द्वारा प्रस्तावित, इसमें कहा गया है कि अच्छी तरह से परिभाषित संपत्ति अधिकार दिए जाने पर, निजी पक्ष सरकारी हस्तक्षेप के बिना बातचीत कर सकते हैं और बाहरी समस्याओं के कुशल समाधान तक पहुंच सकते हैं।

नकारात्मक बाह्यताओं पर लगाए गए कर का नाम:

बाहरी लागतों को आंतरिक करने के लिए नकारात्मक बाह्यताओं पर लगाए गए कर को "पिगौवियन टैक्स" या "सुधारात्मक कर" के रूप में जाना जाता है। इस कर का नाम ब्रिटिश अर्थशास्त्री आर्थर पिगौ के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने निजी लागत को सामाजिक लागत के साथ संरेखित करने और बाजार दक्षता बहाल करने के लिए नकारात्मक बाहरी प्रभाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर कर लगाने की वकालत की थी। पिगौवियन कर का उद्देश्य बाहरीता पैदा करने वाली गतिविधि की मात्रा को कम करना और अधिक सामाजिक रूप से लाभकारी विकल्पों की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करना है। **(अत: कथन 3 सही है)**

97.**b**

स्पष्टीकरण:

अर्थशास्त्र में स्वायत्त उपभोग (Autonomous Consumption):

- परिभाषा: स्वायत्त उपभोग, उपभोग व्यय के उस स्तर को संदर्भित करता है जो **तब भी होता है जब किसी व्यक्ति के पास कोई खर्च करने योग्य आय नहीं होती है।** यह उपभोग की न्यूनतम मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यक्ति या परिवार बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। **(इसलिए विकल्प बी) सही है)**
- प्रमुख कारक: स्वायत्त उपभोग विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है:
  - बुनियादी आवश्यकताएँ: जीवित रहने के लिए आवश्यक उपभोग, जैसे भोजन, कपड़ा और आश्रय।
  - निश्चित व्यय: किराया, उपयोगिताएँ और स्वास्थ्य देखभाल जैसे कुछ निश्चित व्यय।
  - व्यवहारिक पैटर्न: आय में परिवर्तन की परवाह किए बिना आवश्यक वस्तुओं पर आदतन खर्च करना।
- निहितार्थ: स्वायत्त उपभोग एक उपभोग स्तर स्थापित करता है जिसके नीचे कोई व्यक्ति या परिवार आय के अभाव में भी खर्च कम नहीं करेगा। यह आर्थिक मंदी की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिरता में योगदान देता है जब आय का स्तर गिरता है।
- चित्रमय प्रतिनिधित्व: उपभोग-आय ग्राफ में, स्वायत्त उपभोग स्तर को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जहां उपभोग अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष को रोकता है।
- आय से संबंध: आय शून्य होने पर स्वायत्त उपभोग प्रारंभिक उपभोग है। जैसे-जैसे प्रयोज्य आय बढ़ेगी, खपत स्वायत्त स्तर से अधिक हो जाएगी।
- व्यापक आर्थिक निहितार्थ: व्यापक अर्थशास्त्र के संदर्भ में, स्वायत्त उपभोग राष्ट्रीय आय और उत्पादन के संतुलन स्तर की गणना में एक भूमिका निभाता है। यह समग्र व्यय मॉडल का एक घटक है।

- समय के साथ परिवर्तन: सामाजिक मानदंडों, आर्थिक स्थितियों और आवश्यक व्यय पैटर्न को प्रभावित करने वाले नीतिगत परिवर्तनों में बदलाव के कारण स्वायत्त उपभोग बदल सकता है।
- बचत के साथ परस्पर क्रिया: स्वायत्त उपभोग बचत को प्रभावित करता है। यदि आय स्वायत्त स्तर से अधिक हो जाती है, तो बचत संभव है; यदि आय कम हो जाती है, तो व्यक्ति बचत में लगा सकते हैं या कर्ज ले सकते हैं।
- नीतिगत विचार: स्वायत्त उपभोग को समझने से नीति निर्माताओं को गरीबी को संबोधित करने, आय पुनर्वितरण और सुरक्षा जाल बनाने में मदद मिलती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्ति बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।
- संक्षेप में, स्वायत्त उपभोग व्यक्तियों द्वारा आय के बिना भी खर्च करने का न्यूनतम स्तर है, जो आर्थिक स्थिरता और नीति नियोजन में आवश्यक उपभोग की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

98.**c**

स्पष्टीकरण:

मितव्ययिता का विरोधाभास (Paradox of Thrift):

मितव्ययिता का विरोधाभास एक आर्थिक अवधारणा है जो व्यक्तिगत स्तर पर बढ़ी हुई बचत के प्रतिकूल परिणाम को उजागर करती है जिससे कुल मांग में कमी आती है और संभावित रूप से आर्थिक विकास में बाधा आती है। इसे महामंदी के दौरान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। **(अत: कथन 1 सही है)**

- बढ़ी हुई बचत: व्यक्ति और परिवार अनिश्चित समय या आर्थिक मंदी के दौरान भविष्य के लिए वित्तीय सहायता बनाने के लक्ष्य के साथ अपनी बचत बढ़ाने का निर्णय लेते हैं।
- समग्र मांग पर प्रभाव: जबकि बचत करना व्यक्तियों के लिए विवेकपूर्ण है, जब हर कोई सामूहिक रूप से अधिक बचत करता है, तो यह वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोक्ता खर्च को कम करता है।
- कुल मांग में कमी: कम उपभोक्ता खर्च के परिणामस्वरूप उत्पादों की मांग कम हो जाती है, जिससे व्यवसायों को उत्पादन और रोजगार में कटौती करनी पड़ती है, जिससे संभावित रूप से मंदी आ सकती है।
- गुणक प्रभाव: उपभोक्ता खर्च में कमी से गुणक प्रभाव होता है, जहां एक व्यक्ति के खर्च में कमी से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, जिससे आय और मांग में और कमी आती है।
- व्यवसायों की प्रतिक्रिया: कम मांग व्यवसायों को उत्पादन में कटौती करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे नौकरी छूट जाती है और श्रमिकों की आय में कमी आती है।
- बिगड़ता चक्र: जैसे-जैसे नौकरी छूटने के कारण आय घटती है, व्यक्ति खर्च करने के बजाय बचत करने के लिए और भी अधिक मजबूर महसूस कर सकते हैं, जिससे यह चक्र जारी रहता है।
- सरकारी हस्तक्षेप: विरोधाभास राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप की संभावित भूमिका पर प्रकाश डालता है, जैसे कि उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने और कुल मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खर्च में वृद्धि या कर में कटौती। **(अत: कथन 2 सही है)**
- अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक: जबकि व्यक्तिगत वित्तीय स्थिरता के लिए बचत महत्वपूर्ण है, बचत का विरोधाभास इस बात पर जोर देता है कि व्यक्तिगत स्तर पर जो फायदेमंद हो सकता है वह अर्थव्यवस्था-व्यापी स्तर पर अनपेक्षित नकारात्मक परिणामों का कारण बन सकता है।

- संतुलन अधिनियम: विरोधाभास व्यक्तिगत बचत और लंबे समय तक मंदी से बचने के लिए निरंतर आर्थिक गतिविधि की आवश्यकता के बीच संतुलन पर प्रकाश डालता है। **(अतः कथन 3 सही है)**
- कीनेसियन अर्थशास्त्र: यह अवधारणा कीनेसियन अर्थशास्त्र का केंद्र है, जो अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और समग्र मांग को बनाए रखने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की भूमिका पर जोर देती है।

99.**c**

स्पष्टीकरण:

सार्वजनिक वस्तुओं के लक्षण:

सार्वजनिक वस्तुएं अर्थशास्त्र में वस्तुओं की एक विशिष्ट श्रेणी होती हैं जिनमें विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो उन्हें निजी वस्तुओं से अलग करती हैं। ये विशेषताएँ सार्वजनिक वस्तुओं की प्रकृति और प्रावधान को परिभाषित करने में मदद करती हैं:

गैर-बहिष्करणीयता:

- सार्वजनिक वस्तुएं गैर-बहिष्कृत हैं, जिसका अर्थ है कि व्यक्तियों को उस वस्तु का उपयोग करने या उससे लाभ उठाने से बाहर नहीं किया जा सकता है, भले ही वे इसके लिए भुगतान न करें। **(अतः कथन 1 सही है)**
- एक बार वस्तु उपलब्ध करा दिए जाने के बाद व्यक्तियों को उसका लाभ लेने से रोकना चुनौतीपूर्ण होता है।

गैर-प्रतिद्वंद्वी उपभोग:

- सार्वजनिक वस्तुएँ गैर-प्रतिद्वंद्वी हैं, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु का उपयोग या उपभोग दूसरों के लिए उसकी उपलब्धता को कम नहीं करता है। **(अतः कथन 2 सही है)**
- एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु का उपभोग दूसरों द्वारा उसके उपभोग को प्रतिबंधित नहीं करता है।

सामूहिक उपभोग:

- सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग अलग-अलग व्यक्तियों के बजाय समग्र रूप से समाज द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है।
- निजी वस्तुओं के विपरीत, **उपभोग का श्रेय किसी विशिष्ट व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता** ; इससे सभी को एक साथ लाभ होता है। **(अतः कथन 4 सही है)**

बाजार की विफलता:

- सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं बाजार की विफलता का कारण बनती हैं, क्योंकि निजी बाजार मुफ्त राइडर (मुफ़्त सेवा प्राप्त करना) समस्या और उपभोक्ताओं से शुल्क लेने में असमर्थता के कारण इन वस्तुओं को कुशलतापूर्वक प्रदान नहीं कर सकते हैं।

सरकार की भूमिका:

KUMAR'S IAS

- सरकारें अक्सर सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाती हैं, क्योंकि वे समान वितरण सुनिश्चित करती हैं और मुफ्त राइडर की समस्या को दूर करती हैं।
- उदाहरणों में राष्ट्रीय रक्षा, सार्वजनिक पार्क, स्ट्रीट लाइटिंग और स्वच्छ हवा शामिल हैं।

इष्टतम प्रावधान:

- किसी सार्वजनिक वस्तु को प्रदान करने के लिए इष्टतम मात्रा का निर्धारण करना जटिल है, क्योंकि इसमें समाज के लिए लागत और लाभ का आकलन शामिल है।

अशुद्ध सार्वजनिक वस्तुएँ:

- कुछ वस्तुएं सार्वजनिक और निजी वस्तुओं (जैसे, सड़क, शिक्षा) दोनों की विशेषताओं को प्रदर्शित करती हैं।
- वे आंशिक रूप से गैर-बहिष्कृत या गैर-प्रतिद्वंद्वी हैं, जिससे उनके वर्गीकरण और प्रावधान के बारे में बहस छिड़ जाती है।

मूल्य निर्धारण में कठिनाई:

- सार्वजनिक वस्तुओं में गैर-बहिष्करण के कारण स्पष्ट बाजार कीमतों का अभाव होता है, जिससे उनका आर्थिक मूल्य निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। **(इसलिए कथन 3 गलत है)**

100.**d**

स्पष्टीकरण:

फिएट/ वैधानिक मुद्रा (Fiat Money):

फिएट मनी एक प्रकार की मुद्रा है जो सरकार द्वारा जारी की जाती है और **किसी देश के भीतर लेनदेन के लिए कानूनी निविदा के रूप में घोषित की जाती है** । इसका महत्व है क्योंकि सरकार इसे विनिमय के माध्यम के रूप में बनाए रखती है और ऋण, करों और वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए इसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। कमोडिटी मनी के विपरीत, जिसका आंतरिक मूल्य (जैसे सोना या चांदी) होता है, फिएट मनी का अंतर्निहित मूल्य नहीं होता है, लेकिन जारी करने वाली सरकार के अधिकार और विश्वास के आधार पर स्वीकार किया जाता है। **(अत: कथन 1 सही है)**

फिएट मनी की विशेषताएं:

- कानूनी निविदा: सरकारें लेनदेन के लिए फिएट मनी को एकमात्र आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्थापित करती हैं और ऋणों के निपटान के लिए इसे स्वीकार्य घोषित करती हैं।
- आंतरिक मूल्य का अभाव: कमोडिटी मनी के विपरीत, फ़िएट मनी का कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं होता है। इसका मूल्य उस भौतिक पदार्थ से नहीं, जिससे यह बना है, बल्कि सरकार के अधिकार से प्राप्त होता है। **(अत: कथन 2 सही है)**
- सरकारी नियंत्रण: फ़िएट मनी जारी करने, आपूर्ति और प्रबंधन पर सरकारों का पूर्ण नियंत्रण होता है। वे आवश्यकतानुसार इसे प्रिंट, टकसाल या डिजिटाइज़ कर सकते हैं। **(अत: कथन 3 सही है)**
- स्वीकृति और विश्वास: फिएट मनी का मूल्य लोगों के सरकार में विश्वास और समय के साथ इसके मूल्य को बनाए रखने की क्षमता में निहित है।

- असीमित आपूर्ति: सरकारों के पास फ़िएट मनी की अतिरिक्त इकाइयाँ बनाने की शक्ति है। हालाँकि, अत्यधिक छपाई से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो सकती है।
- लचीला प्रबंधन: सरकारें मुद्रास्फीति, अपस्फीति या मंदी जैसी आर्थिक स्थितियों को प्रबंधित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति को समायोजित कर सकती हैं।
- वैश्विक मानक: अधिकांश विश्व अर्थव्यवस्थाएँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विनिमय और निवेश के लिए मानक मुद्रा के रूप में फिएट मनी का उपयोग करती हैं। **(अत: कथन 4 सही है)**
- इलेक्ट्रॉनिक रूप: आधुनिक फिएट मनी अक्सर इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद होती है, क्योंकि डिजिटल लेनदेन अधिक आम हो गया है।

KUMAR'S IAS